सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

20 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

सप्तदश विधान सभा वृहस्पतिवार, तिथि 20 मार्च, 2025 ई०

चतुर्दश सत्र 29 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न

अल्पसूचित प्रश्न सं0–''क''–2 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आरा)

अध्यक्ष : अमरेन्द्र जी, पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, उत्तर नहीं मिला है । उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आपके यहां गया है ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, इसका जवाब कृषि मंत्री देंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 आशिंक स्वीकारात्मक है । भूगर्भीय जल में यदि आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो तो इस जल से सिंचाई किये जाने पर आर्सेनिक फसलों और उसके पैदावर तक पहुंच सकता है । विभिन्न फसलों में आर्सेनिक की अनुमान्य मात्रा की सीमा इस प्रकार है पत्ते वाली सब्जी, मेथी, बंदागोभी 0.1 ग्राम प्रति किलोग्राम, जड़ वाली सब्जी में 0.3 अन्य फसल में 1.0 ।

खंड–2 इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत जानकारी ली जा रही है ।

खंड–3 इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया जाएगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, इस जवाब से काम नहीं चलेगा । बहुत गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से ही तो जवाब दिया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, नहीं दिये हैं । जवाब है कोई ? इससे काम नहीं चलेगा ।

अध्यक्ष : आपने प्वाइंट आउट किया है तो बात करेंगे संबंधित विभाग से । आपका पूरक क्या है ? पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, हमारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही था कि ये जो मानक है, रिसर्च के बाद वह मानक आया है और धान में, गेहूँ में, आलू में और इस प्रकार से जो कृषि फसल है उसमें, सिंचाई के पानी से उसमें इतना आर्सेनिक पाया गया है जिससे कैंसर, स्कीन कैंसर यह सब हो रहा है, यह बहुत गंभीर मामला है और हमारे यहां, हम भोजपुर जिले की बात करते हैं गंगा के इलाके में पूरा का पूरा इलाका आर्सेनिक पानी से प्रदूषित है, पीने का पानी पूरा, पानी ऊपर आता है तो काला हो जाता है, हाथ धोते हैं तो हाथ काला हो जाता है महोदय, इस प्रकार से ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं इन्होंने यह नहीं कहा ? आर्सेनिक, सिंचाई का पानी, पीने का पानी में क्या फुलप्रूफ कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य सीनियर भी हैं, अभिभावक भी हैं, इनकी चिंता जायज है और ये बिहार के भविष्य के लिए जो चिंता व्यक्त किये हैं विभाग गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कह चुकी है और ऐसे भी इस संदर्भ में जब यह विषय संज्ञान में आया है तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लघु सिंचाई विभाग के साथ विस्तृत विमर्श होगा और उसके रिजल्ट के बाद आपकी चिंता के समाधान का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : वाह ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : ठीक है महोदय ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–''क''–200 (श्री अजीत शर्मा, भागलपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक ।

यह कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है । रेलवे द्वारा दिनांक–06.06.2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है मगर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल भागलपुर के पत्रांक–627 (अनु०) दिनांक–10.08.2024 के द्वारा रेलवे, कोलकाता को रेलवे क्षेत्र में कार्य करने हेतु Structural Drawing अनुमोदन हेतु भेजा गया है, जो अद्यतन अप्राप्त है । रेल क्षेत्र आवागमन के बाहरी क्षेत्र में पूर्ण आरेखण में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रेलवे क्षेत्र के Structural Drawing का रेलवे से अनुमोदन हेतु लगातार विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है । अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बताया है कि दिनांक– 06.06. 2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र रेलवे द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि यह काम कब प्रारंभ हुआ, मेरा पहला पूरक है महोदय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इनके प्रश्न के उत्तर में हमने अस्वीकारात्मक लिखा है और यह कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है । रेलवे द्वारा दिनांक–06.06.2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है मगर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल भागलपुर के पत्रांक–627 (अनु०) दिनांक 10.08.2024 के द्वारा रेलवे, कोलकाता को रेलवे क्षेत्र में कार्य करने हेतु Structural Drawing अनुमोदन हेतु भेजा गया है, जो अद्यतन अप्राप्त है । रेल क्षेत्र आवागमन के बाहरी क्षेत्र में पूर्ण आरेखण में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रेलवे क्षेत्र के Structural Drawing का रेलवे से अनुमोदन हेतु लगातार विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अजीत शर्मा : उत्तर आया हुआ है, हम पढ़े हुए हैं । हमने पूछा आपसे कि कब काम प्रारंभ हुआ वह नहीं बताए ? दूसरा पूरक है, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि अनुमोदन हेतु लगातार विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि कार्य प्रमंडल भागलपुर द्वारा कब–कब रेलवे से पत्राचार किया गया ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, कार्य प्रमंडल के द्वारा डिटेल मंगाकर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मेरा तीसरा पूरक है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 7 माह से अधिक बीत गया है इस दौरान क्या पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक अथवा कृषि विभाग के सचिव की कोई बैठक रेलवे के अधिकारियों के साथ इस बिंदु पर हुई और हुई तो कब कृपया तिथि बता दें ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमने कहा, डिटेल में इस विभाग की पूरी जानकारी प्राप्त करके क्योंकि यह पुल निर्माण निगम से जुड़ा हुआ विषय है और हमारे विभाग से जुड़ा हुआ विषय है दोनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उनको उपलब्ध कराया जायेगा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मुद्दा है इसको स्थगित किया जाय, जवाब तो इन्होंने एक भी नहीं दिया, इसको स्थगित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप जानते हैं कि जब आर0ओ0बी0 बनता है या अंडरपास बनता है तो रेलवे की सहमति से ही बन सकता है तो इसके लिए विभाग ने प्रोसेस किया है जानकारी आपको दिया मंत्री जी ने और यह भी कहा कि चूंकि विभाग दूसरा था तो डिटेल जानकारी, जब तिथियों के बारे में पूछा आपने तो उन्होंने कहा कि आपको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, उपलब्ध करा देंगे लेकिन जब सदन में सवाल आया है तो सदन में जवाब होना चाहिए ।

अध्यक्ष : हाँ तो करा देंगे । जल्दी करा देंगे ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, प्रश्न ट्रांसफर हुआ फिर भी जवाब नहीं मिला ।

अध्यक्ष : श्री बिजय सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–''ख''–305 (श्री बिजय सिंह, बरारी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । समाहर्त्ता, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बरारी प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवार फुलवरिया चौक से काढ़ागोला घाट तक जाने वाली सड़क के मड़वा से काढ़ागोला घाट तक सड़क के दोनों किनारे बसे हुए पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक–16.10.2024 को कुल–4678 भूमिहीन परिवारों को भूमि अर्जित /अधिग्रहित कर बंदोबस्त जमीन का पर्चा वितरित कर दी गयी है ।

फुलवरिया चौक से काढ़ागोला घाट तक जाने वाली सड़क के मड़वा से काढ़ागोला घाट तक सड़क के दोनों ओर बसे हुए शेष लोगों के मामले का जाँच कर आवासीय भूमि विहीन पाये जाने की स्थिति में केवल सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को अभियान बसेरा–2 के अन्तर्गत तीन माह के अन्दर बंदोबस्ती पर्चा निर्गत कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, बिजय जी ।

श्री बिजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बरारी प्रखंड में गंगा नदी कटाव से काढ़ागोला घाट से फुलवरिया तक और मड़वा से लेकर काढ़ागोला घाट तक कटाव पीड़ित लोग बसे हुए हैं और बरारी अंचल में सरकार के द्वारा सीज की गई जमीन और सरकारी जमीन काफी मात्रा में है जिस पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा करके खेती की जा रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री बिजय सिंह : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि अपने स्तर से इसकी जांच करा लें और जांच कराकर सड़क के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनको बसाकर जमीन का बासगीत पर्चा दिया जाय । मेरा दूसरा पूरक है, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि...

अध्यक्ष : फिर आग्रह कर रहे हैं, पूरक पूछ रहे हैं कि आग्रह कर रहे हैं ?

श्री बिजय सिंह : महोदय, एक समय–सीमा तय किया जाय और जमीन को कब्जा मुक्त कराकर भूमिहीनों को बसाया जाय ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड में जो फुलवरिया चौक से काढ़ागोला घाट जाने वाली सड़क में, मड़वा से काढ़ागोला घाट तक जो पीड़ित परिवार हैं उनको 16.10.2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर–कमलों के द्वारा 4678 परिवारों को भूमि अर्जित/अधिग्रहित कर बंदोबस्त जमीन का पर्चा वितरित कर दिया गया है और शेष जो है उसका सर्वेक्षण हो रहा है, बाकी जो शेष परिवार बचे हुए हैं उसके सर्वे हेतु टीम भी बन गई है, उसका सर्वे हो रहा है और इसमें सुयोग्य श्रेणी के जो परिवार होंगे, अभियान बसेरा–2 के अंतर्गत 3 माह के अंदर, मैंने समय–सीमा भी उत्तर में दिया है, बंदोबस्ती पर्चा निर्गत कर दिया जायेगा, सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को दिया जायेगा, यह उत्तर में भी मैंने लिखा है ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार सिंह ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब हो गया, अब क्या है ?

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रधानमंत्री आवास सर्वे का काम जोरों–शोरों से चल रहा है, यथाशीघ्र हो जाता तो...

अध्यक्ष : तीन महीना बता दिया उन्होंने ।

श्री बिजय सिंह : धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–''ग''–430 (श्री अजय कुमार सिंह, जमालपुर, मुंगेर)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान ऋषि कुंड में पर्यटन विभाग से...

अध्यक्ष : जवाब तो सुन लीजिए । अजय बाबू, जब आप जवाब नहीं पढ़े हैं तो जवाब सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो ऑनलाइन दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : नहीं पढ़ पाए होंगे ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : ठीक है माननीय सदस्य नहीं पढ़ पाये होंगे यह मैं मान सकता हूं । जवाब देता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्त्ता, मुंगेर के प्रतिवेदनानुसार प्रखण्ड हवेली खड़गपुर के ऋषि कुण्ड में प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में राजगीर की तरह मेला का आयोजन होता है, जिससे सरकार को राजस्व कर प्राप्ति होती है । उक्त मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार में सम्मिलित करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव की मांग समाहर्त्ता, मुंगेर के पत्रांक–576/10, दिनांक–07.03.2025 के द्वारा अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर से की गई है। समाहर्त्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त से तत्संबंधी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के उपरांत उक्त मेला को मेला प्राधिकार की अनुशंसा के आधार पर बिहार राज्य मेला प्राधिकार में सम्मिलित करने तथा इसे राजकीय मेला घोषित करने की कार्रवाई सरकार स्तर पर की जा सकेगी ।

टर्न–2 / आजाद / 20.03.2025

अध्यक्ष : यह तो हो गया, जवाब आपका पोजेटिव है । आप जो कह रहे हैं, वही सरकार कह रही है ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, इसपर त्वरित कार्रवाई करायी जाय और इसको ....

अध्यक्ष : इसपर त्वरित कार्रवाई करायी जाय, ठीक है । माननीय सदस्य श्री राम विलास कामत ।

तारांकित प्रश्न सं0–1655 (श्री रामविलास कामत,निर्मली)

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : (क) आंशिक स्वीकारात्मक ।

नगर पंचायत, पिपरा नवगठित नगर निकाय है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पिपरा के पत्रांक–29 दिनांक–08.02.2025 द्वारा अंचलाधिकारी, पिपरा को भूमि हेतु अधियाचना प्रेषित किया गया है एवं भूमि की उपलब्धता हेतु समन्वय किया जा रहा है । अंचलाधिकारी द्वारा अभी भूमि हस्तांतरित नहीं किया गया है । इसी क्रम में विभागीय पत्रांक–3134 दिनांक 17.03.2025 द्वारा सरकारी भूमि की विवरणी अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, सुपौल से अनुरोध किया गया है ।

भूमि उपलब्ध होने एवं बोर्ड की बैठक से प्रस्ताव पारित होने तथा विभाग को अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए रामविलास जी ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, जवाब मिला हुआ है और जवाब में आया है कि भूमि उपलब्ध होने एवं बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव पारित होने तथा विभाग को अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त अद्यतन कार्रवाई की जायेगी लेकिन अध्यक्ष महोदय, जवाब के शुरूआत में ही बताया गया है कि नगर पंचायत, पिपरा नवगठित नगर निकाय है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पिपरा के पत्रांक–29, दिनांक 08.02.2025 द्वारा अंचलाधिकारी, पिपरा को भूमि हेतु अधियाचना प्रेषित किया गया है । महोदय, कहने का मतलब कि जब बोर्ड के बैठक में निर्णय लिया गया और प्रस्ताव पारित हुआ तभी तो सी0ओ0 को पत्र लिखा गया है और जमीन की

उपलब्धता भी है और बोर्ड से पारित भी है तो कब तक माननीय मंत्री जी पार्क बनवाने का काम शुरू करायेंगे, यह मैं जानना चाहता हूॅ ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी निर्माण कार्य जमीन की उपलब्धता के बाद ही हो सकती है । मैं माननीय सदस्य को एकदम आश्वस्त करता हूॅ कि जैसे ही सी0ओ0 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा, जमीन उपलब्ध हो जायेगा तो तीन महीना के अन्दर इसकी शुरूआत कर दी जायेगी, यथाशीघ्र इसको बनाकर तैयार कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : हो गया आपका ।

श्री रामविलास कामत : धन्यवाद माननीय मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0–1656 (श्री विद्यासागर केशरी, फारबिसगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : 1– आंशिक स्वीकाात्मक । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् जोगबनी के पत्रांक–344, दिनांक–11.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उत्क्रमित नगर परिषद जोगबनी के 28 वार्डों में से वार्ड सं0–01 से 19 तक के घरों में नल का जल की आपूर्ति की जा रही है तथा शेष छूटे हुए घरों में हर घर नल का जल कनेक्शन देने हेतु निविदा दैनिक अखबारों में प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त 20 से 28 वार्डों में पेयजल की आपूर्ति लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा की जा रही है ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् फारबिसगंज के पत्रांक–497, दिनांक–12.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, फारबिसगंज के कुल 25 वार्डो में से कुल 24 वार्डो के घरों में नल का जल की आपूर्ति की जा रही है तथा वार्ड संख्या 17 के बिछाये गये पाईप कट जाने के कारण आपूर्ति बाधित है जिसे एक माह के अंदर मरम्मती कराकर जल की आपूर्ति की जायेगी।

2– अस्वीकारात्मक । नगर परिषद् जोगबनी एवं फारबिसगंज में नियमित रूप से नल जल का मेंटेनेंस का कार्य कराया जा रहा है तथा कार्यालय स्तर से वार्डवार पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारी/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है।

3– नगर परिषद् जोगबनी एवं फारबिसगंज में नल का जल सुचारू रूप चालू है तथा उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है एवं नगर परिषद, जोगबनी द्वारा छूटे हुए घरों में नल का जल का कनेक्शन देने हेतु निविदा किया गया है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए विद्यासागर केशरी जी ।

श्री विद्यासागर केशरी : जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जवाब में बताया गया है कि जोगबनी नगर परिषद् में 01 से 19 वार्डों तक जलापूर्ति रेगुलर हो रही है और शेष जो है, 20 से 28 वार्डों में जलापूर्ति जो है, वह पी0एच0ई0डी0 के द्वारा की जाती है । जबकि यह बिल्कुल सरासर गलत है और फारबिसगंज नगर परिषद् का भी जो है, उसी प्रकार से आया है कि सारे वार्डों में, 25 वार्डों में जलापूर्त्ति नियमित रूप से हो रही है और सिर्फ एक वार्ड जो 17 में है, कटे रहने के चलते वहां पर सप्लाई नहीं हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो जोगबनी नगर परिषद् है या फारबिसगंज नगर परिषद् है, इन सभी वार्डों तक जलापूर्त्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जॉच सुनिश्चित कराने का विचार रखते हैं चूँकि यह महत्वकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का है .....

अध्यक्ष : बैठ जाईए, बोलने दीजिए माननीय मंत्री जी को ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य ने इस जवाब को ठीक से पढ़ा नहीं है । स्पष्ट रूप से इसमें दिया हुआ है ....

अध्यक्ष : जवाब को नहीं पढ़ा है ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : जवाब नहीं पढ़ा है, इसमें स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है कि जोगबनी के 28 वार्ड में से 01 से 19 तक जो नल का जल है, उसकी आपूर्त्ति की जा रही है पूर्व से और इसमें जो नये बसावट और नये घर जो जुड़े हैं, शेष घर के लिए निविदा निकाला गया है, पूरा घर आच्छादित नहीं है । हम तो स्पष्ट इसमें लिख रहे हैं कि 01 से 19 तक जलापूर्त्ति की जा रही है और जो छूटा हुआ घर है, उसके लिए निविदा अखबार में निकाला जा चुका है और निविदा की प्रक्रिया पूरा होते ही उस घर को जोड़ने का काम करेंगे । जहां तक फारबिसगंज का सवाल है, फारबिसगंज पहले से सुचारू रूप से क्रियान्वित हमारा नगर इकाई है । वहां 01 से 25 में 24 वार्ड में जलापूर्त्ति हो रही है, 17 वार्ड के अन्दर कुछ सड़क निर्माण का काम हुआ तो पाईप लाईन कटने के कारण यहां पर डिस्टर्बेंस है, इसको भी हमने निर्देश दिया है कि तुरंत पूरा कराकर के जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, उसका समाधान हम तुरंत करने में सक्षम होंगे ।

अध्यक्ष : अब तो हो गया ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक पूछना चाहता हूँ, पहला पूरक में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी जगहों पर जलापूर्त्ति हो रही है, लेकिन यह बात बिल्कुल निराधार है, जो भी इनको उत्तर दिया गया है पदाधिकारी के द्वारा वह गलत है.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए न ।

श्री विद्या सागर केशरी : दूसरी बात है कि मेनटेनेन्स जो है रेगुलर, जहां भी जलापूत्ति हो रही है, सारे वार्डों में जो है, हर साल मेनटेनेन्स किया जाता है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किन–किन वित्तीय वर्षों में कितने–कितने पैसे मेनटेनेन्स पर खर्च किये गये ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल माननीय सदस्य के सवाल का पूरक का हिस्सा नहीं है । अगर इस प्रकार की कोई प्रश्न इनका है तो ये लिखित रूप से देंगे, विभाग इसकी जानकारी देगी लेकिन इन्होंने फिर वही पहला प्रश्न को दोहराया, मैंने स्पष्ट रूप से पहले प्रश्न में कबूला है कि 01 से 19 तक जलापूर्त्ति हो रही है, जो छूटा हुआ बसावट है, जो छूटा हुआ घर है, उसके लिए हमने निविदा निकाला है, फिर ये कहा सवाल उठ रहा है कि सभी घर को दे रहे हैं, छूटे हुए घर के लिए निविदा निकाला है हमने ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इन्होंने सवाल किया है कि मेनटेनेन्स में कोई कमी हो रही है तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि एक बार उसकी जॉच करा लीजिए न, कमी है तो उसको पूरा करा दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, आपके आदेश का एकदम पालन होगा, हम इसकी जॉच करा देते हैं, लेकिन सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि मेनटेनेन्स के लिए भी पर्यवेक्षक बहाल हैं जैसे ही सूचना मिलती है, विभाग समय–समय पर मेनटेनेन्स का भी काम करता है ।

अध्यक्ष : चेक करा दीजिए, ठीक है, अब बैठ जाईए केशरी जी ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, जॉच करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : हो गया केशरी जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1657 (श्री भाई वीरेन्द्र, मनेर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : समाहर्त्ता, पटना से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि– परियोजना–दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरीडोर निर्माण अन्तर्गत बिहटा अंचल के 13 मौजा यथा नेउरा, थाना नं0–104, अदलीपुर, थाना नं0–79, गोढ़ना, थाना नं0–80, पैनाल, थाना नं0–70, कन्हौली, थाना नं0–69, वाजीदपुर, थाना नं0–85,

परिखोत्तिमपुर पैनाठी, थाना नं0–68, विशुनपुरा, थाना नं0–66, विशम्भरपुर, थाना नं0–57, पतसा, थाना नं0–59, श्रीरामपुर, थाना नं0–58, महादेवपुर फुलाड़ी, थाना नं0–53 एवं खेदलपुरा, थाना नं0–50 में भूमि का अधिग्रहण किया गया है । भूमि का अधिग्रहण एन0एच0 एक्ट 1956 के तहत् किया गया है । विभागीय पत्रांक–450/रा0, दिनांक–12.04.2017 एवं संशोधित पत्रांक–1287/रा0, दिनांक–03.10.2017 के आलोक में छः सदस्यीय प्रकृति निर्धारण समिति का गठन किया गया । दिनांक– 25.06.2020 को स्थल निरीक्षणोपरान्त प्रकृति निर्धारण समिति के द्वारा मौजावार प्रकृति निर्धारित किया गया । तदोपरान्त नियमानुसार आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0आर0 एक्ट–2013 की धारा–26 से 30 में वर्णित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को प्रभावी एम0वी0आर0 के आधार पर मुआवजा भुगतान हेतु दर निर्धारित करते हुए प्राक्कलन तैयार किया गया ।

अभी तक उक्त परियोजनान्तर्गत 1364 पंचाट में 953 हितवद्ध रैयतों को मो0–143.49 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान किया जा चुका है तथा लगातार मुआवजा भुगतान जारी है ।

परियोजना–बिहटा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इनक्लेव निर्माण हेतु बिहटा अंचल में दो भाग में मौजा–कुतलुपुर, थाना नं0–56 एवं मौजा– विशम्भरपुर, थाना नं0–57 अन्तर्गत कुल–134.8525 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है । नियमानुसार छः सदस्यीय प्रकृति निर्धारण समिति के द्वारा निर्धारित की गयी प्रकृति के आलोक में आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0आर0 एक्ट–2013 की धारा–26 से 30 में वर्णित प्रावधान के तहत् अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को प्रभावी एम0वी0आर0 के आधार पर मुआवजा भुगतान हेतु दर का निर्धारण करते हुए प्राक्कलन तैयार किया गया ।

अभी तक कुल 538 पंचाट में 1160 हितवद्ध रैयतों को कुल मो0–242. 46 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है तथा लगातार मुआवजा भुगतान जारी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है । जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, दो तरह की भूमि है । एक है पंचायत का और दूसरा है नगर परिषद् का तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्णित पंचायत और नगर पंचायत, नगर परिषद् का जो सर्किल रेट है, वह कितना सर्किल रेट है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ?

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह प्रश्न है कि परियोजना दानापुर–बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में, इसमें दो अधिग्रहण का मामला है, एक बिहटा–सैन्य हवाईअड्डा पर सिविल इनक्लेव का निर्माण, इसमें इन्होंने कहा है, पूछा है कि भूस्वामियों को अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा की राशि नहीं दी जा रही है । मैंने पूरा विस्तृत जवाब दिया है कि कितने पंचायत में, कितने भूस्वामियों को राशि दी गई है और जो राशि देने की नियम है कि भू–अर्जन अधिनियम–2013 के प्रावधानानुसार दर निर्धारण की प्रक्रिया है और उसमें जो है परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि का प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन तिथि को लागू एम0वी0आर0 अथवा प्रारंभिक अधिसचूना की तारीख से तीन वर्षों में की गयी समरूप किस्म की भूमि के निबंधित दस्तावेज में निहित बिक्रय मूल्यों में से अधिकतम 50 प्रतिशत की औसतन गणना करने पर, दोनों में से जो अधिक है, उसके अनुसार दी जाती है और यही नियम है और उसके बाद अगर किन्हीं को आपत्ति है तो उसके ऊपर व्यवस्था है कि वे आपत्ति दायर करेंगे तो फिर आपत्ति की सुनवाई करके उनका भुगतान किया जायेगा, जो भी निर्देश होगा तो यही व्यवस्था है, वह मैंने जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, उनको जवाब दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय, उचित दर नहीं दिया जा रहा है तो जो एम0वी0आर0 रेट और उसमें जो ....

अध्यक्ष : उसने पूछा है कि सर्किल रेट क्या है ?

श्री संजय सरावगी, मंत्री : महोदय, सर्किल रेट के अनुसार ही दिया जा रहा है । सर्किल रेट पर इन्होंने आपत्ति नहीं की है । इन्होंने कहा है अध्यक्ष महोदय, सर्किल रेट जो है, सर्किल रेट या उसमें जो ज्यादा हो, उस दोनों में से जो ज्यादा हो, वह दिया जा रहा है तो सर्किल रेट क्या है, मैं उनको भेजवा दूँगा । कल ही भेजवा दूँगा, वहां पर सर्किल रेट क्या है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था, वे न तो सर्किल रेट बता रहे हैं, न भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है पंचायत स्तर का, वह आवासीय भूमि है और नगर परिषद् का भी जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, वह भी आवासीय है तो मैं आपके माध्यम से केवल माननीय मंत्री जी से, सरकार से जानना चाहता हूँ कि उन दोनों का सर्किल रेट क्या है ? वह हमको बतावें, सर्किल रेट बतावें न ।

टर्न–3 / पुलकित / 20.03.2025

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने कहा है कि जो सर्किल रेट घोषित है उसमें दो प्रकार के नियम बने हुए हैं जैसा उन्होंने कहा है । एक तो सर्किल रेट के हिसाब से और दूसरा जो तीन साल में रजिस्ट्री हुई है उनका एवरेज निकालकर के दोनों में जो मैक्सिमम है वह रेट किसानों को देने का नियम है । अगर आपको यह लगता है कि हां, इस नियम का पालन कहीं नहीं हुआ है तो जरूर इस बात को हाईलाईट करना चाहिए ताकि मंत्री जी इसकी जांच करा लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, इसीलिए तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि सर्किल रेट बतावें सदन को कि सर्किल रेट दोनों का क्या है ? तब न हम पूछेंगे ।

अध्यक्ष : मंत्री जी आपको भेज देंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, भेजना नहीं है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि भेज देंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, यह सदन की प्रोपर्टी है । मंत्री जी बतावें दोनों जगह का जो सर्किल रेट है, वह सरकार बतावें । माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां काफी किसानों की जमीन जा रही है और अभी तक जो भूमि ली गयी है उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सर्किल रेट हमको बता दें ताकि जो सर्किल रेट से उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह हम जांच करायेंगे । पहले मंत्री जी सर्किल रेट बता दें ।

अध्यक्ष : मंत्री जी सर्किल रेट आपको भेज देंगे । आप जांच करा लीजिएगा, अगर कुछ होगा तो फिर बताइयेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, यह सदन की प्रोपर्टी है । आपके संरक्षण की आवश्यकता है । यह किसानों का मामला है, हुजूर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वही तो मैं कह रहा हूँ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, यह किसानों का मामला है और सर्किल रेट अगर मंत्री जी नहीं बताते हैं तो इससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला लगता है ।

अध्यक्ष : नहीं, दाल में कुछ काला नहीं लगता । उन्होंने पूरे नियम का हवाला दिया है।

श्री भाई वीरेन्द्र : जब सर्किल रेट नहीं बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है और किसानों के साथ, जो भूमि किसान दे रहे हैं, उसके साथ अन्याय होने की आशंका है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सर्किल रेट सरकार दोनों का हमको बता दें ।

अध्यक्ष : रेट बता देंगे, आपको जानकारी दे देंगे ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न पढ़िये । प्रश्न को माननीय सदस्य पढ़ें, इसमें इन्होंने यह नहीं कहा है कि सर्किल रेट के अनुसार नहीं मिल रहा है । माननीय सदस्य प्रश्न पूछे हैं कि उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा । महोदय, उचित मुआवजा दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : वही न हुआ ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : महोदय, उचित मुआवजा दिया जा रहा है और किनको कितना मुआवजा दिया गया, उसकी भी मेरे पास सूची है । कितने गृहस्वामियों का आवासीय का दिया गया, किसको प्रगतिशील आवास का दिया गया । सारी सूची मेरे पास है । अगर माननीय सदस्य सर्किल रेट जानना चाहते हैं, अलग–अलग क्षेत्रों के अलग–अलग सर्किल रेट हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मैंने कहा कि पंचायत का और नगर परिषद का मामला है और अलग–अलग दोनों का सर्किल रेट होगा ।

अध्यक्ष : एक मिनट भाई वीरेन्द्र जी, पहले मंत्री जी की बात सुन लीजिए ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सर्किल रेट तो पब्लिक डोमेन में है । कहीं कोई यह छिपा हुआ मामला ही नहीं है ।

अध्यक्ष : बिल्कुल ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : माननीय सदस्य वरीय सदस्य हैं, सर्किल रेट तो पब्लिक डोमेन में है । यह कोई छिपाने की चीज भी नहीं है । वह तो माननीय सदस्य खुद देख सकते हैं कि सर्किल रेट क्या है ? उन्होंने सर्किल रेट पर आपत्ति नहीं की थी इसलिए मैंने सर्किल रेट नहीं बताया । कितने को किस रेट से दिया जा रहा

है वह भी सूची मेरे पास है । इसलिए कहीं कोई मामला ही नहीं है । सर्किल रेट तो पब्लिक डोमेन में है । माननीय सदस्य अभी खुद बाहर जाकर सर्किल रेट देख सकते हैं । मैं इनको सर्किल रेट भिजवा भी दूंगा कि सर्किल रेट क्या है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जब आसन पर आप बैठे रहते हैं तो सबको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री कौन हैं ? लेकिन आप पुकारते हैं न माननीय मुख्यमंत्री, तब वे बोलते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार बतावें कि सर्किल रेट दोनों का क्या है ? यह सरकार बतावें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए, सर्किल रेट पता करके मुझे बता दीजिए, मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा । माननीय सदस्य, अब बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अब बैठिये, हो गया ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1658 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, जहानाबाद)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक ।

2– स्वीकारात्मक । भारत सरकार के पत्रांक–2–1/2023–पी0डी0.II(E.383244), दिनांक–29.08.2024 के आलोक में बिहार में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में हस्तलिखित रजिस्टरों को हटाकर पूर्णतः ऑनलाईन प्लेटफार्म से संचालन कराने की प्रक्रिया विचाराधीन है ।

3– उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जवाब आया है और हमने सवाल भी किया था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं । बैठिये, सुदय जी का प्रश्न हो रहा है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, भारत सरकार का मतलब हवाला देकर के ...

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाह रहे हैं कि जांच कब तक करवा लेंगे?

अध्यक्ष : वह तो बनाकर रखे हुए हैं ।

सुदय जी, पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, ऑनलाईन प्लेटफॉर्म से जन वितरण प्रणाली की दुकानों का मतलब संचालन करने की व्यवस्था पर मेरा सवाल था । सरकार कब तक उसको लागू करना चाहती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये, अब आगे बढ़ गये हैं । जब प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं ? बैठिये ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का जो पत्र आया है मैंने उसके विषय में कहा है कि हमलोग इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही इसको लागू करेंगे ।

अध्यक्ष : जल्द ही लागू करेंगे ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, एक पूरक है । जैसे ये जो ऑनलाईन प्लेटफॉर्मस से व्यवस्था करने की बात कही गयी थी । इसके चलते जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मतलब एम0ओ0 और निचले जितने कर्मचारी हैं उसके द्वारा शोषण–दोहन किया जा रहा है । इसलिए हुआ था कि इसको जल्द से जल्द सरकार लागू करें ताकि दुकानदार अपने–आप को सुरक्षित महसूस करें ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य का सुझाव है कि जल्द से जल्द लागू करिये ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : जी, महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जल्द से जल्द होगा । बैठिये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1659 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, शेरघाटी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । गया जिलान्तर्गत प्रखंड–शेरघाटी के पंचायत–बेला के वार्ड सं0–11 में तिवारीचक टोला अवस्थित है, जिसमें लगभग 92 अदद घर है, जिसमें सभी घरों में गृह जल संयोजन किया गया है एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है । दो टोला यथा पश्चिमी खडार एवं जगदीशपुर, चिलिम पंचायत के वार्ड सं0–17 में अवस्थित है एवं छूटा हुआ टोला में शामिल किया गया है । जो निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में है ।

अध्यक्ष : मंजु जी, पूरक पूछिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, मैं सरकार के....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : एक मिनट मेरी बात सुनिये । अध्यक्ष जी, एक बात और हम कह देते हैं कि ये लोग मोबाईल पर विषय लेकर के बात कर रहे हैं । आपके द्वारा मोबाईल सदन में प्रतिबंधित था, रोका हुआ था और सब मोबाईल लेकर के बोल रहे हैं । यह कोई बात है ?

अध्यक्ष जी, आप प्रतिबंध करिये कि कोई भी सदन में मोबाईल लेकर नहीं आये । मोबाईल को प्रतिबंधित कीजिए और पहले से ही सदन में मोबाईल पर प्रतिबंध किया हुआ है । यह ऐसा क्यों चल रहा है ? पांच–छह साल से यह व्यवस्था शुरू हुई और इसके बाद तो दस साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगी । मोबाईल तो बेकार है ही । सबलोग मोबाईल को ही देखेगा तो बेकार हो जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मोबाईल में देखने के अलावा आप अलग तरह से बोलिये ।

(व्यवधान)

वह फालतू बात है । पहले तो हम खूब देखते थे लेकिन जब हम 2019 में जान गये कि इससे गड़बड़ होने वाला है और आगे होगा । 2020 से खूब लोग मोबाईल लिया है और हम तो मोबाईल छोड़ दिये । समझ गये या नहीं ? ऐसे ही मोबाईल देखते हैं ? क्यों मोबाईल लेकर रखे हुए हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मोबाईल सदन में प्रतिबंधित है । आप भूलिये मत । अध्यक्ष जी, आप याद कराइये कि कोई मोबाईल लेकर के सदन में आयेगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा । अध्यक्ष जी, इसे पूरा करिये, यह काम करिये । जल्दी करिये, जल्दी करिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अपनी तरफ से आप बोलिये । ये मोबाईल लेकर के क्या बोलते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, बैठ जाइये । मंजु जी खड़ी हैं, उनको प्रश्न करने दीजिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल, पूरक पूछिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, मैं सरकार के जवाब से असंतुष्ट हूँ ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, मेरा पहला पूरक है कि प्रखण्ड शेरघाटी के ग्राम पंचायत बेला के वार्ड नं0–11 बहेरी टोला तिवारीचक में लगभग 4 वर्ष पूर्व नल–जल योजना को चालू किया गया था, जिसमें 270 घरों में पानी जा सका है । दो ही चार घर में पानी जा सका है । इसकी जांच करा ली जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या का कहना है कि घर छूटा हुआ है, जांच कर ली जाए ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, विस्तार से जवाब दिया हुआ है । जिन घरों की चिंता माननीय सदस्या कर रही हैं वहां हमलोगों ने निविदा करा दी है । इसी महीने में निविदा की प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी और अगले महीने से वहां पर काम शुरू हो जाएगा ।

अध्यक्ष : अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, हमारा दूसरा पूरक है कि चिलिम पंचायत के वार्ड नं0–17 और दो टोला में नल जल योजना कब चालू की जाएगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : इसकी समय अवधि बता दी जाए ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैंने बता दिया है और माननीय सदस्या बता रही हैं कि लगभग 270 घरों में पानी नहीं जा रहा है । हमने जवाब दिया है कि 92 घरों में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है । जो छूटे हुए टोले हैं वहां हमलोगों निविदा निकाल दी है और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : कब तक ? जांच भी हो ।

अध्यक्ष : अब हो गया ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1660 (श्री मुकेश कुमार रौशन, महुआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में वर्तमान में कोई बस स्टैंड नहीं है । रामाशीष चौक पर एन0एच0ए0आई0 की खाली जमीन पर/फ्लाई ओवर के नीचे बस का ठहराव होता है । नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के राज्यादेश सं0–35, दिनांक–10.06.2021 द्वारा हाजीपुर में बस/टैम्पू पड़ाव के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए 515.52000 (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार) रुपये मात्र नगर परिषद, हाजीपुर को हस्तान्तरित किया जा चुका है ।

तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1848, दिनांक–11.07.2023 द्वारा समाहर्ता, वैशाली (हाजीपुर) से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । जिला भू–अर्जन कार्यालय में भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । भूमि उपलब्ध होते ही प्राप्त राशि से सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा युक्त बस–स्टैंड का निर्माण करा लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, मुकेश जी ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, क्या यह बात सही है कि विगत 40 वर्षों से वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के रामाशीष चौक पर बस पड़ाव का संचालन जिला प्रशासन की देख–रेख में हो रहा है ? यदि हां, तो वहां मूलभूत सुविधा, यात्री शेड, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार करने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, इसका स्पष्ट जवाब मैंने दिया हुआ है । उत्तर माननीय सदस्य का आंशिक स्वीकारात्मक है । हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में वर्तमान में

कोई बस स्टैंड नहीं है । रामाशीष चौक पर एन0एच0ए0आई0 की खाली जमीन पर फ्लाई ओवर के नीचे बस का ठहराव होता है ।

(क्रमशः)

टर्न–4 / अभिनीत / 23.03.2025

...क्रमशः..

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के राज्यादेश–35, दिनांक– 10.06.2021 द्वारा हाजीपुर में बस और टेंपू पड़ाव के निर्माण की स्वीकृति करते हुए 5 करोड़ 15 लाख 52 हजार रुपये हाजीपुर को स्थानांतरित कर दिये गये हैं । तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक– 1848, दिनांक–11.07.2023 के द्वारा समाहर्ता, हाजीपुर से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होते ही इस काम को शुरू किया जायेगा । किंतु वहां भूमि की थोड़ी परेशानी है तो अभी हमलोग आगे बढ़कर इसमें रेलवे से बातचीत किये हैं । वहां नगर में कहीं भी बस स्टैंड जहां बन सके वहां सरकार की जमीन नहीं है । समाहर्ता की जो रिपोर्ट है और भू–अर्जन पदाधिकारी को भी इसमें लगाया गया था । नगर के अंदर जहां बस स्टैंड की उपयोगिता है वहां कहीं भी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, तो हमलोगों ने रेलवे से बातचीत की है, रेलवे की कुछ जमीन उपलब्ध है । अभी द्विपक्षीय वार्ता होगी, रेलवे ने कुछ अपनी शर्त रखी है, जैसे ही हमारी वार्ता रेलवे के साथ सफल होती है हमलोग तुरंत इस काम को प्रॉयोरिटी के आधार पर करायेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, आपका भी संबंध रहा है हाजीपुर से, आप जानते हैं कि पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से वहां बस पड़ाव का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है । कैसे माननीय मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं कि वहां बस पड़ाव है ही नहीं । अब बताइये हमलोगों का जन्म–कर्म वहां हुआ, आप भी जाते हैं हाजीपुर और जब भी जाते हैं..

अध्यक्ष : मुकेश जी..

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : पूरा सुन तो लीजिए न ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : वहां पर पिछले 2021 में हमने प्रश्न किया था । तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू उस समय नगर विकास मंत्री भी थे । उसी समय माननीय मंत्री जी ने 05 करोड़ 15 लाख रुपये या 12 लाख रुपये जो भी है उसी समय उन्होंने निर्गत करने का काम किया था । डबल इंजन की सरकार है महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं दीजिए, पूरक पूछिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : चार साल से जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है । महोदय, आखिर किस तरीके की डबल इंजन की सरकार है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए । पूरक कोई है तो पूछिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, चार साल हो गये लेकिन अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हुआ इसका मतलब सरकार इस बस पड़ाव का निर्माण कराना नहीं चाहती है । इसीलिए तो लगता है कि..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । बैठ जाइये, आपका प्रश्न नहीं हो रहा है ।

आप पूरक पूछिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : बैंक में पैसा रखकर, महोदय, बस स्टैंड का निर्माण सरकार कबतक कराना चाहती है, समय सीमा बताये ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने तो आपको बताया कि जमीन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिए । दूसरे की बात सुननी चाहिए । केवल अपनी बात कहने से थोड़े ही होता है । जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं, मैंने भी देखा था लेकिन यह उन्होंने कहा कि वह एन0एच0ए0आई0 की जमीन पर है, फ्लाई ओवर के नीचे रहता है, वह बिहार सरकार की जमीन नहीं है । रुपया सैंक्शन हुआ है और इन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है । जमीन जब बिहार सरकार की नहीं है तो विभाग पहल करके रेलवे से बात कर रही है कि वह जमीन मिल जाये ताकि वहां बस स्टैंड की सुविधा उपलब्ध हो सके । यही तो उन्होंने कहा, इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, हम उत्तेजित नहीं हो रहे हैं । आप बताइये कि वहां जिला प्रशासन के द्वारा पैसा वसूली की जा रही है या नहीं बस पड़ाव के अंदर । पैसा

वसूली हो रही है या नहीं । जब पैसे की वसूली हो रही है तो वहां मूल–भूत सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मिलनी चाहिए, तभी तो सैंक्शन हुए 05 करोड़ रुपये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, डेली वसूली हो रही है, 40 साल से वसूली हो रही है जिला प्रशासन के द्वारा और बस पड़ाव का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है लेकिन डेवलपमेंट की, सरकार की इच्छा भी है कि वहां बस स्टैंड बनाकर यात्री सुविधा स्थापित करे, तभी बिहार सरकार ने रेलवे से बात की है । एक बात माननीय सदस्य को समझनी होगी कि बस स्टैंड वहां बने जहां यात्री को सुविधा हो । अब हम शहर के बाहर जाकर बस स्टैंड बना दें तो गरीबों को टेंपू का भाड़ा इतना देना पड़ेगा, तो बस स्टैंड का कोई मतलब नहीं रह जायेगा । संवेदनशीलता के साथ आप विषय को समझिए । सरकार संवेदनशील होकर रेलवे से बातचीत करते हुए रेलवे की जमीन को, उनके साथ एग्रीमेंट करके हम बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं और पूरी नागरिक सुविधा वहां उपलबध करायेंगे सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : एक मिनट महोदय, वहां पर बी0एस0एन0एल0 गोलम्बर के पास बिहार सरकार की 10 एकड़ की जमीन है रामाशीष चौक पर ही, सरकार को, कई बार हमने भी डी0एम0 से बात करके और उक्त स्थल पर कमीश्नर भी आकर के उस जमीन का निरीक्षण किये लेकिन आजतक चार साल बीत जाने के बाद भी वहां पर बस पड़ाव का निर्माण नहीं हुआ । महोदय, आपकी जमीन वहां पर है, बना दिया जाय क्या दिक्कत है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय–सीमा कैसे निर्धारित हो सकती है जब रेलवे से बात कर रहे हैं । आप ही बताइये आप तो मंत्री रहे हैं । उनका जवाब होने दीजिए न ।

मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जिस जमीन का जिक्र किया है उसको एक बार दिखवा लीजिए ।

माननीय सदस्य श्री अजय यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1661 (श्री अजय यादव, अतरी)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1662 (श्री जय प्रकाश यादव, नरपतगंज)

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, जय प्रकाश जी का जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, नगर पंचायत नरपतगंज के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु विभागीय पत्रांक–3004 नवी/पटना, दिनांक– 25.09.2024 के द्वारा निर्देश दिया गया है । उक्त निर्देश के आलोक में नगर पंचायत, नरपतगंज के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु नगर पंचायत, नरपतगंज के पत्रांक–343, दिनांक–26.10.2024 के द्वारा सभी वार्डों में लगे पोलों के सर्वेक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया है । गठित कमेटी द्वारा सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है एवं नगर पंचायत, नरपतगंज कार्यालय के पत्रांक–44, दिनांक–14.01.2025 के द्वारा कनीय अभियंता, नगर पंचायत, नरपतगंज को एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का प्राक्कलन तैयार करने हेतु पत्र निर्गत किया गया है । इस माह के अंत तक प्राक्कलन तैयार कर लिया जायेगा । प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात निविदा प्रकाशित कर सभी प्रक्रिया पूर्ण कर एजेंसी का चयन किया जायेगा और यथाशीघ्र लाईट लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, हो गया ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय मंत्रीजी को बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री फते बहादुर सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1663 (फते बहादुर सिंह, डेहरी)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक

2– स्वीकारात्मक।

C.W.J.C. NO-15454/2015 के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा C.W.J.C. NO-12299/2016 में स्थगन आदेश पारित था। पुनः M.J.C. NO-3631/2016 में दिनांक–17.12.2024 को स्थगन आदेश समाप्त कर दिया गया है, जिसके आलोक में पूर्व से चल रहे अतिक्रमण वाद

संख्या–02/2007–08 में अतिक्रमणकारी को अंचल अधिकारी, डिहरी के ज्ञापांक–450, दिनांक–13.03.2025 द्वारा पुनः नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

3– उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, जवाब आया है कि जो नारायण मेडिकल कॉलेज द्वारा खाता 560, खेसरा–528 और 529 में 4 एकड़ 25 डेसिमल जो जमीन उनकी है उसमें विद्यालय की 80 डेसिमल जमीन अतिक्रमण किये हैं और यह उच्च न्यायालय का आदेश जो आया था 2016 में, यह आदेश आया था 30 जून, 2016 को कि विद्यालय की जमीन, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या इन अधिकारियों पर जो 9 साल में विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाये इन अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है माननीय सदस्य मेरे उत्तर को नहीं पढ़े हैं । मैंने स्पष्ट कहा है, इन्होंने जो कहा कि 30.06.2016 को उच्च न्यायालय का आदेश था, आदेश था लेकिन तुरंत M.J.C. NO-3631/2016 को स्थगन आदेश भी पारित था उच्च न्यायालय का, मैंने स्पष्ट लिखा है और उसके बाद 17.12.2024 को स्थगन आदेश समाप्त हो गया है । उसके लिए अंचलाधिकारी, डिहरी के ज्ञापांक– 450, दिनांक–13.03.2025 द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद पुनः नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है । महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर में लिखा है । सात साल से, आठ साल से कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि अंचलाधिकारी के द्वारा लेटर नम्बर 271, दिनांक–04.02.2025 को एक नोटिस दिया गया था विद्यालय को कि 20. 02.2025 तक अतिक्रमण हटा लीजिए और जो लेटर नं0 450 जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 13.03.2025 तक आपने अतिक्रमण हटाने का काम नहीं

किया है । 27.03.2025 तक आखिरी आदेश अंचलाधिकारी के द्वारा मेडिकल कॉलेज को दिया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए, तो क्या 27.03.2025 तक अगर मेडिकल कॉलेज द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है...

..क्रमशः..

टर्न–5 / हेमन्त / 20.03.2025

श्री फते बहादुर सिंह : (क्रमशः) : तो क्या सरकार बलपूर्वक विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने का कब तक आदेश देगी और कब तक विद्यालय की जमीन अतिक्रमण मुक्त हो जायेगी।

अध्यक्ष : यह तो 27 के बाद न निर्णय होगा । अगर 27 तक वह हटा लेंगे, जो जरूरत नहीं पड़ेगी ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, एक डेट 25.02.2024 दी गयी थी...

अध्यक्ष : आपने जो पढ़ा मैं वही कह रहा हूं । मैं जानता नहीं हूं ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, 27.03.2025 तक उसको हटाने का आदेश दिया गया है, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर 27.03.2025 तक नहीं हटाते हैं. ..

अध्यक्ष : फते बहादुर जी, अगर–मगर का जवाब नहीं न होता है ।

श्री फते बहादुर सिंह : सरकार क्या कार्रवाई करेगी और विद्यालय की 80 डिसमिल जमीन कब तक मुक्त करा देगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है और उत्तर है, उन्होंने ठीक कहा है कि ज्ञापांक–271..

(व्यवधान)

दिनांक–04.02.2025 के द्वारा अतिक्रमणकारी के विरूद्ध नोटिस निर्गत किया गया था । पुनः अंचलाधिकारी, डिहरी, रोहतास द्वारा ज्ञापांक–450, दिनांक–13.03.2025 से अतिक्रमणकारी को अंतिम चेतावनी देते हुए, अंतिम चेतावनी दी गयी है, 27.03.2025 तक प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु नोटिस निर्गत कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, तो 27.03.2025 में अभी समय है ।

(व्यवधान)

अगर–मगर नहीं न होता है । ललित जी बैठकर बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप सुन क्यों रहे हैं ?

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, इनके जवाब में स्पष्ट नहीं है कि यह कब तक अतिक्रमणमुक्त करा दिया जायेगा । सरकार स्पष्ट करे ।

अध्यक्ष : जब कोई कानूनी नोटिस दिया गया है 27.03.2025 तक खाली करने का, तो पहले कैसे तय हो जायेगा, 27 तारीख के बाद ही न तय होगा ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, अगर 27 तारीख तक खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं...

अध्यक्ष : यह पहले से कैसे अनुमान किया जा सकता है ।

श्री फते बहादुर सिंह : तो 27.03.2025 के बाद सरकार विद्यालय की जमीन कब तक अतिक्रमणमुक्त करवाने का विचार रखती है ? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है न । 27 तारीख तक समय दिया गया है, अगर 27 तारीख तक नहीं करेंगे, तो उसके बाद ही न सरकार कार्रवाई करेगी, विचार करेगी ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, सरकार इसकी एक डेट निश्चित करे । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय विद्यालय की 80 डिसमिल जमीन....

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये ।

श्री फते बहादुर सिंह : कब तक मुक्त करा देगी ।

अध्यक्ष : आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, डेट दीजिए ।

अध्यक्ष : हो गया आपका ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, जवाब नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष : फते बहादुर जी, बैठियेगा तब न होगा । आप खड़े रहेंगे, तो कैसे होगा ।

(व्यवधान)

बैठिये आप । आपका क्या पूरक है ?

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, जब दो बार समय दिया गया, तो क्या गारंटी है कि तीसरी बार में हटा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : यह कोई बात नहीं है ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, नारायण मेडिकल जिसका कॉलेज है, वह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं ।

अध्यक्ष : गलत बात नहीं करिये । बैठिये । आपने उनके सवाल को हल्का कर दिया । आपने हल्का कर दिया गलत बात करके । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1664 (श्री रणविजय साहू, मोरवा)</u>

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री रणविजय साहू : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, रणविजय साहू जी का जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रशासन विभाग में हस्तांतरित हुआ है, क्योंकि यह बिहार लोक सेवा अधिकार के अंतर्गत आता है ।

अध्यक्ष : ट्रांसफर हुआ है, अगली बार आयेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1665 (श्री अशोक कुमार चौधरी, सकरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

2. नगर आयुक्त, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित स्थल की भूगर्भीय नाला के मैन हॉल की मरम्मति करने हेतु नगर निगम, पटना द्वारा दिनांक–13.02.2025 को प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है । सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृति के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर निविदा निस्तार कर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

3. उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री अशोक कुमार चौधरी : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर दिया हुआ है । नगर आयुक्त, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित स्थल की भूगर्भीय नाला के मैन हॉल की मरम्मति करने हेतु नगर निगम, पटना द्वारा....

अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठिये । रामविलास जी, बैठिये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : दिनांक–13.02.2025 को प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल में कही गयी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृति के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर निविदा निस्तार कर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है । इस कार्य को प्रायरिटी में निविदा पूर्ण होते ही हम लोग करायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : हो गया । वह करायेंगे ।

श्री अशोक कुमार चौधरी : कब तक बना देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : मैंने कहा कि इसके लिए निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है । निविदा पूरी होते ही इस काम को करा लिया जायेगा । अगले वित्तीय वर्ष में इसको पूरा कर देंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये । वेल से कही गयी कोई बात नहीं सुनी जायेगी । बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

पूछिये उनसे, ऐसा होता है क्या ? अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद स्टे हो गया । सरकार जवाब कैसे दे सकती है कि हां, हम कल कर देंगे । स्टे रिवॉक भी हो गया, नोटिस हो गया, 27 तारीख तक नोटिस की डेट है । ऐसा थोड़े ही होता है । बैठिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1666 (श्री मिश्री लाल यादव, अलीनगर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1667 (श्री बागी कुमार वर्मा, कुर्था)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नहीं, टेबल नहीं पीटिये । इसकी अनुमति नहीं है । अपने स्थान पर जाकर खड़े होइये। नहीं, जबरदस्ती नहीं हो सकता है । नियम–कानून से काम चलेगा । बिल्कुल नहीं, 27 तारीख के बाद सवाल करियेगा । बैठिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1668 (श्री राजवंशी महतो, चेरिया बरियारपुर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : राजवंशी जी, पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1669 (श्री अजय कुमार, विभूतिपुर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : सूर्यकांत पासवान जी, पूरक पूछियेगा ? नहीं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1670 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, सासाराम)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1671 (श्री अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या–1672 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी, राजा पाकर)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या–1673 (श्री विश्व नाथ राम, राजपुर)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, राजपुर किराये के भवन में संचालित है ।

प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, राजपुर के नये भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है, परन्तु कुछ कार्य अवशेष है । जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–787, दिनांक–25.04.2024 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, बक्सर से पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–1650,(नि0), दिनांक–22.05.2024 एवं 1083 (नि0) दिनांक–13.03.2025 के द्वारा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से पुनरीक्षित प्राक्कलन की मांग की गयी है । प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : विश्वनाथ जी, पूरक पूछियेगा ?

श्री विश्व नाथ राम : महोदय, सरकार ने जवाब दिया है कि वहां भवन बन गया है, जबकि भवन बना होता, तो आपके सरकारी चिकित्सक, पशु चिकित्सक प्राइवेट किराये के मकान में क्यों होते ? महोदय, यह सरकार का उत्तर गलत है ।

अध्यक्ष : क्या पूछना चाहते हैं ? पूरक पूछिये, विश्वनाथ जी ।

श्री विश्व नाथ राम : महोदय, पूछा है हमने कि सरकार कह रही है कि वहां भवन में काम लगा हुआ है । यदि भवन में काम लगा होता, तो सरकारी चिकित्सक, पशु चिकित्सक किराये के मकान में क्यों होते ? इसलिए यह जवाब सरासर गलत है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द–से–जल्द भवन का निर्माण करावे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, राजपुर किराये के भवन में संचालित है ।

प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, राजपुर के नये भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है, परन्तु कुछ कार्य अवशेष है । जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–787, दिनांक–25.04.2024 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, बक्सर से पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–1650,(नि0), दिनांक–22.05.2024 एवं 1083 (नि0) दिनांक–13.03.2025 के द्वारा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से पुनरीक्षित प्राक्कलन की मांग की गयी है । प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उनका कहना है कि जल्दी करवा दीजिए ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : महोदय, यह पुनरीक्षित किया गया है ।

श्री विश्व नाथ राम : महोदय, भवन बनना चाहिए । जब भवन बन जायेगा, तो किराये के मकान में पशु चिकित्सक नहीं रहेंगे ।

अध्यक्ष : इनका कहना है कि जल्दी करवा दीजिए ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : महोदय, इसको पुनरीक्षित होते ही करवा देंगे, अवशेष है ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1674 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, नवीनगर)</u>

अध्यक्ष : पूरक पूछिये विजय जी ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, 10.30 बजे तक जवाब नहीं आया था ।

अध्यक्ष : उत्तर पढ़ दीजिए मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–क, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दिसम्बर, 2024 के तिमाही तक राज्य में लगभग 38.56 लाख के॰सी॰सी॰ धारक किसान हैं ।

खंड–ख, आंशिक स्वीकारात्मक है । के॰सी॰सी॰ ऋण धारक किसानों को केन्द्र द्वारा 03 प्रतिशत तथा बिहार सरकार द्वारा 01 प्रतिशत, कुल 04 प्रतिशत कृषि ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है, जिसे समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को के॰सी॰सी॰ में मात्र 03 प्रतिशत शुद्ध ब्याज दर, 03 लाख रुपया तक कृषि ऋण प्राप्त करने की सुविधा है । इसके अलावा कृषकों को प्रोत्साहन तथा जागरूकता हेतु बैंकों के द्वारा समय–समय पर प्रखंड स्तर पर वसूली शिविर के अलावा के॰सी॰सी॰ ऋण वितरण कैम्प का आयोजन किया जाता है । बैंकों द्वारा किसानों को समय पर के॰सी॰सी॰ ऋण के पुनर्भुगतान अपने क्रेडिट स्कोर को बनाये रखने के लाभ के प्रति जागरूक किया जाता है । हालांकि, बिहार और उड़िसा सार्वजनिक माँग वसूली अधिनियम, 2014 के तहत ऋण चुककर्त्ता, सर्टिफिकेट केस करने का प्रावधान है जिसकी विभिन्न बैंकों में लंबित मामलों की समीक्षा जिला तथा राज्य स्तर पर राजस्व पर्षद द्वारा की जाती है...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दिसम्बर, 2024 की तिमाही तक राज्य स्तर पर सदस्य बैंकों के कुल 3,94,940 मामले लंबित हैं । वर्तमान में किसानों का के॰सी॰सी॰ ऋण माफ करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : सब लोग चले गए, आप भी जा रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, किसानों के प्रति इनकी संवेदनशीलता दिखायी नहीं पड़ती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1675 (श्री संजीव चौरसिया, दीघा)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पानी टंकी (ए०एन० कॉलेज) के पास आवासीय घरों से उत्सर्जित कूड़े को वर्णित स्थल पर छोटे वाहनों यथाः– ई–कार्ट, क्लोज टिपर आदि से बड़े वाहन हाईवा में ट्रान्सफर कर रामाचक बैरिया स्थित डम्पिंग यार्ड में निस्तार किया जाता है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित स्थल की घेराबंदी किया गया है एवं रात्रिकालीन में ही उक्त स्थल से कूड़े को ''0'' शून्य

कर दिया जाता है । वर्णित स्थल पर वाटर स्प्रींक्लर से प्रतिदिन धुलाई की जाती है साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में चूना, ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाता है ।

3. दीघा क्षेत्र में एफ०सी०आई० के पीछे असर्वेक्षित भूमि का चयन किया गया है । जिला प्रशासन द्वारा अनापत्ति भी प्रदान कर दी गई है । भूमि उपलब्ध होने पर कूड़ा डम्पिंग यार्ड को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, पूरक है कि माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि डम्पिंग यार्ड का जीरो वहाँ पर कर दिया जाता है, साथ–साथ एफ॰सी॰आई॰ के पास जो भूमि चिन्हित किया गया है वहाँ पर डम्पिंग यार्ड को ले जाया जायेगा तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अधिकारियों के द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि जीरो कर दिया जाता है और वहाँ के स्थान को धोया जाता है । वहाँ के लोगों को देखा जाय तो लाखों की आबादी में जिस प्रकार बदबू आती है, वहाँ की जनता खुशबू का इंतजार कर रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो स्थान चयनित हुए हैं, उस चयनित जगह पर कब से काम लगेगा और वहाँ जो डम्पिंग यार्ड है उसके साथ–साथ गाड़ी का भी यार्ड वहाँ से हटेगा या नहीं हटेगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कब तक हटेगा यह न पूछिये ? माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि भूमि का चयन हो गया है, भूमि मिल गयी है, उसके लिए अनाप्ति भी जिला प्रशासन के द्वारा दे दिया गया है । यथाशीघ्र हम अगले महीने ही कार्रवाई शुरू करेंगे और यथाशीघ्र जो माननीय सदस्य की चिंता है वहाँ के आम–आवाम को लेकर, उनको यथाशीघ्र राहत मिलेगी यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, केवल एक चीज है कि टेंडर भी निकला है, री–टेंडर हुआ है तो टेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है इसीलिए कोई समय अवधि माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायें चूंकि जनता देख रही है, जनता जानना चाहती है कि कब तक वहाँ पर होगा ? इसकी आप सदन में आश्वासन दें ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर की प्रक्रिया इस सरकार में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है । हमने टेंडर निकाला, पहली बार टेंडर में एकल अगर एक ही व्यक्ति ने निविदा डाला तो दोबारा फिर से टेंडर की प्रक्रिया करना यह नियमसंगत है तो दोबारा टेंडर हुआ है । मुझे उम्मीद है कि कोई–न–कोई इसमें सहभागी भाग लेंगे और नियम के अनुसार उसको फाईनल किया जायेगा । तभी मैंने कहा कि बहुत जल्द वहाँ, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको खत्म करते हुए आम–आवाम को वहाँ राहत मिलेगी, यह सरकार आश्वस्त करती है ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, केवल एक और, माननीय मंत्री जी से चाहिए कि वहाँ डम्पिंग यार्ड के साथ–साथ गाड़ियों का, जे॰सी॰बी॰ का, लोडर का, सब का वहाँ यार्ड बना है तो वह भी वहाँ से हटेगा न ? यह माननीय मंत्री जी से हम आश्वासन चाहते हैं ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक बात है जब हमारे पास अलग जमीन मिल गयी है और जब डम्पिंग यार्ड वहाँ बनायेंगे, वहाँ लोडर इसलिए रहता है कि कूड़ा उठाने के लिए कुछ मशीन, कुछ गाड़ियों को वहाँ रखा जाता है तो जब हमको जगह मिल जायेगी तब पूरा का पूरा मशीन समेत, गाड़ी समेत, पूरी जो व्यवस्था है डम्पिंग यार्ड की, हम नये जगह में शुरू करेंगे तो वहाँ के आम–आवाम को इससे निजात मिल जायेगी, यह मैं आश्वस्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मुझे भी उस रास्ते से बार–बार गुजरना पड़ता है । अटल पथ से अगर पाटलिपुत्र कॉलनी जाना है तो वही रास्ता सुगम है । वास्तव में बड़ी चिंताजनक स्थिति है और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि दूर्गंध को सुगंध में कब बदलियेगा तो जितना जल्दी हो सके, उतना इस पर कार्रवाई कीजियेगा यह विश्वास भी है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1676 (श्री देवेश कान्त सिंह, गोरियाकोठी)</u>

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक । सिवान जिलान्तर्गत प्रखण्ड गोरेयाकोठी में विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित 02 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना एवं 11 अदद वार्ड आधारित हर घर नल जल योजना कार्यरत है । सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण किया गया है । सभी योजनाएँ सुचारू रूप से चालू है । गोरेयाकोठी प्रखण्ड में पंचायती राज विभाग द्वारा PHED को हस्तानांतरित कुल योजनाओं की संख्या 284 है, इसमें 271 अदद चालू है तथा 13 अदद विशेष मरम्मती हेतु बंद है । विशेष मरम्मती वाले योजनाओं पर चयनित संवेदक के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है । इस माह तक पूर्ण कर चालू कर दिया जायेगा । इन 13 अदद विशेष मरम्मती वाले वार्डों में कुल चापाकलों की संख्या–48 अदद है, जो सभी चालू है ।

प्रखण्ड बसंतपुर में विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित 02 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना एवं 13 अदद वार्ड आधारित हर घर नल जल योजना कार्यरत है । सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण किया गया है । सभी योजनाएँ सुचारू रूप से चालू है । बसंतपुर प्रखंड में पंचायती राज विभाग द्वारा PHED को हस्तानांतरित कुल योजनाओं की संख्या 101 है, इसमें 96 अदद चालू है तथा 05 अदद विशेष मरम्मती हेतु बंद है । विशेष मरम्मती वाले योजनाओं पर चयनित संवेदक के माध्यम से कराया जा रहा है । इस माह तक पूर्ण कर चालू कर दिया जायेगा ।

इन 05 अदद विशेष मरम्मति वाले वार्डों में कुल चापाकलों की संख्या–17 अदद है, जो सभी चालू है ।

प्रखण्ड लकड़ी नबीगंज में विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित 01 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना है जो सुचारू रूप से चालू है । सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण किया गया है । लकड़ी नबीगंज प्रखंड में पंचायती राज विभाग द्वारा PHED को हस्तानांतरित कुल योजनाओं की संख्या 170 है. इसमें 158 अदद चालू है तथा 12 अदद विशेष मरम्मती हेतु बंद है । विशेष मरम्मती वाले योजनाओं पर चयनित संवेदक के माध्यम से कराया जा रहा है । इस माह तक पूर्ण कर चालू कर दिया जायेगा । इन 12 अदद विशेष मरम्मती वाले वार्डों में कुल चापाकलों की संख्या–43 अदद है, जो सभी चालू है ।

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की तरफ से या विभाग की तरफ से प्रश्न को अस्वीकारात्मक दिखाया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, जबकि हमारी लॉबी में भी बात हुई थी और संबंधित जो विषय है, अब तो विभाग जवाब दे रहा है माननीय मंत्री जी को...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, मेरा यह कहना है कि विभाग द्वारा जो जवाब दिया गया है वह संतोषजनक नहीं है । मेरा आग्रह होगा कि दो–तीन विषय इसमें जोड़ा जाय, ध्यान दिया जायेगा, इसमें आधा बीमारी अनुरक्षक कौन रहेगा, क्यों नहीं चलेगा? इसके चलते हैं । इसलिए जो टूट गया है, फूट गया है, जल गया है वह ठीक नहीं हो पा रहा है । अनुरक्षक विवाद समाप्त किये बिना वह ठीक नहीं हो सकता है । मेरा मंत्री जी से यह आग्रह है सुझाव के तौर पर कि इसको करा कर, उसको सुविधाजनक करा दिया जाय । पूरे सरकार का यह बहुत ही प्रिय योजना है इससे जनता को बहुत लाभ भी हुआ है । मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री इसका तत्काल कुछ–न–कुछ व्यवस्था करायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी तो आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, लॉबी में भी आपलोग बात करते हैं ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, सुनते हैं लेकिन यहाँ सदन में जवाब देंगे तो क्षेत्र और बिहार पूरा सुनेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब विस्तार से दिया हुआ है और जो मामला है वह स्थानीय है और अनुरक्षक वाले मामले में अगर माननीय सदस्य पहल करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी समाधान हो जायेगा जो रिपेयरिंग का काम है हमलोग करा रहे हैं । माननीय सदस्य का आरोप था कि काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वह हमने जाँच करा ली है । काम की क्वालिटी बेटर है और हमने समय–सीमा भी दे दिया है कि जो बचे हुए टोले हैं उसे हमलोग कब तक करने वाले हैं जो लास्ट प्रश्न है माननीय सदस्य का कि वार्ड सदस्य की झंझट, ये वार्ड सदस्य की जो झंझट है अनुरक्षक के रूप में तो माननीय सदस्य चाहेंगे तो स्थानीय रूप से ही निदान हो जायेगा, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी तो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा । माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि स्थानीय मामला है, निपटा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि एक तय नियम कर दिया जाय क्योंकि जीता–हारा दोनों वार्ड हमारा तो हम किसका पक्ष रखेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, सरकार तय कर दे कि किसको पेमेंट होना चाहिए । बहुत लोगों का निजी भूमि में गड़ा है तो उसमें क्या करना है ? यह एक तय कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के आग्रह पर गंभीरता से विचार कर निदान कराने का काम कीजिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1677 (श्री अजीत कुमार सिंह, डुमरांव)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1678 (श्री राम सूरत कुमार, औराई)</u>

श्री संजय सरावगी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, (1) आंशिक स्वीकारात्मक । समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि बागमती परियोजना अंतर्गत औराई विधान सभा के प्रखंड औराई एवं कटरा में तटबंध बनाने का कार्य चल रहा है । भू–अर्जन की कार्रवाई अभी भी चल रही है । औराई ग्राम अंतर्गत ग्राम बेनीपुर के विस्थापित परिवारों (उत्तर तरफ 158 एवं दक्षिण तरफ 394) को ग्राम बहुअरवा एवं ग्राम–बसंत उर्फ उमापत में पुनर्वासित भी किया गया है । यह कार्य तत्कालीन पुनर्वास कार्यालय, सीतामढ़ी एवं विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाता था । किन्तु कालान्तर में उक्त

कार्यालय के विघटन के फलस्वरूप विस्थापितों के पुनर्वासन एवं व्यवस्थापन का कार्य पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सका है।

(2) स्वीकारात्मक । बागमती के दोंनों तटबंधों के सुदृढ़ीकरण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है ।

(3) स्वीकारात्मक । बागमती योजना अंतर्गत विस्थापित परिवारों को पुनर्वासन हेतु बिहार रैयती सतत लीज नीति, 2014 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (RECTLARR Act-2013) के अंतर्गत नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री राम सूरत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूरक पूछना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूछिये ।

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, इसमें दो विषय है, दो विषयों में से एक ही विषय का जवाब मिला है लेकिन मेरा कहना है कि भूमिहीन परिवार जैसे मालिकाना जमीन पर और सरकार के जमीन पर मकान बनाकर बागमती परियोजना के बीच में रह रहे थे लेकिन सरकार के नियमानुकूल जिनकी निजी जमीन थी उनको ही मकान का भुगतान हुआ और उनके परिवार के लिए सरकार ने जमीन चिन्हित किया,

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में आ गए)

चिन्हित कर उनको 05 डिसमिल जमीन भी दिया लेकिन चिन्हित करने के क्रम में लगभग 34 गाँव को विस्थापित किया गया, उसमें से मात्र एक गाँव बेनीपुर गाँव को....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये । समय नहीं है ।

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, बाकी 33 गाँव को जमीन नहीं मिल पायी और वैसे परिवार जिनके पास न अपना जमीन था, न सरकार के जमीन पर थे, न मकान का मुआवजा मिला और वैसे परिवार बाँध पर रह रहे हैं, वैसे परिवारों को सरकारी जमीन देकर विस्थापित करना है तो दो तरह की प्रक्रिया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बाड़ा बुजुर्ग, चैनपुर ईमलिया, बाड़ा खुर्द, महुआरा उर्फ महुआरा, वसुआ, चैनपुर, नयागाँव, गोपालपुर विशुनपुर, बसंत, मथुरापुर बुजुर्ग, भरथुआ, मधुबन प्रताप, धनौर, बभनगांवा, जो कि खुर्द, जोकी चैनपुर, जनाड़ बेनीपुर....

अध्यक्ष : राम सूरत जी, समय नहीं है । 12 बज रहा है । आप पूरक पूछिये ।

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, यह जिला भू–अर्जन के द्वारा लगभग 86 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया जिसमें से मात्र 16 एकड़ जमीन ही बांटा गया ।

अध्यक्ष : राम सूरत जी, पूरक पूछिये ।

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक नहीं पूछ रहे हैं । मैं तो दो पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री का सुनना चाहता हूँ । आप पूरक ही नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं कि 86 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा सूची प्राप्त है कि लिया गया लेकिन उसमें से 16 एकड़ जमीन ही बाँटा गया ।

अध्यक्ष : आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, कब तक बांटेंगे ?

अध्यक्ष : यह बात हुई न ।

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, दूसरा एक चीज और है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय नहीं है ।

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, जिनकी जमीन है उनके लिए है, जिनके पास जमीन नहीं है वे अलग हैं, वैसे भूमिहीन परिवारों को कब तक देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

टर्न–7 / संगीता / 20.03.2025

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना में विलंब हुआ है । विलंब का कारण क्या था कि यह कार्य पहले तत्कालीन पुनर्वास कार्यालय, सीतामढ़ी एवं विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाता था । किन्तु कालांतर में उक्त कार्यालय के विघटन के फलस्वरूप विस्थापितों के पुनर्वासन एवं व्यवस्थापन का कार्य पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सका है । माननीय सदस्य जो बोले हैं जिन–जिन गांवों की चर्चा की है, उन सभी गांवों की सूची भी मैंने मंगवाया है । इसमें प्रभावित परिवारों की सूची भी मैंने मंगवायी है कि जैसे उन्होंने जिस–जिस गांवों की चर्चा की है, पढ़ूंगा तो बहुत विलंब हो जाएगा, बरारी उर बरारी बुजुर्ग...

अध्यक्ष : नहीं पढ़ना है । उसको पढ़ दिए हैं मंत्री जी ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : जी । अध्यक्ष महोदय, एक तो इसमें पुनर्वासन की योजना जो है बागमती योजना अंतर्गत विस्थापित परिवारों को पुनर्वासन हेतु बिहार रैयती सतत् लीज नीति, 2014 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (RECTLARR Act-2013) के अंतर्गत नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । इसमें विलंब हुआ है मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, इसको जल्द से जल्द माननीय सदस्य को भी बुलाकर...

अध्यक्ष : हां, यह सही है ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : बैठकर इसमें क्या हो सकता है इसमें तुरंत कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे । माननीय सदस्य चिन्तामुक्त रहें, जो भी प्रभावित परिवार हैं उन लोगों की चिन्ता सरकार जरूर करेगी ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 की धारा–64 के तहत बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 एवं बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 एवं बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 की प्रति 14 दिनों तक सदन पटल पर रखी रहेगी ।

प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली, 2012; बिहार राज्य अभिलेखागार रेप्रोग्राफिस्ट (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ख' (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ग' (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेख निदेशक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2015 एवं बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेखवाह/अभिलेख लिपिक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2015 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022; राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) नियमावली, 2023 एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग नियमावली, 2023 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार नगरपालिका सेवा नियमावली, 2021 की प्रति को सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा, सभापति (प्रत्यायुक्त विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–2011 के तहत प्रत्यायुक्त विधान समिति का समाज कल्याण विभाग एवं गृह विभाग से संबंधित नवम् प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

(व्यवधान)

बोलने दीजिएगा भाई, पहले कहने तो दीजिए न ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–20 मार्च, 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0, श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0, श्री बिरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0, श्री शिव प्रकाश रंजन, स0वि0स0, श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0, श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0, श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री बिरेन्द्र कुमार, स0वि0स0, श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0, श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0, श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0, श्री सूर्यकान्त पासवान, स0वि0स0 एवं श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0 ।

2. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0, श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0, श्री मुकेश कुमार रौशन, स0वि0स0, श्री सउद आलम, स0वि0स0, श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0, श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0, डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0, श्री भूदेव चौधरी,

स0वि0स0, श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0, श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, श्री चंद्रहास चौपाल, स0वि0स0 एवं श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0 ।

3. श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 ।

आज दिनांक–20 मार्च, 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–172 (3) एवं नियम–47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, कार्य–स्थगन प्रस्ताव है हम चाहते हैं इस पर सरकार वक्तव्य दे...

अध्यक्ष : पढ़ना चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : जी ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । श्री महानंद सिंह जी, पढ़िए ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में नल–जल योजना पूरी तरह से ध्वस्त है । अधिकांश मुहल्लों में नल–जल योजना पहुंची भी नहीं है । इस बीच, पूरे बिहार में पेयजल का संकट लगातार गहरा होता जा रहा है । यहां तक कि सोन तटीय इलाकों में भी हाल के दिनों में अनियंत्रित बालू उत्खनन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव और तदनुरूप जल स्तर के काफी नीचे चले जाने से पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। साथ ही, लोक स्वास्थ्य व अभियंत्रण विभाग द्वारा गांवों में जो चापाकल लगाए जाते थे, वे भी नल–जल योजना के कारण बंद हो चुके हैं । आम नागरिकों को न तो नल–जल योजना का लाभ मिल रहा है और न ही चापाकल लगाए जा रहे हैं जिससे पेयजल संकट गहरा हो गया है ।

अतः पेयजल की लगातार होती जा रही गंभीर समस्या पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करते हैं ।

अध्यक्ष : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के प्रति राज्य सरकार के उदासीन रवैया के कारण जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की स्थिति खराब हो रही है । राज्य के PDS दुकानदारों को 90 रुपये प्रति

क्विंटल के बदले 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाय । मानदेय के रूप में 25,000 रुपये दिया जाय । PDS दुकानदानों को कार्यरत रहने के दौरान किसी भी उम्र में मृत्यु होने पर अनुकम्पा दिया जाय ।

अतः दिनांक–20.03.2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य में PDS दुकानदारों की बेहतरी हेतु विमर्श किया जाय ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज के लिये सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में घोर बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हो ।

उल्लेखनीय है कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है । बेरोजगारी के कारण पिछले छः महीने में कम से कम एक दर्जन लोगों ने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली । सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिये जो कदम उठाये हैं वे कारगर नहीं हैं और जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नगण्य हैं । युवाओं में हताशा है । यदि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराये गये तो आनेवाले समय में स्थिति भीषण होने की संभावना है ।

अतः आज के लिये सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में घोर बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हो ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आज शून्यकाल की संख्या अंदाज है आपको कितना है – 66 है ।

पढ़िए गायत्री देवी जी ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत सुतिहारा ग्राम में राम जनकी मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है जो जर्जर स्थिति में है ।

अतः परिहार प्रखण्ड में सुतिहारा राम जनकी मंदिर की मरम्मति एवं चहारदीवारी निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री अशोक कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड में ग्राम–नावानगर, दुर्गावती प्रखण्ड में ग्राम–मैरे, विन्दपुरवाँ, खुटहॉ, कलवरीयॉ, सखेलीपुर एवं सारंगपुर नुआँव प्रखण्ड के ग्राम–हरिहरपुर डेरा, लखनपुरा डेरा एवं भटवलीया ये सभी ग्राम दलित एवं अतिपिछड़ों का है मैं सरकार से भवन निर्माण कर प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं ।

टर्न–8 / सुरज / 20.03.2025

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित पोषाहार योजना में आंगनवाड़ी केन्दों में कार्यरत सेविका एवं सहायिका तथा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ताओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुये सरकारी कर्मी के अनुरूप समान सुविधाएं देने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के नौवागढ़ी एवं बरियारपुर पिछड़ा बाहुल क्षेत्र है । सरकारी महाविद्यालय नहीं होने के कारण यहां के छात्र–छात्राओं को मुंगेर, जमालपुर या सुल्तानगंज पढ़ने के लिये जाना पड़ता है ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से सदर प्रखंड के नौवागढ़ी एवं बरियारपुर प्रखंड में राजकीय/अंगीभूत महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड को मधुबन डाकबंगला चौक एन0एच0–104 से ब्लॉक रोड भाया नौरंगीया डीह, नवादा, मझौलिया, पताही होते हुये चोरमा बरगैनीया भारत माला रोड में जोड़ने की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी में मनभरी कुंअर धर्मशाला स्व0 मनभरी कुंअर के 1952 के भूमि समर्पण नामा पर धार्मिक न्यास से निबंधित वो संचालित धर्मशाला को अवैध बिक्री नामा करा लिये हैं ।

भू–माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई एवं सरकार द्वारा आमजन के लिये धर्मशाला को संचालित कराने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बरूराज विधान सभा में एक ही महाविद्यालय है, जिसमें लगभग 6000 छात्रों की संख्या है, लेकिन शैक्षणिक भवन की कमी के कारण पठन–पाठन कार्य में काफी कठिनाईयां होती है।

अतः मैं सरकार से छात्रहित में जीवक्ष महाविद्यालय, मोतीपुर में शैक्षणिक भवन के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के रायपुर पंचायत में किशनगंज–ठाकुरगंज रोड से धुबनिया दलित टोला एवं धुबनिया गांव होते हुये ईदगाह तक पक्की सड़क नहीं रहने के कारण आमजनों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

उक्त सड़क का निर्माण अतिशीघ्र करवाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में लगे पंचायती राज प्रतिनिधियों यथा वार्ड सदस्य, ग्राम पंच पंचायत समिति, जिला पार्षद, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख के मानदेय में वृद्धि करने तथा बकाया मानदेय भुगतान करने एवं दोषी अधिकारी पर सरकार कार्रवाई करे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने से बड़ी संख्या में +2 के उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं के नामांकन में भारी कठिनाई होती है ।

अतः शीघ्र बासोपट्टी में एक डिग्री कॉलेज खोलने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस0एच0–88 बलहा सालेपुर मोर के निकट से मुसेपुर स्टेट ट्यूबवेल से सिंघिया पर्रा बाध, पैकरा पोखर के पश्चिम तरफ से बसुदेवा ग्राम के पश्चिम होते हुये सिंघिया हिरणी कुशेश्वरस्थान पथ में सिंघिया प्रखंड के कर्पूरी चौक तक बाईपास नवीन पथ (ग्रीनफील्ड) का निर्माण करने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल से गंधवार, सन्नौर होते हुये रैयाम, मुरिया मुख्य सड़क तक की सड़क पंडौल–रहिका के कई पंचायतों को जोड़ती है । बड़ी गाड़ियों के परिचालन से सड़क जीर्ण–शीर्ण हो गयी है ।

उपर्युक्त सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहीत कर जीर्णोद्धार कराया जाय ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में शानदार एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति में मानवबलों के उत्कृष्ट योगदान के मद्देनजर मैं सरकार से मानव बलों की सेवा

एजेंसी के बजाय कार्यपालक अभियंता के माध्यम से सीधे लेने तथा मानव बलों को न्यूनतम मजदूरी की दर से मासिक वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : श्री मुहम्मद इजहार असफी । बैठिये आप । असफी साहब बोलिये ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने अन्य जगह जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ।

उक्त प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : सुश्री श्रेयसी सिंह ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बैठिये, नहीं बैठिये, शून्यकाल चलने दीजिये ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जमुई प्रखंड के गरसंडा पंचायत के बालाडीह–गरसंडा गांव में राजस्व क्षेत्र का किऊल नदी से होने वाले कटाव से क्षति को देखते हुये वृहद पैमाने पर कटाव रोधी कार्य कराने की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप अलग से मेरे कक्ष में आकर मुझे बताइयेगा, बैठिये ।

श्री ललन कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : कक्ष में आकर बताइयेगा, अभी नहीं, बैठिये । श्रीमती मंजू अग्रवाल ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप अलग से मुझे बताइयेगा, बैठिये । आप बात सुनिये, बैठिये । अलग से मुझे बताइयेगा, बैठिये । बोलिये ललित जी ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि फीडर में बोरिंग के लिये सिंचाई हेतु पोल, तार, ट्रांसफॉर्मर, मीटर एवं विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र आवंटित कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 16 स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं । एम्बुलेंस की कमी की वजह से 17 पंचायतों के मरीजों को ईलाज में कठिनाइयां होती है । सरकार से आदापुर में 02 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड में भंगहा देवी स्थान एवं कामेश्वरनाथ महादेव मंदिर सिरिसिया का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है ।

अतः सरकार से भंगहा एवं कामेश्वरनाथ महोदव मंदिर सिरिसिया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सूर्यकांत पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला सहित पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविका को 2015 में 2G मोबाईल दिया गया एवं रिचार्ज के लिये 166 रुपया दिया जाता है, जो काम योग्य नहीं है ।

अतः सेविका को नया 5G मोबाईल एवं रिचार्ज हेतु 500 रु0 महीना देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी एवं तेतरिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं होने से इस क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को ग्रेजुएशन की पढ़ाई में कठिनाई होती है ।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि मेहसी एवं तेतरिया में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरवा प्रखंड के बाजितपुर करनैल, इन्द्रवारा, ररियाही, धर्मपुर बांदे, केशोनारायणपुर, मरीचा पंचायतों से पटोरी अनुमंडल की दूरी 5–7 कि0मी0 है । ये पंचायत 35–40 कि0मी0 दूर समस्तीपुर अनुमंडल में शामिल है, जिससे आमजनों को समस्या होती है ।

अतः उपरोक्त पंचायतों को पटोरी अनुमंडल में जोड़ने की मांग करता हूं।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के खजूरी पंचायत में बिलेनिया नदी में रैयती जमीन का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर बनाया गया बांध नदी के बहाव के कारण क्षतिग्रस्त होने से किसानों के फसल का प्रतिवर्ष नुकसान होता है ।

उक्त स्थल पर ड्रेनेज के पुननिर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

टर्न–9 / राहुल / 20.03.2025

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् के बगल से गुजरने वाली सीताधार एवं जोगबनी नगर परिषद् के बगल से गुजरने वाली चेंगामारीधार, दोनों शहरों के महत्वपूर्ण जल निकासी मार्ग हैं जो संकीर्ण हो गया है । दोनों धार को 100 फीट पक्के कैनाल के रूप में विकसित करने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड, ग्राम पंचायत मधुवन बसहा पश्चिमी, ग्राम–बंगराहा की आबादी पांच हजार है । उक्त ग्राम के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ 7 किलोमीटर की दूरी पर हाईस्कूल नहीं है, जनहित में मध्य विद्यालय, बंगराहा को हाईस्कूल में अपग्रेड करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिले के प्रखंड गौनाहा अंतर्गत ग्राम मंगुराहा के स्थानीय किसानों का आवागमन रेंजर मंगुराहा द्वारा रोक लगा दी गयी है । मैं सरकार से मांग करती हूं कि किसानों के आवागमन पर से रोक हटायी जाय।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलांतर्गत कच्छवां थाना कांड संख्या–61 / 25, दिनांक–13.03.2025 में मृतका रचना कुमारी का दुष्कर्म कर तेजाब छिड़क कर निमर्म हत्या कर दी गयी है । मृतका को न्याय दिलाने हेतु एस0आई0टी0 गठित कर उच्चस्तरीय जांच कराते हुए दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलांतर्गत कोढ़ा प्रखंड में पूर्व से प्रस्तावित 132 / 33 केवीए ग्रिड सबस्टेशन जो चार वर्ष पूर्व प्रस्तावित हुआ था, अब तक भूमि अधिग्रहण नहीं हुई है । अतः जनहित में उक्त ग्रिड सबस्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण कराकर ग्रिड सबस्टेशन का शीघ्र निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलांतर्गत प्राणपुर प्रखंड के केहुनिया पंचायत के भोपत कुंडी एवं चिकनी धार में लंबे समय से पुल निर्माण कार्य प्रतीक्षित है । अतएव जनहित में मैं यथाशीघ्र उक्त पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत बहादुरगंज प्रखंडाधीन निशन्द्रा पंचायत अंतर्गत बीना बाड़ी हाट टंगटंगी का पुल टूटे हुए एक दशक के बाद भी नहीं बन पाना दुर्भाग्यपूर्ण है । टूटे हुए पुल से गाड़ियों के परिचालन से कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है । मैं सरकार से लोकहित में पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा अंतर्गत एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है । बच्चे एवं बच्चियों को 30–35 किलोमीटर की दूरी तय कर जिले में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है । मैं सरकार से उपर्युक्त कोई भी प्लस टू स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

डॉक्टर संजीव कुमार, श्री उमाकांत सिंह एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद देश में सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से आरक्षण का लाभ समाज के उन वर्गों को दिया गया था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे । आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के तहत आरक्षण दिया गया लेकिन अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरी आदि में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है जिस कारण ई0डब्लू0एस0 श्रेणी में काफी अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में आवेदन से वंचित हो रहे हैं ।

अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि संविधान के 103वें संशोधन के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में

नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है । इस आरक्षण के प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक–31.01.2019 के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 द्वारा एक नियमावली प्रवृत है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त वर्णित आफिस मेमोरेंडम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान अंकित है । इसलिए राज्य सरकार की नियमावली में भी इसका प्रावधान नहीं किया गया है ।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ई0डब्लू0एस0 के छात्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान की गयी है और आरक्षण का सही लाभ तभी मिलेगा जब एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 की तरह सरकारी नौकरियों के लिए भी ई0डब्लू0एस0 में उम्र की सीमा की छूट दी जाय । यह आरक्षण तभी प्रसांगिक होगा जब आर्थिक आधार पर पिछड़े छात्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाय । अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में जब मिल रहा है और बड़े–बड़े राज्य हैं, गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र तो यहां पर क्यों नहीं दिया जा रहा है ? यह बहुत जरूरी है जो वास्तव में गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से तबाह लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा। इस पर सरकार सोचे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है । यह संविधान के 103वें संशोधन का प्रश्न है तो राज्य सरकार इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, यह संशोधन का कार्य भारत सरकार ही कर सकती है और जब भारत सरकार संविधान के 103वें संशोधन में कुछ करेगी तभी माननीय सदस्य जो बात उठा रहे हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है ।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, बस एक सेकंड । महोदय, सरकार अपनी तरफ से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे क्योंकि अन्य राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु में भी हो रहा है तो यहां क्यों नहीं हो सकता है ?

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री उमाकांत सिंह : उन्हें सभी राज्यों में अन्य राज्यों में जैसे माननीय संजीव जी ने बताया उनकी आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ाने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं । सीमा आयु बढ़ जाय जिस तरह से और लोगों को आरक्षण मिल रहा है उस तरह से ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं तो फिर आरक्षण से लाभ क्या मिलेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जवाब चाहता हूं कि वह दो तरह का नहीं

हो, अगर आरक्षण मिला है तो उसका लाभ मिले नहीं तो फिर ये आरक्षण से क्या फायदा ?

अध्यक्ष : यह मामला राज्य सरकार का नहीं है । यही तो कहा उन्होंने...

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, सरकार प्रस्ताव भेज सकती है ।

अध्यक्ष : बैठिये । बैठिये न ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । सरकारें अलग–अलग होती हैं । एक गठबंधन की सरकार हो सकती है लेकिन सरकारें अलग–अलग हैं, सबके नियम–कानून अलग–अलग हैं।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये आपका हो गया है । बैठिये न । बैठ जाइये ।

डॉ0 संजीव कुमार : महोदय, सरकार प्रस्ताव तो भेज सकती है ।

अध्यक्ष : बैठियेगा तब न एक बार । आप लोगों की भावनाओं को मंत्री जी ने सुना है ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य के पटना शहर में बेशकीमती 11.86 एकड़ भूमि गर्दनीबाग में बिहार वित्त सेवा निर्माण समिति को सरकार द्वारा दे दिया गया है । समिति एवं जिला प्रशासन द्वारा आनन–फानन में पूरे भूखंड की चहारदीवारी कार्य भी आरंभ कर दिया गया है । बिहार वित्त सेवा निर्माण समिति को कहीं अन्य जगह पर भूखंड दिया जा सकता है । उल्लेखनीय है कि गर्दनीबाग में आवंटित भूखंड की घेराबंदी होने से एक हजार परिवार का मोहल्ला धीराचक जो कि सौ वर्षों से इसी भूखंड से रास्ते का उपयोग कर रहे थे, अब पूर्णरूपेण बंद हो जायेगा जिससे हजारों परिवार आपातकालीन सेवा यथा अग्निशामक वाहन, एम्बुलेंस इत्यादि की सेवा से वंचित हो जायेंगे ।

अतः बिहार वित्त सेवा निर्माण समिति को अन्य भूखंड देने एवं मोहल्ला वासियों को पुराना रास्ता या चालीस फीट चौड़ा रास्ता देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

टर्न–10 / मुकुल / 20.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दूसरे विभाग में ट्रांसफर है तो वहां से जवाब आयेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका जवाब अगली बार आयेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, किस विभाग से जवाब आयेगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका जवाब आ जायेगा, अगली बार आ जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तो नगर विकास से, रास्ता से भी संबंधित है और नगर का मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ? आपने जब पुट कर दिया तो यह सदन की संपत्ति हो गई, इसका जवाब आयेगा, इसमें चिंता क्या करना ।

माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन साहब ने अपनी शून्यकाल की सूचना में धुबनिया हरिजन टोला का जिक्र किया, हरिजन शब्द अब संवैधानिक नहीं है, उसको दलित टोला कहना चाहिए । उसको संशोधित कर दीजिए, दलित टोला कर दीजिए अब वह हरिजन टोला नहीं रहेगा ।

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

श्री सउद आलम : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के भोलमारा पंचायत अन्तर्गत चांदमनी चौक से उत्तर बस्ता जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क नदी कटाव के जद में है । मैं सरकार से उक्त सड़क को बचाने हेतु कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–बाराचट्टी के पंचायत रोही के ग्राम–दरवार में कृषि विभाग की भूमि पर कृषि अनुसंधान भवन का निर्माण जारी है । इस भवन के निर्माण में संवेदक द्वारा गुणवत्ता में घोर मनमानी की गयी है । मैं सदन से यथाशीघ्र जाँच कर कारवायी की मांग करती हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 2010 से ही नियुक्त किसान सलाहकारों को मात्र 11,440 रुपये मानदेय मिलता है । किसान सलाहकारों की योग्यता और कार्यों को देखते हुए उन्हें जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के पद पर बहाल कर मानदेय 30,000 रुपये प्रति माह देने की माँग करता हूँ ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज नगर के वार्ड 11–12 में नल–जल योजना का बिना कार्य कराए 1 करोड़ 11 लाख का भुगतान कर गबन किया गया है । मैं समस्त विधानसभा में पूर्ण हो चुकी योजनाओं की सरकार से उच्चस्तरीय जाँच करा दोषियों पर कारवाई कीं माँग करती हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सीवान के ठेपहा पंचायत के खाता–226, खेसरा–2894, रकवा–चार विगहा चौदह कट्टा गैरमजरूआ भूमि पर जहां नौजवान

विभिन्न खेलों को खेलते हैं । उसपर बन रहे मनरेगा द्वारा खेल मैदान को दूसरे जगह बनाने तथा उक्त स्थल पर खेल स्टेडियम बनाने का मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल महाजाम से अस्पताल, विद्यालय, दुकानें प्रभावित हैं। फुटपाथ व छोटे दुकानदार समेत अरवल बाजार के दुकानदारों की कमाई बंद है। 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक भारी वाहनों के लिए नो इंट्री लगाने, दुकानदारों के कर्ज माफ करने व मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा अर्न्तगत तेघड़ा प्रखंड के पंचायत गौड़ा–2 के वार्ड नं0–7 में अवस्थित पंचायत सरकार भवन में एक भव्य सभागार का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अन्तर्गत ग्राम–भेलवाड़ा (सम्पतचक) मुसहरी टोला उसी गांव के एक जाति विशेष के दबंगों द्वारा होली के रंग– अबीर पराने का बहाना बनाकर उनके घरों में लूट–पाट, बिजली के मीटर तोड़ने, चापाकल तोड़ डालने तथा महिमा–पुरुष की पिटाई की गई । मुकदमा के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है । अतः सदन के माध्यम से करवाई की मांग करता हूं।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार से बाहर किसी भी तरह के मजदूर की मृत्यु होने पर शव को घर तक जाने के लिए 10 हजार की आर्थिक सहायता मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति की व्यवस्था तथा विधवा महिला को 5 लाख रूपया अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त करवाने की सदन से मैं मांग करता हूँ ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखण्ड के पुनसिया–इंग्लिश मोड़ मुख्य मार्ग अजीतनगर पहाड़ से नहर होते हुए उपरामा हाई–स्कूल तक लगभग तीन किलोमीटर सड़क कच्ची है । चार पंचायतों के लोगों के आवागमन का यह महत्वपूर्ण मार्ग है । अतः प्राथमिकता के आधार पर सड़क के पक्कीकरण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत दुल्हिनबाजार चौक पर दिनांक–05.03.2025 की रात 9 बजे दो वाहन BR01PG3106 और BR01PD8353 अनियंत्रित होकर गुजरी । हरपुरा गाँव के निवासी विनीत कुमार द्वारा टोकने पर उसमें सवार सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों ने विनीत के साथ अपमानजनक व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट की । दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण यहाँ के छात्र/छात्राओं को 10+2 के बाद उच्चस्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य शहर जाना पड़ता है । सदन के माध्यम से केवटी में डिग्री कॉलेज स्थापना करने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री चंद्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, पान जाति की उपाधि तांति–ततवा को अति–पिछड़ा से विलोपित कर संविधान की नौवीं सूची में डालने का आग्रह केन्द्र सरकार से करते हुए उनको मौलिक अधिकार पान जाति की सुविधा मुहैया करवाने की मांग बिहार सरकार से करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर से सबौर तक प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन के मार्ग का विस्तार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल जमसी होते हुए गोराडीह तक किया जाय।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पंचायत क्षेत्र और प्रखंड स्तर पर अस्पतालों के नये भवन बने हैं । लेकिन उसमें ए0एन0एम0, पेथोलोजिस्ट, डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टर से लेकर सभी तरह के स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली, दवा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करता हूं।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जातीय गणना में जातियों की संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति का 22 प्रतिशत, अति–पिछड़ी का 25 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति का 18 प्रतिशत दिया गया आरक्षण रोक दिया गया है। विधान मंडल तथा संसद में फिर से पास कराकर संविधान की नवीं अनुसूचि में जोड़वाते हुए आरक्षण देने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आधुनिक समाज में महिलाओं द्वारा पुरुषों पर बढ़ रहे अत्याचार जिसमें पुरुषों की जान तक जा रही है तथा झूठे केस मुकदमा किये जा रहे है। अतः सदन के माध्यम से समाज में संतुलन बनाने हेतु महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग के गठन की सरकार से माँग करती हूँ ।

श्री भरत बिंद : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अन्तर्गत भभुआ प्रखण्ड के ग्राम सैयदरा एवं ममहान के बीच कुहिरा नदी पर पुल नहीं होने के कारण दर्जनों गाँव के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है । अतः उक्त नदी पर पुल निर्माण शीघ्र कराने की मांग सरकार से करता है ।

टर्न–11/यानपति/20.03.2025

श्री शिवप्रकाश रंजन : अध्यक्ष महोदय, मजहरूल हक विश्वविद्यालय के कुलसचिव कामेश कुमार पर अनेक वित्तीय और अकादमिक गबन के अरोप हैं । कुलसचिव के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है और यह कार्यकाल भी आठ माह पूर्व समाप्त हो चुका है । कामेश कुमार के दोनों काल के भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच व कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत टी0एस0 कॉलेज, हिसुआ मगध विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय की सभी अर्हताओं को पूरी करता है, अतएव नवादा जिला के उन्नत शैक्षणिक स्तर हेतु छात्र–छात्राओं एवं जनता के हित में टी0एस0 कॉलेज में मगध विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय खोलने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री विजय कुमार : राज्य के व्यवहार न्यायालयों में नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय श्रेणी के कर्मचारियों को न तो प्रोन्नति दी गई है, न ही प्रोन्नति देने के लिए पदों का सृजन किया गया है । आश्रितों को शत–प्रतिशत अनुकम्पा का लाभ नहीं मिलता है ।

प्रोन्नति एवं अनुकम्पा का लाभ दिलाने की मांग करता हूं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत स्थित रेलवे ढाला नंबर–16 के पास ओवरब्रिज/अंडरपास नहीं रहने के कारण राहगीर घंटों जाम में फंसे रहते हैं ।

अतएव दिघवारा नगर पंचायत में जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु उक्त वर्णित स्थल पर ओवरब्रिज/अंडरपास का निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी अनुमंडल में उच्च शिक्षा के लिए एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है । जिससे छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है । मैं डिग्री कॉलेज खोलने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत अत्क्रमित उच्च विद्यालय में स्थायी रात्रि प्रहरी सहायक की नियुक्ति तथा अंगीभूत महाविद्यालय एवं विद्यालय में सेवानिवृत्त पश्चात् खाली पदों पर नियुक्ति/मृत्युपरांत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा नवसृजित विद्यालयों को भवन–भूमि उपलब्ध कर स्थायी करना ।

उपरोक्त सभी मांगों हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा और अलीगंज प्रखंड हैं । अलीगंज प्रखंड से जमुई जिला मुख्यालय की दूरी 55 कि0मी0 है । उसी प्रकार सिकन्दरा से 35 कि0मी0 की दूरी पर है । रजिस्ट्री कचहरी मुख्यालय जमुई में है जो काफी दूर पड़ता है ।

अतः रजिस्ट्री कचहरी सिकन्दरा में बनवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड मुख्यालय में एक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक आवासीय विद्यालय की स्थापना करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री रामविशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के 50 प्रतिशत ही किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध हुआ है, 50 प्रतिशत अभी भी किसानों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध नहीं हुआ है ।

अतः मैं शेष किसानों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

डॉ0 शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार से आपातकालीन मरीज बड़ी उम्मीद से पटना एम्स, आई0जी0आई0एम0एस0, पी0एम0सी0एच0 एवं आई0जी0आई0सी0 जैसे बड़े अस्पताल आते हैं, बेड खाली नहीं है का बहाना बनाकर भर्ती नहीं किया जाता है । ससमय भर्ती नहीं होने से अधिकांश मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ देता है ।

अतः मरीज की भर्ती सुनिश्चित करने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग में भर्ती नियमावली में संविदा पर कार्यरत कर्मीगण को परीक्षा अधिमानता देने एवं निगमों में कार्यरत कर्मियों को अनुभव के आधार पर अधिमानता तथा एम0बी0ए0/पी0जी0डी0एम0 डिग्रीप्राप्त कर्मियों को अधिमानता एवं बी0पी0एस0सी0 को 19 पदों पर नियमित नियुक्ति एवं पूर्व से कार्यरत कर्मियों अधिमानता की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री की मॉरीशश यात्रा से बिहार का मखाना देश–दुनिया में सुपर फूड के रूप में प्रसिद्ध हुआ है । लोकसभा अध्यक्ष जी ने लोकसभा कैंटीन में मखाना को स्नैक्स व्यंजन में सम्मिलित किया है । बिहार विधान सभा कैंटीन के व्यंजन की सूची में मखाना को शामिल करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा बॉलीवुड एवं राज्य के बाहर के कलाकारों को मनोरंजन के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, जबकि राज्य के प्रतिभावान कलाकारों को न उचित सम्मान, न उचित राशि दी जाती है ।

राज्य के अंदर प्रतिभावान कलाकारों को उचित सम्मान व राशि देने की मांग करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न गांवों से अनुमंडल कार्यालय की दूरी लगभग 65 कि0मी0 होने के कारण प्रशासनिक कार्य

में आम जनता को परेशानी होती है, कटोरिया नवसृजित अनुमंडल कार्यालय के लिए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भी मापदंड को पूरा करती है ।

अतः कटोरिया में अनुमंडल कार्यालय बनाने की मांग करती हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, खरीक सिंह कुण्ड का दर्जनों परिवार कोशी कटाव से बेघर हो गये हैं । कटाव से बचाव हेतु कटाव निरोधी कार्य शुरू हुआ है । 500 मीटर अपस्ट्रीम में और काम कराने की जरूरत है । पीड़ित को मुआवजा, आवास देने एवं अपस्ट्रीम में कटाव निरोधी कार्य कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–12/अंजली/20.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की माँग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगाः–

भारतीय जनता पार्टी	– 59 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 57 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)	– 08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰)	– 02 मिनट
सी0पी0आई0	– 02 मिनट
ए0आई0एमआई0एम0	– 01 मिनट
निर्दलीय	– 01 मिनट

....

कुल – 180 मिनट

....

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 20035,80,00,000/– (बीस हजार पैंतीस करोड़ अस्सी लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अखतरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र एवं श्री महबूब आलम से स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण मांग पर प्रतीक कटौती प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से अनुदान मांग के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं इन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं ।

सम्पूर्ण मांग पर प्राप्त प्रतीक कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा का कटौती प्रस्ताव प्रथम है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–173 (6) के प्रथम परन्तुक के तहत मितव्ययिता के आधार पर दिये गये कटौती प्रस्ताव को अग्रता दी जाती है ।

अतः माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

पार्टी ने आपको कोई समय नहीं दिया है, इसलिए केवल आप पुट कीजिएगा, भाषण नहीं दीजिएगा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष–2211, उप मुख्य शीर्ष–00 के लिये 2872,43,82,000/– रुपये की मांग 5,00,00,000/– से घटायी जाय ।

मितव्ययिता पर विचार–विमर्श करने के लिए ।

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसीलिए किया है क्योंकि कार्यालय व्यय में जो वास्तविक खर्च 2023–2024 में 8 लाख 7 हजार 708 रुपए हुए थे उसे 2025–2026 में बढ़ाकर 80 लाख कर दिया गया है । इस पूरे उप मुख्य शीर्ष में

इस तरह की बढ़ोत्तरी है । महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पेश करने का समय दिया है इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह अपना पक्ष रखें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, एक व्यवस्था या एक सूचना चाहते हैं । हम लगातार देख रहे हैं कि माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी पिछले दिनों विभिन्न विभागों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव देते रहे हैं । हमने देखा है लेकिन इतनी राशि की कटौती की जाय, इसमें ये हमेशा अलग–अलग राशि का उल्लेख करते हैं किसी में 5 करोड़ भी बोलते हैं, किसी में 5 लाख भी बोलते हैं आज उन्होंने 5 करोड़ बोला है तो ये संख्या क्या कोई लॉटरी से निकालते हैं या संख्या इंगित करने का कोई औचित्य होता है ? हम आपके माध्यम से यह सिर्फ समझना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : नहीं, अब इस पर डिबेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा । अलग से बैठ कर बात करेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : ठीक है महोदय, ।

अध्यक्ष : अजय बाबू बोलिए । 14 मिनट का समय आपके पास है ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग एवं आपदा विभाग के अनुदान मांग पर होने वाले वाद–विवाद में भाग लेने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं इस विभाग के अनुदान मांगों के विरुद्ध कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, जब देश आजाद हुआ तो सीमित संसाधनों में कांग्रेस की सरकार ने देश के लिए स्वास्थ्य सेवा की नींव रखी, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो यह सरकार का ही मामला है, चाहे कानूनी मामला हो, स्वास्थ्य मामला हो, शिक्षा का मामला हो या सीधे–सीधे सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो ।

महोदय, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और इसके बजट प्रबंधन को ठीक करने की कोई गारंटी नहीं है । अगर गारंटी होती तो फिर विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता ही क्यों और यह विभाग 20 वर्षों में अधिक एन0डी0ए0 सरकार के भाजपा के ही जिम्मे रहा है । इस सरकार में लगातार 20 वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दिनों–दिन खराब होती जा रही है । स्वास्थ्य मंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है लेकिन उनके वक्तव्य से मैं सहमत नहीं हूं कि डब्लू0एच0ओ0 के मानक पर मीडिया में आपका जो बयान है कि 1 लाख 19 हजार डॉक्टर हमारे प्रदेश में मौजूद हैं मैं इससे सहमत नहीं हूं । महोदय, हम सभी अवगत हैं कि बिहार सरकार का जितना भी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज

हॉस्पिटल या चिकित्सा केंद्र है कहीं भी पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं हैं । इस सरकार ने सदन में भी स्वीकार किया है कि हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की भारी कमी है । राज्य सरकार के डेटा के अनुसार चिकित्सक के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अनुमंडल अस्पताल हो, जिला का अस्पताल हो, वहां मानक के अनुरूप चिकित्सक नहीं हैं, तकनीशियन नहीं हैं, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग मूल कोटि के 4480 पद हैं और 3 हजार पदों में प्रोन्नति होनी है वह भी सरकार नहीं कर रही है । हद तो तब हो गई जब इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में सृजित पदों का 40 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी है और तो और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ छपरा और समस्तीपुर में, तो वहां जो सृजित पद हैं उसमें 95 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी है । समस्तीपुर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी इसके गवाह होंगे और उनको भी इस बात की तकलीफ होती होगी कि 95 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं और उनके जिले में रिक्त पड़े हैं । राज्य के मेडिकल कॉलेज में 2017 के सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी तकनीकी फार्मासिस्ट आदि की बहाली नहीं हो पा रही है । पी0एम0सी0एच0 हो, आई0जी0आई0एम0एस0 हो, एन0एम0सी0एच0 हो, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान हो, यह सब जानते हैं सब क्षेत्र से वेंटिलेटर पर मरीज आता है तो जब हमलोग अप्रोच करते हैं, सभी सदस्य अप्रोच करते हैं तो कहा जाता है कि अगर वह होश में नहीं है तो आप मत भेजिए, किसी प्राइवेट संस्थान में उसको लगा दीजिए चूंकि हमारे यहां आई0सी0यू0 की कमी है । जो भी हमारे पास बेड हो पी0एम0सी0एच0 में, आई0जी0आई0एम0एस0 में, एन0एम0सी0एच0 में, एल0एन0जी0पी0 में जो राजधानी के अस्पताल हैं उस बेड के मुताबिक 20 प्रतिशत आई0सी0यू0 बेड भी हमारे पास होना चाहिए जो नहीं है, यह सुझाव के रूप में मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष आपके माध्यम से रख रहा हूं । कई अनुमंडलों में तो अस्पताल का उद्घाटन हो गया, मेरे ही जिले खड़गपुर में अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन हो गया, सुविधा नहीं है । महोदय, जब भी राजधानी के मानक अस्पतालों में कोई गंभीर बीमारी का इलाज कराने आता है तो उसे जो भी टेस्ट कराने की जरूरत होती है तो उसे लाइन में खड़ा हो जाना पड़ता है कि 5 महीने बाद आपका टेस्ट होगा, दो महीने बाद आपका टेस्ट होगा, ये–ये दिक्कते हैं और प्राइवेट अस्पताल की चर्चा, प्राइवेट डॉक्टरों की चर्चा माननीय मंत्री जी ने डब्लू0एच0ओ0 में उसको भी गिन लिया है यह तो बड़ा हास्यास्पद है बिहार जैसे गरीब राज्य में ।

(क्रमशः)

(क्रमशः)

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, इस सदन में हम सभी साथी चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, बैठे हुए हैं या पूर्व के सदस्य हों, स्थिति तब और भ्रामक हो जाती है जब हमारे पूर्व के सदस्य या वर्तमान सदस्य अगर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों तो बिहार में उसके इलाज का अगर इंतजाम नहीं है तो वह राज्य से बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं और वहां से लौटने के बाद विधान सभा सचिवालय कहता है कि आप प्रोफेसर रैंक के डॉक्टर से रेफर होकर गये थे या नहीं गये थे । आपके माध्यम से मैं सरकार के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि 90 फीसदी प्रोफेसर के पद खाली हैं । अब किससे रेफर कराकर हमारे सदन के सदस्य जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए, इसकी चिंता को सरकार को होनी चाहिए । गरीब से लेकर के और इस सदन में बैठे हुए लोग सभी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति चिंतित हैं और यह चिंता सरकार को करनी चाहिए । 20 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता किसी सरकार के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए । जो राज्य के अंतर्गत का मामला है मैंने कहा कि तीन चीजें राज्य के अंतर्गत आती है वह शिक्षा है, स्वास्थ्य है और कानून व्यवस्था है । स्वास्थ्य 20 साल के भीतर भी नहीं सुधर पाया तो यह चिंता का विषय है । महोदय, साथ ही साथ हमलोग गाँव से जुडे हुए लोग हैं और मामला कृषि का भी है । संयोग से माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष : अब आपका दो मिनट का समय बचा हुआ है ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, सिर्फ दो ही मिनट ।

अध्यक्ष : हां, दो–ढाई मिनट ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, कृषि वाला मामला गंभीर है ।

अध्यक्ष : जल्दी–जल्दी संक्षेप में पूरी बात कह दीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, कृषि के मामले में हमारी सरकार ने जो काम, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया है, जिसका समर्थन माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी करेंगे । हरित क्रांति–1 और हरित क्रांति–2 दोनों कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री के रिजिम में हुआ है । एक इंदिरा जी के समय में हुआ है और एक हैदराबाद में मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ है और इतना ही नहीं मैक्सिको और पेरू से, मैक्सिको से गेहूं और पेरू से धान का बीज मंगाया गया । स्वामीनाथन साहब थे वे हमारे ब्रिडर थे, उन्होंने काम किया और क्या कहते हैं अपने लिए, देशवासियों के लिए खाद्यान की कमी नहीं रही ? आत्मनिर्भर हो गया भारत । हमारी पार्टी हमेशा आत्मनिर्भर कराने की पक्षधर है । आज हम आत्मनिर्भर नहीं है । कई

जिलों से आंकड़ा प्रस्तुत होता है, सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी बढ़ गई लेकिन जिले के एग्रीकल्चर ऑफिसर जब कहते हैं, वे कहां से आंकड़ा देते हैं ? एक वर्ग मीटर में धान की या गेहूं की कटाई करके और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको एक हेक्टेयर का आंकड़ा मानते हैं । अगर सरकारी आंकड़े पर भी हम चलें तो सरकार के विश्वविद्यालय भी हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज भी हैं और कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इन्होंने जो कांग्रेस के जमाने की बात कही और उसकी तस्दीक करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री का नाम लिया । महोदय, अभी पिछले दिनों जब सिंचाई यानी जल संसाधन विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है आप उस समय उस दिन चर्चा नहीं किए थे । हमने ही चर्चा की थी कि 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आई थी, उससे सिंचाई के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया था ? लेकिन महोदय, मैं हरित क्रांति के बाद जब सिंचाई के स्वरूप में परिवर्तन की चर्चा कर रहा था तो मुझे क्या पता था कि कांग्रेसियों के स्वरूप में ही परिवर्तन हो गया है ?

अध्यक्ष : आप ज्यादा जानते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वह परिवर्तन हमने इस रूप में देखा कि जब मैं उसकी चर्चा कर रहा था तो इन्हीं के वरिष्ठतम नेताओं में से एक विजय शंकर दूबे जी वहाँ से आपत्ति कर रहे थे । अब समझिए, सिंचाई के स्वरूप में परिवर्तन की मैं चर्चा कर रहा था और यहाँ सदन में देखा कि सिंचाई के स्वरूप से ज्यादा परिवर्तन कांग्रेसियों के स्वरूप में हो गया है, जो अपनी बात भी नहीं समझ सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिये, माननीय सदस्य ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मैं यह कह रहा था ।

अध्यक्ष : एक मिनट और बचा है, आपके पास ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, हमारा समय...

अध्यक्ष : इसीलिए आपका समय बढ़ा दिया है ।

श्री अजय कुमार सिंह : जी । सरकार के विश्वविद्यालय है, सरकार के एग्रीकल्चर कॉलेज हैं । सरकार का कृषि विज्ञान केंद्र है, जब इनके उत्पादन में जो खर्च होता है और इनके उत्पादक का जो मूल्य बाजार में होता है । उसमें, इनका उत्पादन करने में जो खर्च हुआ वही अधिक हो जाता है । 2011 के सर्वे के मुताबिक इस

देश में 93 प्रतिशत छोटे किसान थे, 6 प्रतिशत मझौले किसान थे और 01 प्रतिशत बड़ा किसान था । आज 2025 है, छोटे किसानों की संख्या बढ़ी है तो आप उन छोटे किसानों के आमदनी बढ़ने की बात कैसे कर सकते हैं, जब आपके फॉर्महाउस के उत्पादन का खर्च, उत्पादक मूल्य से कम हो जाता है । मैं तो साईंस एडवाइजरी कमेटी का मुंगेर में मेम्बर था ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : जी, तुरंत समाप्त करता हूं । क्योंकि कृषि का रोड मैप एक महत्वपूर्ण रोड मैप है । इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि कृषि में जोन–1, जोन–2 और जोन–3 या जो भी क्षेत्र चिन्हित किया गया है । उसमें किस क्षेत्र में किस जमीन का पी0एच0 वैल्यू क्या है ? कौन–कौन सी जमीन का पी0एच0 वैल्यू अधिक होगा, जिसमें उसकी फसल अच्छी होगी । न्यूट्रलाइज पी0एच0 वैल्यू पर कौन–सी फसल हो सकती है । महोदय, इसका कहीं भी जिक्र कृषि के रोड मैप में नहीं है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री विनोद नारायण झा । 14 से 15 मिनट के बीच में आपको अपनी बात समाप्त करनी है ।

श्री विनाद नारायण झा : महोदय, मेरी पार्टी की इच्छा है कि मैं उस समय से थोड़ा कम ही समय में बोलूं ताकि आगे समय मिल जाए ।

अध्यक्ष : और कम कर दीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा : हां, सचेतक महोदय ने बोला है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । कल बिजेन्द्र बाबू बिजली विभाग पर बोल रहे थे।

अध्यक्ष : माईक थोड़ा ऊंचा करके बोलिये ।

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, कल आदरणीय बिजेन्द्र बाबू बिजली विभाग पर बोल रहे थे । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इसलिए बिजली इतनी करने में सुविधा हुई । अच्छा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, मालूम भी हैं । लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं, किसी रूप में काम किया है, वह जानते हैं भले ही वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं लेकिन बिहार के हर विषय पर हर विभाग के बारे में उनकी जो पैनी दृष्टि हैं, वह अपने आप में असाधारण है और एक–एक छोटी चीजों की जो उनकी समझ हैं, यह कोई सामान्य राजनेता

नहीं कर सकता । यह कोई स्टेटमैन ही कर सकता है, चाहे वह बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, कृषि का सवाल हो उन्होंने किया । इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिहार ने असाधारण तरक्की की है, पिछले 19 सालों में, 20 सालों में । यह सौभाग्य है कि लम्बे समय से एक सक्षम मंत्री के रूप में श्री मंगल पाण्डे जी, उस विभाग को देख रहे हैं और मंगल पाण्डे जी भी एक ऐसे मंत्री हैं जब 2–3 साल ही बीता था, हम भी उस समय स्वयं मंत्री थे तो मुझे लगता था कि सारी बारिकियों को यदि कोई मंत्री समझ रहा है अपने विभाग की तो उसमें एक मंगल पाण्डे जी भी हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गयी और लगातार स्वास्थ्य विभाग में मंत्री हैं । मैं तो अब इसकी भी गणना करने के लिए बोलूंगा कि कोई बिहार में आजादी के बाद कोई मंत्री थे ? जो इतने दिनों तक स्वास्थ्य को इतने बढ़िया से चलाया और एक आदमी को इतनी जिम्मेवारी मिली क्या ? महोदय, यह इनकी योग्यता और क्षमता की ही उपलब्धि है कि लगातार उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया । मेरे विरोधी दल खासकर राजद के मित्रों को बहुत बुरा लगता है कि जब हम कहते हैं, हमारे साथी कहते हैं के 2005 से पहले ऐसी हालात थी ? 20 साल में क्या हुआ ? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विकास की कोई निश्चित रेखा नहीं होती । विकास या तो दुनिया में कुछ विकास हो तो उसकी हम नकल कर सकते हैं या फिर विकास की जो पिछली परिस्थितियां हैं उससे हम कम्पैरिजन कर सकते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / अभिनीत / 20.03.2025

..क्रमशः..

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, कोई निश्चित अवधारणा नहीं है कि विकास किसको कहते हैं । कितने पर विकास रूक गया, विकास कहां तक जायेगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर इस पर शोध होते रहते हैं, निरंतर उस पर प्रयोग होते रहते हैं । पिछले दिनों जो परिस्थितियां बनीं इस राज्य में जब 15 साल उनकी सरकार थी, जो परिस्थितियां बनीं उसे मैं आज दोहराने नहीं जाउंगा लेकिन यह परिस्थिति लोगों को याद है कि किस तरह धीरे–धीरे सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गयीं । 1990 का कार्यकाल एक बेहतर कार्यकाल था । बिहार में बाबू श्रीकृष्ण के 1961 मे देहावसान के बाद 1990 के बीच में करीब 22, 23, 24 मुख्यमंत्री बदल गये । 22–23 हो गये थे, किसी को मौका नहीं मिला था । कोई साल भर, कोई तीन साल, कोई चार साल, एक मात्र व्यक्ति थे जिन्हें लंबा कार्यकाल मिला । विकास की नई गाथाएं लिखी जा सकती थी और उसी समय में 1990 का जो दशक है वह वैश्वीकरण का दशक था । वैश्वीकरण में दुनिया की इकोनॉमी ओपेन हो रही थी । दुनिया भर में एक–दूसरे से कंप्टीशन की बातें

हो रही थी । आयरन कर्टेन जो इकोनॉमिक्स में लगा हुआ था वह छट गया था और उस मौका को गंवा दिया । गंवा ही नहीं दिया नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने उनकी जो विजन थी वह विकास विरोधी थी, विकास से कोई लेना'–देना नहीं था 15 वर्षों में । इसका असर सभी विभागों पर हुआ । सिर्फ एक विभाग पर नहीं सभी विभागों पर हुआ । मैं यह नहीं कहता कि उनको जो सरकार मिली वह सब कुछ दुरूस्त मिला । कठिनाइयां थी लेकिन कुछ चल रहा था । कम हुआ, 1961 के बाद डिटोरिएशन हुआ । यह भी ध्यान है कि दुनिया में, भारत में बेस्ट गवर्नमेंट का अवॉर्ड बाबू श्रीकृष्ण के समय में बिहार को मिल चुका था लेकिन 1961 के बाद चूंकि डिटोरिएशन प्रारंभ हुआ तो उसकी गति धीमी थी लेकिन 1990 के बाद जो गति आयी डिटोरिएशन की तो राज्य के सारे सिस्टम ध्वस्त होते चले गये । सारी व्यवस्थाएं समाप्त होती चली गयीं । सिर्फ वोट के लिए कहानियां गढ़ी जाने लगीं और बिहार सबसे खराब राज्यों की स्थिति में आ गया । तरह–तरह की रिपोर्ट आने लगीं । मैं विस्तार में जाउंगा तो समय बढ़ जायेगा, इसलिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं है । बुरा मुझे तब लगा जब पिछले दिनों राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, वे उस 15 साल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे । मैं कह देना चाहता हूं कि बिहार फिर उस काल को दोहराने की जब सोचता है तो सिहर उठता है । वह 15 साल की जो हालत थी लोग सिहर जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं । क्या ऐसी ही सरकार की कल्पना है महागठबंधन के पास, क्या ऐसी सरकार चाहते हैं तेजस्वी यादव जिसमें लोगों का अपहरण हो, एक जात दूसरे जात की हत्या कर दें । छोड़िए बाकी विभागों की बात मैं नहीं करता, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करता हूं । महोदय, हालत यह थी कि एक–एक करके लोगों ने अस्पताल जाना छोड़ दिया । जिस पी0एम0सी0एच0 में अस्पताल हुआ करते थे, जिसमें लोग रहा करते थे, जो आजादी के पहले बनी थी..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें ।

श्री विनोद नारायण झा : उस पी0एम0सी0एच0 में आदमी के बजाय मवेशी और कुत्ते रहने लगे थे उनकी बेडों पर, यह हालत हो गयी थी । 2005 में जो मौका मिला और मैं विस्तार में नहीं जाउंगा । क्या कारण था कि नीतीश कुमार को तीन साल में आपको छोड़ना पड़ा । जार्ज फर्नांडीश को छोड़ना पड़ा । क्या कारण था कि शरद यादव को छोड़ना पड़ा और विस्तार में नहीं जाइये । मैं बताना चाहता हूं लेकिन मैं कहता हूं महोदय, यह हालत हो गयी थी । एक ही प्रमाण काफी है कि जब मौका मिला नीतीश कुमार जी को और एनडीए को तो एक बड़ी चुनौती थी । चुनौती यह थी महोदय, सुशील मोदी हमारे नेता थे और नीतीश कुमार जी

का नेतृत्व था और हम सबलोग एम0एल0ए0 होकर यहां आये थे । बड़ी चुनौती थी, एक जोड़ी और हम तो भूल ही जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन है और यह वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है । बिहार के लिए परफेक्ट गठबंधन है जिसने कुशासन को झेला । हम तो भूल ही जाते हैं कि कभी हमलोग एक–दूसरे से अलग भी हुए । लगातार लगता रहता है कि 20 सालों से साथ हैं । परिस्थितियां थी राज्य की, राज्य की जनता को मौलिक और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, उपलब्ध सुविधाओं की गुंणवत्ता में कैसे सुधार हो और योजनाओं के समय पर गहन समीक्षा और अनुश्रवण के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दिखने लगा । चंद्र मोहन राय जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, मैं विधायक के रूप में रहता था । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब आंकड़े आयें तो महीने में 39 लोग ही अस्पताल जाते थे । डॉक्टर जिनकी पोस्टिंग थी उस इलाके के लोगों को पता नहीं था वे कहीं और प्रैक्टिस करते थे, मैं विस्तार में नहीं जाउंगा लेकिन आज जब मंगल पाण्डे जी मंत्री हैं तो प्रति महीने 11 हजार मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं, यह इसका प्रमाण है । अजय जी ने डॉक्टर की कमी बताई । यह सच्चाई है । डॉक्टर की कमी बहुत है, डॉक्टर की कमी रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं डॉक्टरों की वह डॉक्टर गांव में रहना चाहता है कि नहीं और डॉक्टरों का अभाव था । महोदय, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं डबल इंजन की सरकार बनी, नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हुए और नरेंद्र मोदी जी तो कहते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी तो और विस्तार देते हैं और वह कहते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की मान्यता है कि स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत है और स्वच्छता को फिटनेस और पोषण से भी वे जोड़ते हैं, तो एक सहयोग मिला । पिछले सात–आठ साल से जो सहयोग मिला है उसका परिणाम है कितने मेडिकल कॉलेज खोले गये बिहार में, आजादी के 70 साल, 75 साल हो गये कितने मेडिकल कॉलेज खोले गये । आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना में खुला था । दरभंगा मेडिकल कॉलेज महाराज दरभंगा ने खोला था । 6 मेडिकल कॉलेज थे 2005 से पहले और उसमें चार आपने अधिग्रहण किया था, तो थे कितने, खोला कितने, धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार और मंगल पाण्डे जी के स्वास्थ्य विभाग के काम को और एनडीए गठबंधन को कि आज सरकारी स्तर पर 16 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं और तीन–चार प्रक्रिया में हैं । मेडिकल कॉलेज बनेंगे, डेंटल कॉलेज बनेंगे तभी तो इलाज होगा, तभी तो डॉक्टर बढ़ेंगे और हर चीजों में उसके लिए विकास के मानक को तय किया गया और इतना ही नहीं पुराने मेडिकल कॉलेज को छोड़ा नहीं गया । आपका सीना 56 इंच का होगा जब आपको पता लगेगा आज से साल भर, दो साल बाद जब पटना मेडिकल कॉलेज 5462 बेड का वह मेडिकल कॉलेज हो जायेगा, जो संपूर्ण, मुझे तो आंकड़े ध्यान में नहीं हैं, संपूर्ण एशिया में

सबसे बड़ा अस्पताल बिहार की धरती पर होगा । उतना ही नहीं एम्स का एक मानक है और एम्स के उस मानक पर पटना में एम्स है और जब भारत के प्रधानमंत्री ने दूसरा दिया तो दरभंगा में और बिहार सरकार ने 190 एकड़ जमीन स्थानांतरित कर दी है उनको और आने वाले दिनों में वह उत्तर बिहार ही नहीं नेपाल से लेकर बाकी चीजों के लिए एक असाधारण उपलब्धि होगी ।

उपाध्यक्ष : विनोद जी, आपने कहा संक्षेप करने वाले हैं । आपने कहा कि कम बोलने वाले हैं ।

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, बस शॉर्ट कर देते हैं । हर मानक पर देखेंगे 2005 के यदि मातृ मृत्यु दर को देखेंगे तो लोगों की आंखें खुल जायेंगी । दुनिया बदल रही थी, कैसे हम करते थे, कैसे प्रसव की बातें होती थी, गांव में होती थी, बड़ी चुनौती थी बिहार सरकार के सामने कि कैसे इसको संस्थागत किया जाय और काम बने । योजनाएं बनीं, 2 लाख आशा कार्यकताओं के प्रयास से शुरू हुआ और शुरू हुआ तो जो 30 प्रतिशत से भी कम संस्थागत प्रसव था बिहार में, 23 प्रतिशत था, बड़े लोग जाते थे हॉस्पिटलों में वह आज 90 प्रतिशत संस्थागत प्रसव...

..क्रमशः..

टर्न–15 / हेमन्त / 20.03.2025

श्री विनोद नारायण झा : (क्रमशः) : इसी 19 साल की सरकार में होना शुरू हुआ है और आम लोग भी संस्थागत प्रसव के लिए माताएं जाती हैं अस्पतालों में, वहां होता है । इतना ही नहीं, मातृ मृत्यु दर क्या थी 332, आज मातृ मृत्यु दर घटाकर मंगल पाण्डे की सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने 149 पर लाया है । ऐसे ही शिशु मृत्यु दर हजार पर गिरती थी, 61 थी, 29 थी, कहने के लिए बहुत है और सरकार और भी, अंतिम बात कहकर मैं बठ जाऊंगा । लोगों को कैसे सहयोग हो, असाध्य रोगों के लिए बिहार में नरेन्द्र मोदी खड़े हैं, आयुष्मान खड़ा है और अभी तक 1 करोड़ 50 लाख लोग, परिवार आयुष्मान में पंजीकृत हो चुके हैं, कार्डधारी हो चुके हैं जिसमें तीन करोड़ से ज्यादा परिवार लाभान्वित हैं । इसी तरह बिहार सरकार भी पीछे नहीं है । मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष में मंगल जी के नेतृत्व में सिर्फ इस वर्ष 214 करोड़ रूपये गरीबों को बांटे जा चुके हैं, जो इस वर्ष सिर्फ असाध्य रोगों के लिए आया है । इसीलिए बिहार सरकार के विकास की गाथा अनन्त है और यदि किसी को उसका मुकाबला करना है, तो समानांतर नीतियां घोषित करनी पड़ेंगी, कार्यक्रम देने पड़ेंगे । 15 साल का

गुणगान करियेगा, तो बिहार की जनता दोबारा नीचे पहुंचा देगी, जहां आप हैं । इन्हीं बातों के साथ जय हिन्द ।

अध्यक्ष : श्री ललित कुमार यादव । बीस मिनट का समय आपके पास है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं । महोदय, आज विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं ।

आज कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपदा एवं विधान मंडल विभाग की अनुदान मांग सदन में पारित की जानी है । महोदय, स्वास्थ्य विभाग का, हम लोग माननीय मंत्री मंगल पांडे जी को देखते हैं, जितना चमकते हुए, जितना ये स्वस्थ हैं, उतना इनका स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ नहीं है, यह पूरे बिहार की जनता जानती है । मैं कोई मंगल पांडे जी की या स्वास्थ्य विभाग की बुराई करने के लिए इस सदन में नहीं खड़ा हूं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है, उसपर तो इस सदन में आज चर्चा है, तो स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा करनी होगी और सही चित्रण करना होगा । सरकार बड़ा–बड़ा दावा करती है । आज मंगल पांडे जी 20 हजार करोड़ से ज्यादा की मांग लाये हैं, लेकिन पिछले पांच वर्षों का आंकड़ा देखेंगे, तो 60 प्रतिशत से ज्यादा यह खर्च ही नहीं कर पाते हैं और स्वास्थ्य विभाग की जो हालत है, न आपसे छिपी हुई है, न सदन के माननीय सदस्यों से छिपी हुई है । अभी विनोद झा जी, इनके इलाके में गये, तो इनको रावण झा भी कहते हैं, तो वहां चार–चार हत्याएं हो गयी थी और ये कितना भी बोलें, कितना भी ढोल पीट लें, लेकिन ये भी विजय बाबू की तरह ही कांग्रेस से घूमकर, ये पूरे आरएसएस वाले नहीं हैं । ये विजय बाबू की तरह ही घूमकर आये हैं ।

अध्यक्ष : आप कहना चाह रहे हैं कि विनोद जी ने जो कहा है, गलत कहा है । माने कांग्रेस के कारण । क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप जो उसके माने लगाइये, हमें जो लगाना था, हम लगा लिये । महोदय, स्वास्थ्य विभाग का एक ही लक्ष्य है और यह इनका कटिबद्ध है कि बिहार की जनता को हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं । महोदय, आप ठीक कह रहे हैं कि आई0जी0आई0एम0एस0 में हमारी यह संख्या है, पी0एम0सी0एच0 में मेरी यह संख्या है । हम मानते हैं कि पी0एम0सी0एच0 में मरीजों की संख्या बढ़ी है, आई0जी0आई0एम0एस0 में संख्या बढ़ी है । आप उसका विस्तारीकरण भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए । आपको जिम्मेवारी मिली है, जिनको भी जिम्मेवारी मिलेगी, वह निश्चित रूप से वही काम करेंगे, करना चाहिए । महोदय, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग में, आज जो भी

विनोद बाबू बोल रहे थे, हम बहुत उन बातों पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताना चाहते हैं कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में कह रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ी है । आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग का जो खाद्य पदार्थ है, उसके लिए जांच का आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी और बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र में भी और रेफरल में भी संख्या बढ़ी है, लेकिन आपकी यह भी जिम्मेवारी है, खाद्य पदार्थ की जांच करना । महोदय, न इनके पास प्रयोगशाला है, न इनके पास वैज्ञानिक है, न जांच करने वाला कोई है। महोदय, आज कृषि विभाग की भी अनुदान मांग है । महोदय, इतना कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आर्सेनिक या अन्य बीमारी के माध्यम से आज कैंसर जैसे गंभीर रोग हो रहे हैं, तो खाद्य पदार्थ के कारण, स्वास्थ्य विभाग की यह भी जिम्मेवारी है । स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है ? इनके पास कितनी जांच करने की जगह है और कौन–कौन सी जगह जांच करते हैं ।

महोदय, हम विषयवस्तु से, स्वास्थ्य विभाग से अलग होकर आज मनिगाछी भंडारीसो बाणेश्वरी स्थान बहुत प्रसिद्ध वनेश्वरी स्थान है और वहां पर भगवान के सारे आभूषण, मां बाणेश्वरी आभूषण सारा चोरी हो गया है, हजारों की संख्या में लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं । विजय बाबू हैं, हम कहेंगे कि इसको संज्ञान में लेकर दिखवाइये और उस पर कड़ी कार्रवाई करवाइये, जो भी हो इस पर । मां बाणेश्वरी बड़ी आस्था का और श्रद्धा का वह केंद्र है और वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गयी है, काफी लोग आक्रोशित हैं ।

महोदय, स्वास्थ्य विभाग का, इनका जो अभी नीति आयोग का मामला है कि बिहार में पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में आधारभूत संचरना के साथ–साथ सुविधा स्टाफ एवं चिकित्सक की कमी है । महोदय, इनको हम पूरे राज्य का उदाहरण नहीं देना चाहते । एक छोटा–सा उदाहरण हम अपने रेफरल अस्पताल और सी0एच0सी0 या पी0एच0सी0 हमारे मनिगाछी में है, हम उसका उदाहरण देना चाहते हैं । महोदय, अभी विनोद जी कह रहे थे, सरकार अपनी पीठ अपने थपथपाती है कि 2005 से पहले क्या था । हम आपको चुनौती के साथ कहते हैं, आप मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, आप मंगा लीजिए 2005 से पहले रेफरल अस्पताल मनिगाछी में एक–एक विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे । हम नाम गिना देते हैं, राजेश द्विवेदी, सर्जन थे, मनोज कुमार फिजिशियन थे, वहां के प्रभारी, बिंदुनाथ झा, वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और हम आपको डॉक्टर के नाम बता देते हैं । पांच–पांच डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे...

अध्यक्ष : ललित जी, आप जब मुस्कुरा कर बोलते हैं, तो अच्छा बोलते हैं और जब गुस्से में बोलते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है । मुस्कुरा कर बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पांडे जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इन पर गुस्सा कर ही नहीं सकते । पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनके विभाग का जो क्रियाकलाप है और ये जितना चमक रहे हैं, विभाग को चमकाते तो और खुशी होती, और प्रसन्नता होती । महोदय, हम लोग रेफरल अस्पताल मनिगाछी का आपको बता रहे थे । हम लोगों के यहां 18 उप स्वास्थ्य केंद्र केवल एक प्रखंड मनिगाछी में हैं । कहिए तो हम नाम गिना दें । यदि हम अपने वक्तव्य में कोई बात बोल रहे हैं, मंत्री जी चाहें तो जांच करा लेंगे । महोदय, 18 उप स्वास्थ्य केंद्र थे, नजरा, महमदा, जतुका, चक बसावन, बाजिदपुर, सतवार, धूसी, टटुवार, बिहटा, शारदापुर, बहौरवां, कोटमा, बेलही, राघोपुर, जगदीशपुर, पैठान कवई, दहूरा, राजे, महोदय, इस तरह से 18 आपके कार्यकाल से पहले था और सभी जगह उप स्वास्थ्य केंद्र में सप्ताह में डॉक्टर जाते थे । ए0एन0एम0, ड्रेसर रहता था । आपको हम चुनौती देते हैं कि अगर हम कोई बात गलत बोलते हैं, तो आप जांच करा लीजिएगा, अपने जवाब के क्रम में बोलियेगा । आप 2005 के बाद का ढोल पीट रहे हैं । बीस साल से आप सत्ता में हैं, बीस साल से आप सरकार चला रहे हैं और अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं । बिहार की जनता सब देख रही है। आप क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ? आज लोग कहां जा रहे हैं ? आपके लोग दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, आपके लोग प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं और आप अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अलख जगा दिये, जनता जानती है। महोदय, आज हमने 18 उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम बताया, इसमें से 37 पद कुल हैं, आपके 15 से 16 लोग हैं और ये 2005 से पहले क्या सब जगह था । आप पता कर लीजिए, जांच कर लीजिए । डॉक्टर भी सप्ताह में एक बार जाते थे । चार वहां अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दी, पहले से स्वीकृति थी, आपने भवन बनवाया है । भवन तो ठीक है, भवन बनवाया, अच्छी बात है, आपका स्वागत करते हैं, सराहना करते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / धिरेन्द्र / 20.03.2025

...क्रमशः....

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, लेकिन उसका क्या हाल है, पाँच साल, सात साल से भवन बना हुआ है, एक ए॰एन॰एम॰ है, एक जी॰एन॰एम॰ है, एक कम्पाउंडर है, तीन साल से, चार साल से बना हुआ है वहाँ एक डॉक्टर गया है, महोदय, पूरा छत ढह कर गिर रहा है, पूरे दिवार की ईंट गिर रही है, खिड़की ध्वस्त हो गयी, हमलोग सरकार को अनेक बार संज्ञान में दिये हैं महोदय, लेकिन कहीं वह चार वाजिबपुर है, आपको नोआम में है, आपको राघोपुर है इस तरह से चार–पाँच

जगह है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चार साल से भवन बना हुआ है आपका एक ए॰एन॰एम॰ कम्पाउंडर भी नहीं है, ताला भी नहीं खुला है और भवन झर–झर कर गिर रहा है यह आपके स्वास्थ्य विभाग की हालत है, आप जाँच करा लीजिए इसकी, और आप अपने जवाब में बोलियेगा । हम कोई बात आपको गलत, हम आपका कोई बुराई नहीं कर रहे हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप 10 मिनट बोल चुके । आधा समय आप बोल चुके हैं । इतना डिटेल में जाइयेगा तो पूरी बात आपकी नहीं होगी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप यदि एक मिनट लिये हैं तो एक मिनट बढ़ा दीजियेगा। महोदय, हमको समय का ख्याल है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, और हमें कितनी देर अपनी बात को रखना है यह ध्यान है । महोदय, इनका अभी जो रेफरल अस्पताल का हम बताये हैं, जो रेफरल अस्पताल में पाँच डॉक्टर में एक भी नहीं है । हम विधान सभा में भी प्रश्न लाये थे और हम विभाग को भी, बताइयेगा हम आपको पत्र दे देते हैं, विभाग को भी यह प्रश्न रेफरल अस्पताल मनिगाछी का यानी आज जिसमें हजारों पेसेंट रहते थे, आज कुत्ता, बिल्ली वहाँ बैठा हुआ है, आप जाँच करा लीजिये यदि मेरी बात गलत होगी, आप अपने जवाब में, आपके विभाग के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, आप अभी फोन कीजिये कि कुत्ता, बिल्ली वहाँ बैठा हुआ है या नहीं ? एक पेसेंट होगा तो उसका नाम बताइये ? भवन जर्जर है, अस्पताल के टोटल डॉक्टरों के रहने का क्वार्टर है, टोटल आपको सुसज्जित अस्पताल था । एक भी न डॉक्टर है, वहाँ का जो भी इक्यूपमेंट था, स्टेशनरी सब उठाकर कहीं दूसरे बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में ले गया दो साल पहले, आज तक नहीं लौटा है । आप पता कर लीजिये कि क्या मामला है, कैसा मामला है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्या जी, आप नहीं थीं....

अध्यक्ष : ललित जी, आप इधर बोलिये । इधर देखकर बोलिये न ।

श्री ललित कुमार यादव : हमलोग 30 साल से इस सदन के सदस्य हैं । आप थोड़ा सीखिये भी ।

अध्यक्ष : ललित जी, आप इधर देखकर बोलिये न । फिर आप गुस्सा हो रहे हैं । इधर देखिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं आप ही को देख रहा हूँ लेकिन कोई सदस्या बोल रही है तो उनको सिखाना जरूर है....

अध्यक्ष : ललित जी, बैठे–बैठे बोल रही हैं, संज्ञान नहीं लेना है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, नहीं लेना है लेकिन फिर भी हमलोग भी इस सदन के सदस्य हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे बोलने वाले का संज्ञान नहीं लिया जाता है । बोलिये।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय सदस्या बोलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा । हमलोग भी नहीं बोलते हैं । महोदय, एम्स का निर्माण अभी बता रहे थे विनोद झा जी, बड़ा हल्ला बोल रहे हैं । ठीक है भारत सरकार ने एम्स दिया, बिहार सरकार ने जब महागठबंधन की सरकार थी तब दरभंगा में एम्स की जगह फाइनल हुई । हमलोग थे, विजय बाबू थे, विजय बाबू हमलोगों के साथ बेतिया, पश्चिमी चम्पारण में हम प्रभारी मंत्री थे । एक ही गाड़ी पर मुख्यमंत्री जी और विजय बाबू और संजय झा जी बैठे हुए थे । हमलोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि जगह चयन कर रहे हैं कोई न्यायालय में मामला है, हमलोग कहें कि 300 एकड़ जगह हाइवे पर है, फोर लेन पर, एन॰एच॰–27 पर है और लहेरियासराय–दरभंगा के बाईपास पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम यात्रा पर चलते हैं, शायद समाधान यात्रा चल रहा था तो बोलें कि हम आते हैं। हमलोगों ने जगह दिखायी, मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन स्वीकृत किये, तब इन्होंने क्या किया, नाव लेकर भाजपा वाले लोग 20 फीट पानी है, समुंद्र है, इसमें अस्पताल एम्स का निर्माण कैसे होगा, ये लोग 20 दिन तक आंदोलन किये । आज पीठ थप–थपा रहे हैं, एम्स हमने बनवाया है । प्रधानमंत्री जी बाद में आये वहाँ पर शिलान्यास जरूर किये, स्वागत है प्रधानमंत्री जी का लेकिन एक बात जान लीजिये यह महागठबंधन के समय में दरभंगा चयनित हुआ और उसी समय में तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने 400 या 500 करोड़ वहाँ की चहारदीवारी और समतलीकरण के लिए राशि भी आवंटित किया । मंगल पाण्डे जी, आपको स्मरण नहीं होगा, आप डेट बता दीजिये हमलोगों ने, टेंडर का डेट निकल गया था । यदि आप गलत बताइयेगा, हम अब चुनौती के साथ देते हैं, इस सदन से हम इस्तीफा दे देंगे, आप मंत्री से इस्तीफा दीजियेगा ? यदि...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर गुस्सा हो गए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यदि आवंटित नहीं हुआ होगा, टेंडर नहीं हुआ होगा....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर गुस्सा हो रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : तो आप मंत्री से इस्तीफा दीजियेगा । आप इस तरह से यह नकार नहीं सकते हैं । सच्चाई को आप झूठला नहीं सकते हैं । महोदय, आज इनका, नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट है...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ललित जी वरिष्ठ सदस्य हैं, इतने भावनात्मक क्यों होते हैं, सच्चाई कुछ भी हो सरकार इनकी इस्तीफा में जरा भी रूचि नहीं रखती है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यदि मंत्री देंगे चुनौती, जब कोई बोल रहे हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कहाँ कोई बोला है, आप गुस्सा में बोलने लगते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी की भाषा हम समझते हैं, भाषा वे समझते हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हँस कर बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप क्यों बीच में आ जाते हैं, मंत्री जी से हमको सलटने दीजिये । मंत्री जी के भाषा का जवाब हमने दिया है । यदि मंत्री जी को लगे...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय भाग रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम दोनों को समझते हैं, हम इनका सम्मान भी करते हैं लेकिन जितना आप चमचमाते हैं, विभाग को चमचमाते तो हमलोग भी आपको शाबाशी देते, थैंक यू बोलते लेकिन आप विभाग के लिए ऐसा कुछ नहीं किये हैं. ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल पाँच मिनट आपका बचा है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप बीच–बीच में हमारा समय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, घड़ी हमारे सामने है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम भी घड़ी देख रहे हैं, हमको भी समय का ज्ञान है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप देख लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा अभी पूरे राज्य में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का हमको बता दीजिये, वहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुला है लेकिन उसकी स्थिति क्या है ? उसमें इनका एक भी, उस समय में उद्‌घाटन हुआ था प्रत्यय साहब भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, हमलोग भी थे, उस समय में

उद्‌घाटन हुआ लेकिन इनका आउट सोर्सिंग से अभी सारा स्टाफ है लेकिन उस स्टाफ का, न उनमें ओ॰टी॰ असिस्टेंट है यानी एक भी नहीं है जो भी है आउट सोर्सिंग से है, वहाँ इनडोर चल ही नहीं रहा है । आउट सोर्सिंग से कितना स्टाफ और वह भी भ्रष्टाचार से लाये हुए हैं । एक पेसेंट पेशाब और लैट्रिन के लिए जायेंगे, उनसे दो–दो सौ रुपया, ये स्ट्रेचर वाले लोग वसूलते हैं यानी बुरा हाल है और वहाँ इनडोर अभी तक चालू नहीं हुआ है और वहाँ न कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, न इनडोर में इनकी कोई व्यवस्था है, कोई इनडोर अभी नहीं चालू हुआ है, इनडोर चालू करा दीजिये । मनिगाछी, तारडीह में भी अभी बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्र का उद्‌घाटन हुआ है लेकिन उसमें भी आपका कोई भी स्टाफ नहीं है, उसको देखिये स्टाफ वगैरह का, स्टाफ आपके नहीं रहने से । डी॰एम॰सी॰एच॰ में हम कह रहे थे कि परिसर में खुली मरीजों के लिए बेहतर ईलाज की व्यवस्था रहेगी तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में जानकर आप हैरान होंगे कि इनडोर चालू नहीं है और उनका ओ॰टी॰ असिस्टेंट का पद एक नहीं, नर्स का लगभग 375 पद खाली है और नर्सिंग सिस्टर का 77 पद खाली है, इनका बी॰एम॰एस॰आई॰सी॰एल॰ को मैनपॉवर देना था अभी तक नहीं दिया गया है, ऐसा लगता है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का बूरा हाल है तो इसमें भी सुधार होना चाहिए और भी, जो भी इनका रेफरल अस्पताल मनिगाछी है या हमने पी॰एच॰सी॰, पी॰एच॰सी॰ आपको मनिगाछी, तारडीह पी॰एच॰सी॰, बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्र है, जो भी है अभी केवल आपका पेसेंट तो बढ़ा लेकिन उनके लिए समुचित डॉक्टर नहीं है, उनके ओ॰टी॰ असिस्टेंट नहीं हैं, उनके स्टाफ जो हैं नहीं हैं । हम 18 आपको उप स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में बताये मनिगाछी का, कृपया कर के कम–से–कम सप्ताह में एक दिन खोलवा दीजिये, वहाँ की जनता को लगेगा कि 2005 वाला समय आ गया । यदि आप वह भी समय नहीं दीजियेगा 2005 वाली तो आप अपना ही पीठ अपने थपथपाइयेगा तो हमलोगों को मंगल पाण्डे साहब....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप कहें तो हम समाप्त कर दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं दो मिनट है । दो मिनट बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम आज मंगल पाण्डे जी, आपलोगों को जो प्रिय हैं, इस विभाग से हमलोगों को नहीं, सही चित्रण बिहार की जनता के लिए महोदय, बिहार की जनता भी त्राहिमाम है । स्वास्थ्य विभाग में बढ़ा है ईलाज का लेकिन खाद्य पदार्थ की बीमारी से, आप जैसे आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰ है, इसका क्यों नहीं ब्रांच आप हर जिला में दे देते हैं, हर जिला में ब्रांच दे देंगे तो यहाँ जो आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰ में हमलोग भेजते हैं पेसेंट को तो वहां कहता है कि

आई॰सी॰यू॰ खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है । आप दरभंगा और जगह ब्रांच बढ़ा दीजिये, इसकी शाखा खोल दीजिये । पी॰एम॰सी॰एच॰ में ज्यादा संख्या में आपका पेसेंट नहीं आये, आपका बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, उसको आप पूरी तरह से चालू कर दीजिये, उसमें सारा स्टाफ जितना आपका एक्स–रे मशीन गया है स्टाफ चलाने वाले नहीं हैं, ओ॰टी॰ असिस्टेंट नहीं है, कोई नहीं है । आपका रूटीन वर्क जो पी॰एच॰सी॰ में होता था वही काम हो रहा है तो आप इसको कृपया कर जहाँ भी आप बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये हैं, यदि भवन भी बनवायें हैं, हमने कहा स्वागत कर रहे हैं लेकिन उसको अच्छे बेहतरीन प्रबंधन कीजिये, उसको चलवाइये, देख लीजिये । दवा का आपका बूरा हाल है, कोई दवा लेना नहीं चाहता है.....

...क्रमशः.....

टर्न–17 / संगीता / 20.03.2025

(क्रमशः)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, 65 प्रतिशत दवा आपके अस्पताल में आप दावा करते हैं कि है, ये 65 प्रतिशत दवा नहीं है इन अस्पतालों में...

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आज जो हाल है कृषि विभाग का, किसान को उचित उनका दर नहीं मिल रहा है, आज किसान खेती करने के लिए नहीं चाह रहे हैं । लोग चाह रहे हैं कि खेती करेंगे तो घाटा लगेगा तो आज कृषि विभाग का भी अनुदान मांग है, हम चाहेंगे कि कृषि विभाग भी किसान का आय कैसे बढ़े इस पर ध्यान दें...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बहुत–बहुत आपका धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ पटेल, 10 मिनट है आपका । आप 8–10 मिनट में खत्म करिए थोड़ा और कम समय लीजिए ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । साथ ही आदरणीय श्रवण बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और सम्मानित शीर्ष नेतृत्व एन0डी0ए0 के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं । साथ ही, बुद्ध की कर्मभूमि, महावीर की जन्मभूमि के साथ लोकतंत्र की

जननी वैशाली के तमाम मतदाताओं के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे यहां भेजने का काम किया । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि तमाम सदस्यों को उनके क्षेत्र की जनता ने यहां पर जो भेजने का काम किया, उन्होंने ये सोचा कि यह व्यक्ति मेरे इलाके का विकास करने के साथ–साथ बिहार को उसके गौरव के उच्चतर शिखर तक पहुंचाने का काम करेगा परन्तु हो क्या रहा है, जब तक विपक्ष के माननीय प्रबुद्ध सदस्य आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में रहे सरकार की योजनाओं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन की तारीफ में बोलते नहीं थकते थे, परन्तु सरकार से हटते ही पता नहीं इन्हें क्या हुआ, न जाने कहां–कहां से किस ओर से ऐसे आधारहीन डेटा सदन में लाते हैं जिससे बिहार की गरिमा को ठेस पहुंचती है । टी0वी0 के माध्यम से सारे देश एवं विदेशों में भी सदन की कार्यवाही देखी जाती है । मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से कि जो समय हमें मिला है...

(इस अवसर पर सभापति (श्री भूदेव चौधरी) ने आसन ग्रहण किया)

उसमें विपक्ष के साथी सकारात्मक सहयोग करें, जात–पात, पार्टी की भावना से ऊपर उठकर बिहार के विकास के कार्यों में सरकार का सहयोग करें, अच्छे विकासशील, सकारात्मक विपक्ष की मिसाल पेश करें ।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार की जनता को मौलिक एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सहित उपलब्ध सुविधाओं के गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए युग की आवश्यकता एवं परिवर्तन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है । इसी क्रम में जिले के अस्पतालों में और साथ ही हमारे जो प्रखंड और पी0एच0सी0 हैं वहां के अस्पतालों में जो हमारे प्रसव के जो इलाज होते हैं, जो नवजात बच्चे आते हैं, पैदा होते हैं उनके लिए सरकार ने अनुमंडल अस्पताल के साथ–साथ जिला के अस्पताल में भी निकू वार्ड की व्यवस्था की है । छोटे बच्चे जो बीमार होते हैं उनके समुचित इलाज हो सके । साथ ही साथ बाल हृदय योजनान्तर्गत प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन, अहमदाबाद के साथ राज्य की 2 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान यथा–इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान एवं इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान में मरीजों का इलाज किया जा रहा है । इस प्रकार योजनान्तर्गत अब तक कुल 1771 बच्चों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा चुका है । वर्ष 2025 तक यक्ष्मा बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में आधुनिक टीबी जांच के लिए नए–नए उपकरणों का क्रय कर प्रखंड स्तर पर टीबी के निःशुल्क जांच

की व्यवस्था प्रारंभ की गई है । इससे टीबी मरीजों के मृत्यु दर को काफी कम करने में सहायता मिली ।

सभापति महोदय, वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 28 हजार 892 मरीजों के इलाज हेतु लगभग 214 करोड़ 89 लाख 35 हजार 25 रुपये के अनुदान की राशि जो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गरीबों को दी गई । इसके साथ–साथ आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिसमें 5 लाख रुपये की चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है । अब हमारे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे कि बिहार से मरीज बाहर जाकर अपना इलाज करा रहे हैं । पी0एम0सी0एच0 के कैंपस में ही आइ0जी0आई0सी0 है जो हमारे मरीज जाते हैं अपने हृदय रोग का इलाज कराने के लिए उनकी एंजियोग्राफी और साथ ही सी0ए0बी0जी0 का इलाज भी पी0एम0सी0एच0 में आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया जा रहा है । इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार चला रही है ।

सभापति महोदय, नई पहल करते हुए सरकार ने मेडिकल छात्रों के पास हिन्दी या अंग्रेजी में पढ़ाई करने का विकल्प के उद्देश्य से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 का नए सत्र से हिन्दी में पढ़ाई करने का भी शुरूआत किया है । पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पुनर्विकास योजनान्तर्गत 5 हजार 462 शय्या के अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे वित्तीय वर्ष 2028–29 में पूर्ण करने का लक्ष्य है । साथ ही, दरभंगा एम्स को 187.44 एकड़ भूमि बिहार सरकार द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु भूमि पूजन भी किया जा चुका है । आई0जी0आई0एम0एस0 में अतिरिक्त 500 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है जिसे दिसंबर, 2025 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है । राज्य के ग्रामीण स्तर पर संचालित चिकित्सा संस्थानों के आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में 1–1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण एवं 5–5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के रूप में उन्नयन करते हुए नए भवन का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है । इस क्रम में 124 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 470 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के भवन का निर्माण कराया जा चुका है ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप करें ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : महोदय, 2023–24 से अब तक कुल 1602 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई जिसमें से 588 का निर्माण कार्य प्रगति पर है । सरकार ने प्रत्येक जिले में किडनी की समस्या से जूझ रहे मरीजों को जिले के सदर अस्पतालों में ही डायलेसिस की सुविधा प्रदान की है, अब उन्हें दूर नहीं

जाना पड़ता है । ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य के सभी प्रखंडों में सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन योजना के क्रम में इस वर्ष 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । कोविड के महामारी के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चुनौती के रूप में विभाग में काम किया और ग्रामीण क्षेत्रों में आज मैं आपको बता दूं कि मेरे क्षेत्र वैशाली में लगभग 12—13 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 1 पी0एच0सी0, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है और कार्य कर रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं हम अपने साथियों कुछ और लोग बोल रहे थे माननीय सदस्य कि वहां कोई ताला लगा रहता है । मैं उनको ले जाकर वैशाली में अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाकर दिखाने का काम करूंगा कि जो अस्पताल बनकर तैयार हुए हैं वे किसी आधुनिक प्राइवेट नर्सिंग होम से बेहतर उसकी संरचना देखने को मिलती है और तमाम तरह की दवाएं जो जीवनरक्षक दवाएं हैं वहां सरकार उपलब्ध कराए हुए है और उसके साथ जो मुफ्त में जांच किया जाता है वह भी वहां उपलब्ध है ।

सभापति महोदय, दवाओं की सूची में जो सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जीवनरक्षक दवा दे रही है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 212 दवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 201 दवा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 140 दवाएं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 151 दवाएं, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर 32 दवाएं जो जीवनरक्षक दवाएं हैं, वे गरीब मरीजों को दी जा रही हैं ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुफ्त जांच की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, सदर अस्पतालों में 148 जांच जो हैं वे मुफ्त में किए जा रहे हैं । अनुमंडल अस्पतालों में 51 जांच हैं वे मुफ्त में किए जा रहे हैं । सी0एच0सी0 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उनमें 75 जांच मुफ्त में कराए जा रहे हैं...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : मैं अपना खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध होगा कि पिछले 2020—21 के समय हमलोगों ने उनसे मांग की थी कि वैशाली विधान सभा के गोरौल में एक ट्रामा सेंटर देने के लिए, तो वह ट्रामा सेंटर उन्होंने दिया और वह कार्यरत है । वैशाली प्रखंड में जो वैशाली एक ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व का स्थल है ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / सुरज / 20.03.2025

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया आप समाप्त करें ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : वहां पर भी एक ट्रॉमा सेंटर खोलने की आवश्यकता है...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव जी अपना पक्ष रखेंगे ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : कृपया अनुरोध होगा वैशाली की जनता की तरफ से कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां ट्रॉमा सेंटर खोलने का काम करें ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : आपका समय 13 मिनट है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं सदन में सरकार द्वारा पेश किये गये बजट 2025–26 के विरूद्ध लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं ।

महोदय, मैं कुछ अपना विचार रखूं इससे पहले मैं अपने क्षेत्र 27, बाजपट्टी विधान सभा क्षेत्र के उन महान मतदाता मालिकों का आभार प्रकट करता हूं जो मुझ जैसा अदना आदमी को चुनकर इस सदन में भेजा है । मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार के दलितों, पीड़ितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों के मसीहा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जिनके शासन काल में उन दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को समाज और सरकारी महकमा के निकट बोलने, उठने, बैठने में बराबरी का दर्जा मिला । मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार के युवाओं के दिल की धड़कन, बिहार राज्य के भविष्य धर्म निरपेक्षता के सच्चे हितैषी, बिहार राज्य के बेरोजगारों को रोजगार एवं नौकरी देने के लिये प्रतिबद्ध अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को । मुझे मौका मिला है इस राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के रूप में सदन में बोलने का गौरव भी प्राप्त हुआ है । मैं आभार प्रकट करता हूं अपने मुख्य सचेतक शाहीन जी का ।

महोदय, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ बातें पेश करूं उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं । महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वस्थ भी हैं, व्यवहारिक भी हैं लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था स्वस्थ्य नहीं है और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सरल भी नहीं है । महोदय, मैं एक शेर कहना चाहता हूं :

मंगल है अमंगल मुख्यमंत्री जी लाचार

स्वास्थ्य व्यवस्था पर बाबा जी के ट्यूट से

बिहार की गरीब जनता है परेशान ।

महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है :

Sound mind and Sound Body

स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ्य मन का वास होता है । महोदय, जनक नन्दनी मां जानकी की पवित्र भूमि सीतामढ़ी जिला के स्वास्थ्य व्यवस्था से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को महिमा मंडित करना चाहता हूं ।

महोदय, सीतामढ़ी जिला के सदर हॉस्पीटल कैम्पस में लाखों की लागत से आई0सी0यू0 भवन बनाने वाला संवेदक पूर्णरूपेण भवन कम्पलीट कर हॉस्पीटल प्रशासन को हस्तगत भी नहीं कराया लेकिन आज से लगभग 6 माह पहले 6 सितम्बर, 2024 को माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भवन का उद्घाटन किया गया लेकिन आज भी उस भवन में अलीगढ़ का ताला लटका हुआ है । महोदय, वर्ष 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्णमयी शुरूआती शासन काल में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में आई0सी0यू0 भवन बना लाखों की लागत से मुझे खुशी भी हुई लेकिन आई0सी0यू0 व्यवस्था बिना चालू हुये भवन खंडहर हो चुका है ।

महोदय, यही है इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, यही है सुशासन, यही है, न्याय के साथ विकास ?

महोदय, सीतामढ़ी सदर हॉस्पीटल में मेंटल, कॉर्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ई0एन0टी0, यूरोलॉजी के एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, जबकि पद स्वीकृत है । आज तक सीतामढ़ी में आंख का एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ, प्रसूती विभाग में एम0बी0बी0एस0 की जगह आयुष चिकित्सक मरीज का इलाज करते हैं । अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड होता भी है लेकिन प्रतिदिन 15–20 मरीज बाहर से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फर्जी रोस्टर बनाया जाता है । मैं जब भी हॉस्पीटल गया प्रभारी उपाधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई । डॉक्टर ट्रेन से आते हैं और 24 घंटे की डयूटी करके अपने घर लौट जाते हैं । महोदय, सीतामढ़ी जिला 40 लाख जनसंख्या वाला जिला के सदर हॉस्पीटल में 5 खटारा एम्बुलेंस है । ड्रेसर, ओटी सहायक, फॉर्मासिस्ट सदर हॉस्पीटल में नहीं हैं । यही है इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था ।

सीतामढ़ी जिला के पी0एच0सी0 बाजपट्टी, नानपुर, बोखड़ा सहित पूरे बिहार में एक में भी स्वीकृत पद के अनुसार डॉक्टर तो दूर एक्स–रे टेक्निशियन भी नहीं हैं ।

महोदय, हमारे नेता तेजस्वी जी के कार्यकाल में एन0एच0एम0 कर्मियों के लिये पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने की घोषणा की गयी थी। इन्होंने आज तक नहीं लागू किया यह एक गंभीर विषय है ।

महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा हमेशा ट्यूट कर लिखा जाता है अखंड स्वास्थ्य व्यवस्था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इतना बना । महोदय, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो स्थिति है सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कबाड़ा, जंगल, विषैला सांप और मवेशी वहां रहते हैं ।

महोदय, कुछ लोग हमारे नेता पर कटाक्ष करते हैं । मैं उनलोगों को बहुत करीब से जानता हूं, कुछ लोग सदन में भी हैं जिनको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जीरो से हीरो बनाने का काम किया । आज वे लोग अन्योक्ति बोलते हैं और परिवारवाद का राग अलापते हैं । उनलोगों को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं अपनी चाल छोड़ कर खड़रीच की चाल नहीं चलिये अन्यथा अपनी चाल भी भूल जायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद जी वह व्यक्ति हैं जिस पर जितना प्रहार करेंगे उतना निखरेंगे । महोदय, सोना आग में जलता नहीं चमकता है ।

महोदय,

तेजस्वी यादव नाम है जिसका, वह भिल मरण से डरता है,

ज्वाला को बुझते देख कुण्ड में स्वयं कूद जो लड़ता है,

झा–झा सोई तूफान रूका प्लवंजा रहा कगारों में,

तेजस्वी है नाम जिसका वह जन–जन के हुंकारों में ।

महोदय, मैं कमिशनरी श्रीकृष्ण मेडिकल अस्पताल के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । वहां हेड फार्मासिस्ट के 6 पद स्वीकृत हैं, कार्यरत बल जीरो है, रिक्ति 06 है । इसी तरह ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्निशियन, एक्स–रे टेक्निशियन, डार्क असिस्टेंट, लोवर डिविजन क्लर्क, डायटीशियन, ई0सी0जी0 टेक्निशियन, ई0सी0एच0ओ0 टेक्निशियन, सी0एस0एस0डी0 टेक्निशियन, आर्थो प्रोस्टोरिक टेक्निशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर, हॉस्पीटल मैनेजर, हेल्थ मैनेजर, डायलेसिस टेक्निशियन, ई0एम0जी0/एन0सी0बी0/ई0टी0सी0 टेक्निशियन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर । महोदय, श्री कृष्ण मेडिकल अस्पताल में 728 स्वीकृत पद हैं, उसमें मात्र 128 कर्मी कार्यरत हैं, 654 रिक्ति है । यही है सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था, यही है सरकार की मंगल स्वास्थ्य व्यवस्था ?

महोदय, ये लोग हमेशा 2005 से पहले की बात करते हैं । आपको 20 साल मौका मिला लेकिन 20 साल में आप एक श्रीकृष्ण मेडिकल अस्पताल हो, चाहे पी0एच0सी0 हो, चाहे सदर अस्पताल में हो । महोदय, 20 साल का शासन, शासन होता है और 20 साल के शासनकाल में भी रिक्ति के अनुसार न डॉक्टर है, न टेक्निशियन है, न लैब टेक्निशियन है, नर्स कीं बहाली क्यों नहीं हुआ ? अपनी पीठ थपथपाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा ।

महोदय, अब मैं राज्य की राजधानी पटना के चकाचौंध सुदृढ़ीकरण, सुव्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं । राजधानी पटना में डायबीटीज और थायराईड का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल न्यू गार्डिनर है, जहां 06 विशेषज्ञ चिकित्सकों की जगह मात्र दो चिकित्सक हैं । यहां किडनी रोगी के लिये 06 बेड की डायलेसिस इकाई है परन्तु चिकित्सक नहीं होने के कारण नर्सों द्वारा बिना चिकित्सक के देखरेख में डायलेसिस करायी जाती है जो कि मानव जीवन के लिये घातक है ।

महोदय, पी0एम0सी0एच0 की क्या कहूं कहानी – भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी । राज्य ही नहीं देश स्तर के हॉस्पीटलों में शुमार पी0एम0सी0एच0 का यह हाल है कि वहां मरीज के परिजनों को बेड पर लगा गंदगी मल–मूत्र स्वयं साफ करना पड़ता है...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आपके पास मात्र 03 मिनट बचा है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : इस हॉस्पीटल में हथुआ नाम से प्रसिद्ध वार्ड जहां फर्श पर लेटे मरीज के बगल में मल–मूत्र का प्रवाह होता है । जहां जिंदा मरीज को भी डेथ सर्टिफिकेट देकर उनके घर भेजा जाता है । जैसे 12 अप्रैल, 2021 की बात है । बाढ़ का चुन्नु ठाकुर ब्रेन हैमरेज के कारण पी0एम0सी0एच0 में भर्ती हुआ था, भर्ती होने में मरीज के परिजनों से बिचौलिया ने 500 रुपया लिया, भर्ती के पश्चात मरीज के परिजन को वहां से हटा दिया गया लेकिन मरीज के परिजन किसी प्रकार कुछ रुपया खर्च कर बिचौलिया से मरीज का विडियो मंगवाया । सुबह में परिजनों को बताया गया कि आपका मरीज सिरियस है। पुनः एक घंटा के बाद कहा कि आपका मरीज मर चुका है । उसको पैक करके और चुन्नु ठाकुर की पत्नी कविता देवी को अंत्येष्ठि के लिये जब लाश लाया जाता है और अंतिम दर्शन के लिये जब उनकी पत्नी देखती हैं तो कहती हैं कि यह मेरे पति नहीं हैं । यही है पी0एम0सी0एच0 का हाल, यही है स्वास्थ्य व्यवस्था । फिर लाश पुनः पी0एम0सी0एच0 लाया जाता है । वही चुन्नु ठाकुर जीवित होता है । यही सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार में ।

आई0जी0आई0एम0एस0 और एम्स में डॉक्टर से दिखवाकर एवं जांच कराकर पुनः डॉक्टर से मिलने के लिये 4 से 5 माह का समय लगता है ।

(क्रमशः)

टर्न–19 / राहुल / 20.03.2025

श्री मुकेश कुमार यादव : (क्रमशः) एम0आर0आई0 के लिए 6–6 महीने समय लगता है यही है स्वास्थ्य व्यवस्था । महोदय, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं सगुना मोड़ के नरेश कुमार आई0जी0आई0एम0एस0 में चिकित्सकों के द्वारा अल्ट्रासाउण्ड कराकर दिखाने को कहा तो वहां 4 माह के बाद समय दिया, डॉ0 समुन कुमार, विभागीय अध्यक्ष, आई0जी0आई0एम0एस0 सफाई देते हुए कहते हैं चिकित्सकों की कमी है । महोदय, 20 साल आपको मौका मिला अभी भी चिकित्सक की कमी है । आप बिहार की जनता को ठगने का काम करते हैं । महोदय, यही तो हाल है बीमार होंगे आज, दवा खायेंगे 6 महीना के बाद । एक देहाती कहावत है बाबा अईहन तो बैल बिकईयन, ओकरा बाद पोता इलाज करावे हॉस्पीटल जईयन । महोदय,

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
कुछ लोग कत्ल भी करते हैं तो बनते हैं ईमानदार ।

महोदय, स्वास्थ्य व्यवस्था का यही हाल है आज तक डेंटल चिकित्सा शिक्षा संवर्ग नहीं है, आज तक फार्मेसी शिक्षा संवर्ग नहीं है, आज तक सभी मेडिकल कॉलेज में डी0एम0 की पढ़ाई नहीं होती है, आज तक डेंटल के सभी विषय में पी0जी0 एवं पी0एच0डी0 तो अभी तक आराम नहीं हुआ है, फार्मेसी कॉलेज में पी0जी0 एवं पी0एच0डी0 की पढ़ाई हुई नहीं हुई है, नर्सिंग में किसी सरकारी कॉलेज में पी0जी0 पढ़ाई तथा पी0एच0डी0 तो अभी तक आराम भी नहीं हुआ है । वर्तमान में राज्य में हॉस्पीटल में प्रतिदिन 2.15 लाख मरीज चिकित्सा हेतु पहुंचते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 11 हजार प्रतिमाह पहुंचते हैं । महोदय, बिहार में 1,24,909 सामान्य चिकित्सक की जगह मात्र 58144 डॉक्टर हैं । यही है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था । महोदय, मैं एक छोटी–सी कहानी की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । हमारी पंचायत के बगल में एक ग्राम शरीफपुर की कहानी है...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया संक्षेप करें । आपका समय समाप्त होने वाला है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : यह हमारे प्रमुख काल की बात है । ग्राम शरीफपुर में गरीब अल्पसंख्यक एवं दलित समाज की ज्यादा आबादी है, उक्त ग्राम में कोई डॉक्टर नहीं था । एक रोज एक हकीम साहब गांव में पहुंचे और कुछ लोगों से मिलकर कहा कि हम आपको गांव में रहकर लोगों की चिकित्सा करना चाहते हैं । ग्रामीणों ने कहा यह तो अच्छी बात है यहां कोई चिकित्सक नहीं है । इनको

रहने की जगह दी जाय । हकीम साहब की जगह निश्चित कर दी गयी फिर हकीम साहब कहे कि मुझे चिकित्सा शुरू करने से पहले यहां के प्रमुख और मुखिया से मुझे मिलवा दीजिये । मुझे खबर मिली, मैं भी वहां गया पूछा बताया जाय हकीम साहब क्या बात है ? हकीम साहब बोले प्रमुख जी, मुखिया जी मैं पहले आप लोगों के साथ ग्राम में किसी के ईलाज करने से पूर्व यहां के कब्रिस्तान एवं शमशान की लंबाई और चौड़ाई का मुआयना करना चाहता हूं । कुछ देर के लिए मुझे लगा यह व्यक्ति प्रतिकूल मानसिकता के तो नहीं हैं...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मुकेश कुमार यादव : लेकिन महोदय, जहां डायलेसिस नर्स से कराया जाय, प्रसूती महिला एम0बी0बी0एस0 की जगह आयुष चिकित्सक से करायी जाय तो कब्रिस्तान और शमशान की लंबाई चौड़ाई तो नापी ही जायेगी । महोदय,

चमन को सींचने में
पत्तियां कुछ झड़ गयी होंगी,
यही इल्जाम है मुझ पर,
मगर जिसने चमन को पैरों तले रौंदा है,
आज वहीं रहनुमाई करते हैं चमन का ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब समाप्त करें । कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, याचना नहीं अब रण होगा,
जीवन जय या मरण होगा ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री देवेश कांत सिंह ।

श्री मुकेश कुमार यादव : इस बार तेजस्वी से लड़ने वाला, मिट्टी में मिल जायेगा,
खड़रीज का चाल अगर चला, तो अपनी चाल भूल जायेगा,
हिटलरशाही यदि किया तो हिटलर की तरह मिट जायेगा ।

जय हिंद ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री देवेश कांत सिंह अपना पक्ष रखेंगे । आपके पास मात्र 6 मिनट है ।

श्री देवेश कांत सिंह : माननीय सभापति जी, आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने एन0डी0ए0 के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी, दोनों उपमुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मंगल पांडे जी और हमारे सचेतक श्रवण बाबू, उप सचेतक हमारे जनक बाबू का आभार व्यक्त करते हुए कटौती प्रस्ताव उन्होंने रखा है, हम सरकार का पक्ष रखेंगे लेकिन मैं एक बात के लिए सबसे पहले गौरव महसूस करते हुए बात को रखना चाहता हूं कि सीवान के दो लाल, एक प्रशासनिक स्तर पर और एक सरकार के स्तर पर इस स्वास्थ्य विभाग का जो कल्याण कर रहे हैं और जिन लोगों ने लूटा है उनको यह न नजर आता है, न समझ आता है । मैं सरकार से कहता हूं और सभापति महोदय जी से भी आग्रह करता हूं जब इन विषयों पर चर्चा हो तो कुछ

कब्ज की और कुछ पेट दर्द की दवाई भी सदन में होनी चाहिए क्योंकि कोई किसी को कुछ भी कह दे इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि वही 15 साल की सरकार थी, जहां रमेश चंद्रा जैसे स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर इस प्रदेश को छोड़कर चला गया, जहां डॉक्टर कालीका शरण चले गये, जहां डॉक्टर नरेन्द्र कुमार के यहां जो हुआ, उसकी चर्चा आज भी डॉक्टरों के बीच होती है तो स्वास्थ्य विभाग के साथ क्या–क्या हुआ और उसमें परिवर्तन उनको नजर नहीं आयेगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो सदन में एक आदमी यहां बैठकर कहते हैं कि बिहार को केन्द्र सरकार से बजट में कुछ नहीं मिला और बगल के विधान परिषद् में नेता कहती हैं कि प्रधानमंत्री को यहां सरकार बनानी है और आंध्र का समर्थन प्राप्त करना है इसलिए सिर्फ बिहार और आंध्र को देखा जा रहा है । मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी से कहता हूं कि राजनीतिक रूप से जो आंखों का ईलाज हो सके उसके लिए भी एक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में होनी चाहिए । उसकी भी होनी चाहिए क्योंकि...

(व्यवधान)

मुख्यमंत्री जी कितने लोगों का ईलाज करा रहे हैं यह आपको भी पता है । आज जो स्थिति है, आज स्वास्थ्य के प्रति कितना गंभीर हैं...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्यगण शांति बनाये रखें ।

श्री देवेश कांत सिंह : स्वास्थ्य मंत्री जी के आज सदन में रखने के बाद आप लोगों को कितना कष्ट है यह किसी को...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : बैठिये–बैठिये । प्लीज ।

श्री देवेश कांत सिंह : आज स्थिति यह है कि आप स्वास्थ्य के प्रति कितना गंभीर हैं यह सदन में आपकी उपस्थिति बता रही है । माननीय कांग्रेस के नेता अजय बाबू...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : आप बैठिये । आप बैठिये । बोलने दीजिये ।

श्री देवेश कांत सिंह : कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे और सरकार के खिलाफ बोल रहे थे लेकिन कटौती प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष आने के पहले सदन को छोड़कर चले जाना इन लोगों की आदत बन गयी है । अजय बाबू बोले, चले गये, मुकेश जी भी थोड़ी देर में 04.30 बजे सूचना आयेगी, चले जायेंगे । ललित भैया भी 30 वर्ष से इस सदन के स्वस्थ सदस्य हैं और सारे लोग, जितने लोग बैठे थे सबने अपने दल की व्यथा के अनुसार सरकार के विरोध कर रहे हैं लेकिन कोई माननीय मंत्री जी के काम का विरोध व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सके । इसलिए क्योंकि सारे लोगों का स्वास्थ्य भी यही स्वास्थ्य मंत्री देखते हैं और आज स्थिति है कि कोई कहता है कि हमारे यहां ताला लगा है...

(व्यवधान)

अब तो अस्पताल आपको पता है । माननीय ललित भैया कह रहे थे कि अस्पतालों में ताला लटका है, ताला क्यों नहीं लटकेगा । 15 साल में एक डॉक्टर, एक अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज आपने नहीं खोला, जनसंख्या बढ़ गयी, उसके लिए डॉक्टर, ईलाज की व्यवस्था नहीं हुई । आज यह सरकार ईलाज की व्यवस्था के अंतर्गत प्राईवेट और सरकारी मिलाकर 16 अस्पताल चला रही है और कुल 1200 विद्यार्थी पास कर रहे हैं । डॉक्टर प्रोडक्ट होगा तो डॉक्टर बहाल होगा और डॉक्टर वहां जायेगा...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया शांति बनाये रखें । सबको बोलने की स्वतंत्रता है ।

श्री देवेश कांत सिंह : आप परेशान न होइये । मैंने 20 साल, 15 साल में एक डॉक्टर प्रोडक्ट नहीं हुआ और जब 20 साल में डॉक्टर पैदा हो रहे हैं...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : देवेश जी, अब आपका समय समाप्त होता है ।

श्री देवेश कांत सिंह : मैं सरकार से इस आग्रह के साथ कि जो हमने कहा कि लोगों के लिए सदन में भी कुछ डॉक्टरी की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से एक व्यक्तिगत आग्रह के साथ गोरेयाकोठी विधान सभा क्षेत्र, सीवान जिले के सुदूर क्षेत्र में पड़ता है । प्रत्यय अमृत जी भी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं कि गोरेयाकोठी में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां एनेस्थिसिया और महिला डॉक्टर की व्यवस्था होकर एक फर्टिलाइज की व्यवस्था कर दे जिसकी व्यवस्था पूर्व में थी । अभी वे लोग पी0जी0 करने चले गये हैं इसलिए उसकी जगह पर कुछ व्यवस्था करे और मैं ललित भैया के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने, चाहे अजय जी ने, चाहे मुकेश जी ने, सबको माननीय मंत्री जी अच्छे लगते हैं...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें । अब आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री देवेश कांत सिंह : महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद और आप सभी नेताओं का आभार ।

टर्न–20/मुकुल/20.03.2025

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री फते बहादुर सिंह जी अपना पक्ष रखें । आपका समय मात्र 8 मिनट है ।

श्री फते बहादुर सिंह : धन्यवाद सभापति महोदय । महोदय, विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आज मैं समाज कल्याण विभाग पर अपनी बात रखूंगा । महोदय, समाज कल्याण विभाग जो है रसोईया की स्थिति देख लीजिए, समाज कल्याण विभाग के अनुसार रसोईया 1550 रुपया प्रति माह काम करने के लिए मजबूर है । आशा, ममता, आंगनबाड़ी की सेविका/सहायिका, जबकि मुख्यमंत्री जी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि महिलाओं के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है और जितनी भी महिलाओं की योजना

है सबको फ्री में या कम तनख्वाह देकर के उनसे काम कराया जा रहा है तो मैं सरकार से इस पर मांग करता हूं कि आशा की जो महिला हैं उनको 600 रुपया एक डिलीवरी पर मिलता है और ममता को 300 रुपया मिलता है, जिस दिन उनको अगर डिलीवरी/प्रसव की महिला नहीं मिली उस दिन उनके घर का चूल्हा तक नहीं जलता है । सरकार को समाज कल्याण को दुरुस्त करने के लिए आशा को कम से कम 10 हजार रुपये प्रति माह देने के लिए मैं मांग करता हूं, ममता के लिए कम से कम 8 हजार रुपये, आंगनबाड़ी सेविका को 7 हजार मिलता है, उनको कम से कम 15 हजार, सहायिका को कम से 10 हजार देने के लिए मैं मांग करता हूं । जो रसोईया है, वह आठ घंटा काम करता है, उनको कम से कम 10 हजार रुपया प्रतिमाह मिलना चाहिए । महोदय, समाज कल्याण जो है हमारे बच्चों को भी शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन हमारे ही सरकार के कुछ लोग जो हैं, हमारे सरकारी विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण कर लेते हैं, जैसे हमारे ही क्षेत्र में जमुहार का उच्च विद्यालय है जिसका 80 डिसीमिल जमीन जो है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद, लोकसभा के द्वारा 80 डिसीमिल जमीन कब्जा कर लिया गया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया । महोदय, आज मेरा क्वेश्चन भी था, आज मेरा सवाल भी था उस सवाल पर जो है मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि मैं सरकारी विद्यालय की 80 डिसीमिल जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, इससे स्पष्ट साबित होता है कि सरकार जो है भूमाफियाओं के साथ है, जो विद्यालय की जमीन अतिक्रमण करके रखे हैं । महोदय, सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा, वह भूमाफियाओं के साथ है या पिछड़े, दलित जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके साथ है । महोदय,

''सबकुछ जानते हुए भी,

अक्ल पर पत्थर क्यों पड़ी है तुम्हारी,

अगर मंदिर से दानपेटी हटा दिया जाये,

तो भगवान नाराज होगा या पुजारी ।''

महोदय,

''हम सोये वतन को जगाने चले हैं,

हम मुर्दा दिलों को जगाने चले हैं,

गरीबों को रोटी न देती हुकूमत,

जालिमों को जालिमों से लोहा बजाने चले हैं,

हमें और ज्यादा न छेड़ो ए जालिम,

मिटा देंगे जुल्म के ये सारे नजारे

या मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं,

हम सोये वतन को जगाने चले हैं ।''

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, कृपया आप संक्षेप करें, अब आपके पास मात्र एक मिनट का समय बचा है ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, महोदय ये कैसा न्याय के साथ विकास है कि गरीबों की अगर झोपड़ी उजाड़नी होती है तो 5 मिनट में उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है और माफियाओं को, जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वह पिछले 25 वर्षों से विद्यालय की 80 डिसीमिल जमीन कब्जा करके रखे हैं उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, यह न्याय के साथ विकास है क्या ? मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हैं तो पिछड़े, दलित के बच्चों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज जिसकी 80 डिसीमिल जमीन को कब्जा करके जो रखा हुआ है उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करावें हमारे मुख्यमंत्री जी । गरीब की झोपड़ी उजाड़ने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है, मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी पिछड़े और दलितों के साथ हैं या विद्यालय की सरकारी जमीन को कब्जा करने वाले के साथ हैं ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार चौधरी जी अपना पक्ष रखें । आपके पास मात्र पांच मिनट का समय है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, हमको पांच मिनट ही चाहिए, इसलिए चाहिए कि ललित भाई ने आज कुछ बातें कह दी हैं तो उनका जवाब देना जरूरी है । सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, उसके बाद मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिनकी वजह से मैं यहां पर आ सका हूं और मैं अपने दोनों उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं और मैं मंगल पाण्डेय जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे माता–पिता के नाम से एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं उनके प्रति तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं ।

अभी ललित बाबू ने कहा, हमारा उनसे बड़ा ही आत्मीय संबंध है । ललित बाबू ने कहा मणिगाछी में हमलोग दरभंगा जिला के दोनों आदमी हैं, दरभंगा जिला का एक समय था कि ललित बाबू जिस क्षेत्र से, मणिगाछी से आते थे, कांग्रेस समय में भी वहां से कांग्रेस के लिए स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, ललित बाबू और वह स्वास्थ्य मंत्री महोदय, दोनों आदमी हमारा बेनीपुर अनुमंडल और बिरौल अनुमंडल है वहां पर रेफरल अस्पताल नहीं था, लेकिन मणिगाछी में रेफरल अस्पताल था, ये लोग जो सारे नियम को ताक पर रखकर के मणिगाछी में सबकुछ रखते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह पूरे राज्य के, अब दबंग तो नहीं कह सकते हैं टेक्निकली अशुद्ध शब्द है लेकिन दोनों हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी पहले जो थे श्रद्धेय उनका नाम अब सदन में नहीं है, हैं भी नहीं और हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं और दोनों आदमी सिर्फ मणिगाछी का विकास करते थे, दरभंगा जिला का विकास ये लोग नहीं करते थे । महावीर बाबू थे स्वास्थ्य मंत्री, महावीर बाबू के समय में भी, ललित बाबू भी बहुत नजदीक थे खाली ले जाते थे मणिगाछी तो मणिगाछी के स्वास्थ्य से पूरे जिला का और पूरे राज्य का स्वास्थ्य की तुलना आप नहीं कर सकते हैं । अगर 2005 से पहले की बात आप करते हैं कि मणिगाछी में बेहतर स्वास्थ्य था तो वह स्वास्थ्य बेनीपुर में क्यों नहीं था ?

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, आप कृपया विषय पर बोलें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल क्यों नहीं बना था, बिरौल अनुमंडल था, बिरौल में अनुमंडल अस्पताल क्यों नहीं बना था, यह होना चाहिए था । समुचित रूप से सबका विकास जब होता है तब उस विकास को आप रेफ्रेंस दे सकते हैं तो 2005 से पहले मणिगाछी के विकास से पूरे राज्य का विकास नहीं हो सकता है यह मैं अपने ललित बाबू को कहना चाहता हूं । नीतीश कुमार जी का शासन सिर्फ एक सरकार नहीं है, बल्कि एक क्रांति है और स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो हर क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाया है और यह तो घोषित रूप से या अघोषित रूप से सब आदमी मानते हैं, मान लेने में क्या हर्ज है कि क्रांति हुई है और सुधार चाहिए । कैसे सुधार होता आप अविभाजित बिहार में छः मेडिकल कॉलेज था और

....क्रमशः...

टर्न–21 / यानपति / 20.03.2025

(क्रमशः)

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, 1990 से लेकर 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपने नहीं की तो कहां से डॉक्टर पैदा लेता और डॉक्टर पढ़ा ही नहीं, डॉक्टर डिग्री लिया ही नहीं तो डॉक्टर की बहाली कहां से हो पाती । यह था

उनका, अस्पताल कम था, खंडहर ज्यादा था, डॉक्टर कम थे, बिचौलिए ज्यादा थे, सरकारी अस्पतालों में दवा से ज्यादा धूल मिलती थी और अगर दवा मिल भी जाती थी तो वह या तो एक्सपायरी होती थी या फिर गायब रहता था । चारा घोटालों की, चबाते वक्त क्या उन्होंने बिहार के बीमार लोगों की कराहटें नहीं सुनीं, जहां कभी दवा के नाम पर लूट चलती थी, आज वहां नई स्वास्थ्य क्रांति पलती है । नीतीश जी की मेहनत का यह परिणाम है कि आज हर मरीज को बेहतर उपचार मिलता है । उस समय में, 1990 से लेकर 2005 तक के बीच में जी0एन0एम0 कॉलेज क्या है यह पता नहीं था, ए0एन0एम0 कॉलेज क्या था यह नहीं पता था और पारा मेडिकल कॉलेज क्या था यह पता नहीं था...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें । आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महिना, रमौली, सिवराम और उसरी धाम में चिकित्सक, अवर चिकित्सक, कर्मी जो पूर्ण रूप से नहीं हैं उसकी व्यवस्था. ..

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, श्री अरूण सिंह जी अपना पक्ष रखेंगे । आपका समय 8 मिनट है ।

श्री अरूण सिंह : सभापति महोदय, मैं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । हमारा देश लोक कल्याणकारी राजव्यवस्था के जरिए चलता है और जनता को केंद्र में रखकर कानून बनाए जाते हैं । अभी सदन में जो बातें चल रही हैं तो 15 और 20 वर्ष की चर्चाएं खूब चल रही हैं । हम वर्ष–2000 में इस विधान सभा के सदस्य चुने गए थे और जो हमारे यहां प्रखंड का हॉस्पिटल है वहां 8–8 डॉक्टर रहते थे । हम सभी आदमी शाम को चाय की दुकान पर भी बैठते थे । सब लोग वहीं आवास भी करते थे । आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और कोई भी आवास उनका नहीं है । हमलोग फोन करते हैं कि आप देख लीजिए तो वह अपने घर से आते हैं, यह स्थिति है 2020–2025 के बाद । जब हम बचपन में थे और जब पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे तो घर से लोग कहते थे कि हॉस्पिटल से दवाई ले आना दर्द कर रहा है, कय हो रहा है और हमलोग स्कूल जाकर लौटते थे तो हॉस्पिटल से दवा लेकर आते थे लेकिन आज हम नहीं देखते हैं कि कहीं हॉस्पिटल चालू है और वह हॉस्पिटल है भी तो डॉक्टर और नर्स है या नहीं । उस समय कंपाउंडर घर पर आकर सूई भी देते थे, इंजेक्शन भी देते थे लेकिन आज इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं, 15 और 20 की तुलना जो कर रहे हैं तो उस बारे में आपको दो उदाहरण मैं दे रहा हूं । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं 15 और 20

की तुलना इस बात से भी की जा सकती है कि अभी हाल में ही इसी विधान सभा ने राज्य के अंदर जातीय जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया और 10 हजार से कम आय पर जीवन–बसर करने वाले बिहार में लोगों की संख्या है 63 प्रतिशत, क्या है स्थिति, 15–20 की चर्चा आप खूब कर रहे हैं लेकिन स्थिति क्या है । 63 परसेंट, आबादी का दो हिस्सा, तीन हिस्सा में दो हिस्सा किसी तरह से जीवन बसर कर रहा है बिहार के अंदर और इसको ख्याल में रखकर स्वास्थ्य विभाग का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसकी नीतियां बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, इसपर चर्चा होनी चाहिए । यह सवाल बिहार का मौजूदा सवाल है लेकिन इस सवाल पर कोई चर्चा नहीं होती है । कोरोना काल में इसी विधान सभा में हमलोग थे तो कोरोना था, कोरोना काल में चीजें सामने आई कि राज्य के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे । कहीं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चल रहा था आज कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट हॉस्पिटलों का प्रचलन बढ़ा हुआ है और हम देखते हैं इन हॉस्पिटलों में कि सरकार की कोई भी नीतियां काम नहीं कर रहीं । मनमाने ढंग से फीस वसूली जा रही है, मनमाने ढंग से ऑपरेशन चार्ज वसूला जा रहा है, मनमाने ढंग से बेड चार्ज वसूला जा रहा है, मनमाने ढंग से नर्सरी चार्ज वसूली जा रही है, कोई भी नीतियां सरकार की नहीं चल रही हैं और लगता नहीं है कि बिहार में कोई सरकार नाम की चीज है । सरकार रहती तब न यह नीतियां रहती, अब कितना भी आप पीठ थपथपा लीजिए 15 और 20 वर्ष की असलियत बिहार की यही है कि कोई भी कोई नियंत्रण उन संस्थानों पर नहीं है । कोरोना काल में जो चीजें सामने आई कि हमें सरकारी हॉस्पिटल को और मजबूत करना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल को जितना मजबूत करेंगे, हम बिहार के लोगों के पास उतनी ही सुविधा उपलब्ध करवा देंगे और उसी में मांग हुई कि प्रखंड स्तर के जो हॉस्पिटल हैं उसको सदर हॉस्पिटल की सुविधा मुहैया कराई जाय और सदर हॉस्पिटल में जो सुविधा है उसको पी0एम0सी0एच0 में जो सुविधा मुहैया है उसको मुहैया कराया जाय और पी0एम0सी0एच0 को एम्स जैसी सुविधा मुहैया हो । अगर हम यह काम करने में सफल होते हैं तो इस गरीब बिहार में उनके स्वास्थ्य की सुविधा हम दे सकते हैं नहीं तो किसी तरह की बात बोल रहे हैं, वह पूरी तरह से बेमानी है ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आपके पास मात्र दो मिनट बचा है ।

श्री अरूण सिंह : सरकारी हॉस्पिटल की यह स्थिति है कि इनको जितना मजबूत करेंगे उतना आपको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध, इधर–उधर की बात मत कीजिए, आप बिहार की सरकार हैं, बिहार आपके भरोसे चल रही है और बिहार का कल्याण करने की जिम्मेदारी आपकी है । रोहतास जिला में 19 प्रखंड, शाहाबाद जिला में रोहतास आता है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर तीनों जिला में मेडिकल हॉस्पिटल स्वीकृत हो गया है । रोहतास जिला में सबसे बड़ा भोजपुर से भी बड़ा रोहतास

जिला वहां मेडिकल हॉस्पिटल नहीं खुल रहे हैं, क्यों नहीं खुल रहे हैं इसलिए अब भाजपा का नाम ले लेंगे तो बस युद्ध हो जायेगा, वहां गोपाल नारायण मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, प्राइवेट हैं वो, जमीन अतिक्रमण, वह भाजपा के नेता हैं और उसी को आधार बनाकर अभीतक वहां कॉलेज नहीं खुला है । मैं मंत्री महोदय से...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अरूण सिंह : विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वहां मेडिकल कॉलेज खोला जाय...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : आपका समय समाप्त हो गया है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अरूण सिंह : और कुछ मांगें हैं महोदय, कि महिलाओं की खूब चर्चाएं होती हैं, महिलाओं की चर्चा करते समय हमारे मुख्यमंत्री जी, सत्तापक्ष के लोग थकते नहीं हैं...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें ।

श्री अरूण सिंह : लेकिन आशा बहनों से आज तक जो वादा किए हैं उसको भी पूरा करने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार रौशन जी अपना पक्ष रखेंगे।

श्री अरूण सिंह : उनका वेतन बढ़ाना चाहिए, उनको मानदेय देना चाहिए ।

टर्न–22 / अंजली / 20.03.2025

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार रौशन जी, अपना पक्ष रखेंगे । आपका समय 16 मिनट है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : माननीय सभापति महोदय, आज विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए आपने समय दिया है इसके लिए आपके प्रति आभार, अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार और अपने नेता प्रतिपक्ष बिहार के युवाओं के मान और सम्मान, देश के युवाओं के आदर्श श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं ।

महोदय, अपने मुख्य सचेतक श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन साहब के भी प्रति आभार प्रकट करते हैं । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र महुआ की महान

जनता के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहां बोलने के लिए खड़ा हूं ।

महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है । महोदय, बिहार की जो वर्तमान हालात हैं, अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है और बिहार में बहार और फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार हैं, चारों तरफ हो रहा हाहाकार है, हर तरफ हो रही लूट, हत्या और बलात्कार है और फिर भी नीतीश कुमार है । मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सैल्यूट करता हूं कि जब–जब उनको मौका मिला महागठबंधन की सरकार बनी 2015 में उस समय और 2022 में जब–जब मौका मिला स्वास्थ्य विभाग में काम करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने जिस तरीके से मिशन–60 के तहत काम किया मेडिकल कॉलेज अनुमंडल अस्पताल, सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित एवं सुसज्जित करने के लिए उन्होंने काम किया, एक नया इतिहास रचने का काम किये । रात के अंधेरे में जब वे निकलते थे औचक निरीक्षण पर पूरे बिहार का डॉक्टर एलर्ट मोड पर हो जाता था कि आज तेजस्वी यादव जी अस्पताल में जा रहे हैं निरीक्षण करने, पूरा अपने घर से चप्पल छोड़कर भागता था डॉक्टर और अपने अस्पताल में जाकर ड्यूटी करता था लेकिन दुख तब होता है माननीय मंत्री मंगल पाण्डे जी तेज–तर्रार मंत्री हैं ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए न ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : पंकज जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आपको भी मौका मिलेगा तो अपनी बात रखेंगे ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : सभापति महोदय, माननीय मंगल पाण्डे जी यहां बैठे हैं बहुत तेज–तर्रार मंत्री हैं लेकिन दुख तब होता है कि जब माननीय मंत्री जी अस्पताल का निरीक्षण करने जाते हैं, तो जूता में जो कैप पहनने के लिए दिया जाता है उसको सिर पर पहना दिया जाता है, यह चिकित्सकों के द्वारा माननीय मंगल पाण्डे जी के जूता में पहनने वाला कैप को माथा में पहना दिया जाता है, यहां इस तरीके की व्यवस्था है । डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की बात कही जाती है लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी जी जब पी0एम0सी0एच0 में रात में जाकर छापेमारी करते थे, वहां पर जो डॉक्टर, जो अधीक्षक, डॉक्टर आई0एस0 ठाकुर जिस तरीके की कार्रवाई उनपर देखने को मिला, भाई जब वे अस्पताल में गए तो देखें कि चारों तरफ गंदगी का अंबार था, डॉक्टर आई0एस0 ठाकुर पर जब उन्होंने कार्रवाई की बात कही तो सरकार के आला–अधिकारियों ने डॉक्टर

आई0एस0 ठाकुर को बचाने का काम किया और दुख तब होता है कि जब डॉक्टर आई0एस0 ठाकुर रिटायर हो गए थे, संविदा पर उनको रखा गया, बार–बार एक जाति विशेष के लोगों को संविदा पर, संविदा पर, संविदा दिया गया और उसके बाद संविदा कर्मी में जो सरकार का संकल्प है कि संविदा कर्मी को वित्तीय प्रभार नहीं देना है, डॉक्टर आई0एस0 ठाकुर के द्वारा वित्तीय अनियमितता का मामला है, दवा घोटाला का मामला है, उपकरण खरीदने में उन्होंने घोटाला किया है, बहुत सारे घोटाले किए हैं उसके बावजूद उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जाता है ।

महोदय, अभी पी0एम0सी0एच0 के अंदर बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है लेकिन वहां पर स्थायी चिकित्सक नहीं हैं । महोदय, अगर एक से एक योग्य चिकित्सक हैं तो उनको अधीक्षक क्यों नहीं बनाया गया ? 2022 में बजट सत्र में तत्कालीन मंत्री उस समय में भी मंगल पाण्डे जी थे मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया कि पी0एम0सी0एच0 को स्थायी अधीक्षक कब दिया जाएगा, तो इन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि 1 अप्रैल, 2022 स्थायी अधीक्षक की बहाली कर देंगे लेकिन आज तक वहां स्थायी अधीक्षक नहीं मिला है और उसके बाद...

(व्यवधान)

सरकार बनी अगस्त में, आपको पता है । सरकार अगस्त में बनी है । और जिस तरीके से डॉक्टर आई0एस0 ठाकुर को रातों–रात अंधेरे में फाइल लेकर और मुख्यमंत्री जी से दस्तखत कराकर रात के अंधेरे में सारे नियम–कानून को ताक पर रखकर और उसको एक्सटेंशन दिया गया । महोदय, हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है पी0एम0सी0एच0 में, डॉक्टर आई0एस0 ठाकुर, डॉक्टर है कि इंजीनियर है ? आपने अभी जवाब दिया है आज से दस दिन पहले कि अस्पताल का जो देखरेख है उनके अनुश्रवण में ही हो सकता है, अगर भगवान न करें किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटे, अगर डॉक्टर आई0एस0 ठाकुर को अगर कुछ हो गया तो क्या उसके बाद पी0एम0सी0एच0 बनेगा या नहीं बनेगा ? माननीय मुख्यमंत्री जी आज बोल रहे थे कि बहुत दुख हो रहा है कि दस साल में दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो 2019 में उनको ऐसा सपना आया कि दुनिया समाप्त हो जाएगा, अगर दुनिया समाप्त हो गया तो फिर मुख्यमंत्री जी का क्या होगा ? 2019 में उनको यह सपना आया तो मोबाइल फेंक दिए, लेकिन आज 2025 है 6 साल 10 साल में से माइनस हो गया बचा 4 साल, अब बताइए कि 4 साल बचा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी किस–किस को खुश करेंगे । कभी प्रधानमंत्री जी के पैर पर गिरेंगे, कभी अपने मंत्री के पैर पर गिरेंगे या अपने आला–अधिकारियों के पैर पर गिरेंगे । महोदय, यह बिहार को शर्मसार करने वाली बात है । बार–बार ये लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी

की मांग करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं, विशेष पैकेज की मांग करते हैं लेकिन इनको मिलता क्या है ? इसी जगह बिहार में आरा में आते हैं प्रधानमंत्री जी और बिहार की बोली लगाकर जाते हैं कहते हैं 1 लाख करोड़ दूं कि सवा लाख करोड़ दूं कि डेढ़ लाख करोड़ दूं लो दिया, डेढ़ लाख करोड़ दिया लेकिन मिला क्या आज तक ठेंगा के नाम पर और तो कुछ मिला नहीं, यहां झुनझुना और लॉलीपॉप थमाया जाता है । महोदय, जिस तरीके से बिहार के अंदर स्वास्थ्य विभाग का हाल है ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य मुकेश जी, विषय पर बात करें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : बिल्कुल विषय पर ही बोलेंगे महोदय । महोदय, जिस पर घोटाला का आरोप रहता है, सारे नियम–कानून को ताक पर रखकर पी0एम0सी0एच0 के अंदर लूट–खसोट जारी है । महोदय, जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था की गई है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके द्वारा 25 हजार रुपया कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पर उठाया जाता है, उसको मिलता कितना है, 12 हजार रुपए मिलता है । सुरक्षा प्रहरी का 18 हजार रुपया उठाता है देता कितना है 8 हजार रुपया, पूरे राज्य में इस तरीके का माहौल है । जब मैं सदर अस्पताल, हाजीपुर गया तो वहां आउटसोर्सिंग वाली कंपनी के स्टाफ को जब मैंने बुलाकर पूछा कि आपको कितना वेतन मिलता है तो उन्होंने कहा 18 हजार मिलता है, इन हैंड कितना मिलता है तो 10800, बाकी कहां जाता है ? यह बताना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है कि डबल घपलेबाजी की सरकार है, जिस तरीके से हमारे यहां चेहराकलां में सी0एच0सी0 का निर्माण हुआ, उस समय 2020 में मात्र 1 करोड़ 70 लाख के आसपास में निर्माण हुआ था, आज वहां नया पी0एच0सी0 जा रहा है तो उसका एस्टीमेट देख रहे हैं कि 5 करोड़ 75 लाख, कहीं न कहीं लगता है कि बिहार में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, भवन निर्माण के नाम पर बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के तहत अस्पतालों का जो निर्माण हो रहा है उसमें कहीं न कहीं लगता है कि एस्टीमेट घोटाला किया जा रहा है । आज से 5 साल पहले डेढ़ करोड़ में वह भवन बनता था, आज पौने 6 करोड़ में बन रहा है, कहीं न कहीं इस बीच की जो राशि है उसमें बंदरबांट किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

एक बात बताइए न कि पी0एम0सी0एच0 में जो आई0एस0 ठाकुर है वह डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि बिना उनके पी0एम0सी0एच0 का निर्माण हो ही नहीं सकता । हमारे यहां पटना में पी0डी0सी0एच0 है, पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैं भी एक दंत चिकित्सक हूं और दंत चिकित्सकों का दुख मैं जानता हूं, किस तरीके से वे अपना भरण–पोषण करते हैं । 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, बी0पी0एस0सी0 के तहत उस समय दंत चिकित्सकों की बहाली

कराई गई थी आज क्या स्थिति है ? आज हजारों–हजार डेंटिस्ट जो है वह रोड पर नौकरी के बाट जोह रहे हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ की बहाली होनी चाहिए, पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली होनी चाहिए और लैब टेक्नीशियन की बहाली होनी चाहिए । कोरोना काल में जिस तरीके से नर्सिंग स्टाफ ने काम किया, अभी बिहार तकनीकी संस्थान से उनकी बहाली निकाली गयी है, कोरोना काल के समय इन लोगों ने जो काम किया, उनका जो अनुभव मिलना चाहिए, वे संविदा पर उस समय काम कर रहे थे, उनका अनुभव उस बहाली की प्रक्रिया में जोड़ा नहीं जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लैब टेक्नीशियन, पारा मेडिकल, डेंटिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन की बहाली हो तो कोरोना काल के समय में जो काम किए हैं, उनका जो अनुभव है उसको जरूर जोड़कर उनको अंक निर्धारण करना चाहिए । आप ही के डबल इंजन की सरकार में और अन्य राज्यों में 5 अंक दिया गया है, जो काम किए हैं, उसी तरह यहां पर भी काम मिले । जिस तरीके से मिशन 60 के तहत हमारे नेता ने अस्पतालों में इवनिंग ओ0पी0डी0 की व्यवस्था की थी, आज इवनिंग ओ0पी0डी0 बंद हो गया है । जिस तरीके से दवा मिल रही थी, अभी हमको कल सूचना मिली कि वैशाली में सी0एच0सी0 है, वैशाली प्रखंड में जो सी0एच0सी0 है वहां पर एक्सपायरी दवा दी जा रही है इससे शर्म की बात क्या होगी ? जहां हमारे नेता 600 मेडिसीन का लिस्ट टंगवाने का काम किए थे अस्पतालों में आज क्या व्यवस्था है ? मरीज को अगर एक्सपायरी दवा दी जाएगी तो वह उससे बचेगा या मरेगा यह आप ही बता सकते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–23 / पुलकित / 20.03.2025

(क्रमशः)

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में खराब पड़े उपकरण को ठीक करने हेतु अहम कार्य किये गये । जिला अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की बहाली की गयी और डॉक्टरों को प्रोन्नति दी गयी । सेंट्रल सैम्पल और ब्लड कलेक्शन सेंटर की व्यवस्था की गयी । जिस तरीके से वेटिंग एरिया, ओ0पी0डी0 के समय व्यवस्थित की गयी । लॉन्ड्री सर्विसेज, हैंडवॉशिंग वेशिन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और हैंडवॉश फैसिलिटीज, लूज हैंगिंग इलेक्ट्रिक वर्क को सही किया गया । जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय है । महोदय, तेजस्वी जी जब भी कहीं निकलते थे तो जरूर कहीं न कहीं सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल या कहीं पी0एच0सी0 में जाकर के छापेमारी करते थे, देखते थे कि डॉक्टर हैं या नहीं । लेकिन आजतक मैंने मंगल पाण्डे जी को नहीं देखा कि वह किसी भी सदर अस्पताल में जाकर और

वहां छापेमारी करके देखने का काम करें कि वहां आपके मरीज का इलाज हो रहा, नहीं हो रहा ? महोदय, एक बार विधानसभा की कमेटी लेकर के हम मुजफ्फरपुर गये थे । यहां पर बैठे हुए थे अवधेश जी, लगता है कि अभी चले गये । निवेदन समिति के सभापति के रूप में वे गये थे और हम और विजय सम्राट जी भी साथ में गये थे । वहां जब गये तो देखें, यह पिछले वर्ष की बात है कि वहां सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर में जहाँ मरीज के इलाज कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां उस बेड पर कुत्ता सो रहा था और पानी घुटने तक भरा हुआ था । महोदय, कैसी सुशासन की व्यवस्था है, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है ? इसका मंत्री जी को जाकर के औचक निरीक्षण करना चाहिए । जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि भाई किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी और अब इनका 2047 चला गया है । जो हम लोग नये भारत का निर्माण करेंगे, उसमें 2047 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी । किसानों की दुगनी आमदनी के नाम पर किसानों को कबतक छलने का काम करेंगे । किसानों के साथ ये लोग छलावा करने का काम करते हैं । किसानों को कम से कम प्रति एकड़ 10 लाख रुपये का एक क्रेडिट कार्ड के रूप में क्रेडिट कार्ड देना चाहिए ताकि उस किसान को अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने के लिए या शादी–विवाह के लिए उनको एक सहायता मिले या एक फसल लगाने के लिए उनको एकमुश्त राशि मिल जाए ताकि किसी के सामने उनको हाथ नहीं फैलाने पड़े । जिस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग की बात है । आपदा के समय वर्ष 2021 में हमारे क्षेत्र में सामुदायिक किचन की शुरूआत जिला पदाधिकारी के निर्देश पर की गयी थी । लेकिन वहां के अंचल अधिकारी द्वारा आपदा को भी अवसर बना दिया गया और आज तक 20 लाख से ऊपर उसकी राशि हो गयी, आज तक जो संचालन करता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उस समुदायिक किचन का जो संचालन कर रहे थे, उसका आजतक पेमेंट नहीं हुआ और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है । कोरोना काल में सभी माननीय सदस्यों का पैसा काटा गया ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आपके पास दो मिनट बचे हैं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, दो मिनट काफी है । महोदय, जो दो–दो करोड़ रुपया काटा गया, उस पैसे से क्या विकास किया गया ? किस–किस माननीय के क्षेत्रों में क्या व्यवस्था दी गयी, उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को डिटेल बतानी चाहिए । हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट लगा ? भारत सरकार के मंत्री जाकर के वहां ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास करते हैं और आज तक वह शिलान्यास, शिलान्यास ही रहा गया । हमारे क्षेत्र के बगल में अनुमंडल पातेपुर है, भारत सरकार के माननीय मंत्री जी वहां जाकर के शिलान्यास करते हैं आज तक वहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं बना । हमारे यहां जो ऑक्सीजन प्लांट है, उसको चलाने के लिए वहां टेक्निशियन नहीं है, उसके लिए स्टेबलाइजर नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए । इसके अलावा जो एन0आई0सी0यू0 की व्यवस्था होनी थी

। वर्ष 2020 से वहां उपकरण लाकर के रखा गया है । उस उपकरण पर धूल पड़ी हुई हैं उसको एस्टैब्लिशमेंट कराने के लिए पहल करनी चाहिए । जिस तरीके से हाजीपुर सदर अस्पताल के नये भवन का जो निर्माण हुआ है, उसको जाकर के उच्चस्तरीय टीम से जांच करानी चाहिए क्योंकि वह सदर अस्पताल जो बना, उसमें चार नंबर ईंट लगायी गयी । उसमें कई बार हम लोगों ने जाकर के वहां जिला प्रशासन के लोगों को कहा कि इसकी जांच की जाए लेकिन आज तक वह जांच लंबित है, उस पर कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुई । जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सी0एम0 और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे तब उस समय कार्रवाई और सुनवाई होती थी । जो डॉक्टर महीनों–महीनों तक गायब रहते थे, जो नर्सिंग स्टाफ गायब रहता था, जो पैरामैडिकल स्टाफ गायब रहता था, उसके ऊपर कार्रवाई और सुनवाई हुई । उसके तहत कई डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई और उसके तहत उसको सस्पेंड किया गया । लेकिन आज क्या है ? सदर अस्पताल में 70–70 स्टाफ बैठा हुआ है लेकिन दूरदराज के इलाके में पी0एच0सी0 में, सी0एच0सी0 में जहां डॉक्टर होना चाहिए, वहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो सुदूर इलाका है, जो एडिशनल पी0एच0सी0 स्तर का जो सेंटर है ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : उसमें दंत चिकित्सकों की भी बहाली की जाए और जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उसकी भी बहाली की जाए । बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : धन्यवाद । अब माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह अपना पक्ष रखेंगे । आपका समय मात्र 6 मिनट है ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

(व्यवधान)

सही–सही बोलेंगे । सत्यदेव बाबू, आप भी सही–सही बोलियेगा ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने आज हमको बोलने का अवसर दिया है । हम आभार प्रकट करते हैं अपने द्वि–उपमुख्यमंत्री का जिनके नेतृत्व में चमकता बिहार और दमकता बिहार और यह आगे बढ़ता बिहार दिखाई पड़ रहा है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम आज सरकार की ओर से लाये गये प्रस्ताव के, जो सदन में रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । महोदय, हम यूं हीं खड़े नहीं हुए हैं, यूं ही हम समर्थन में बोलने के लिए नहीं आए हैं । हम केवल सत्ता पक्ष के हैं इसलिए केवल समर्थन में बोले यह जरूरी नहीं है । हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जब 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के नाते एक कार्यकर्ता जो बीमार था, उसको पी0एम0सी0एच0 मैं लेकर गया तो मैंने

पी0एम0सी0एच0 में देखा कि एक दीवार पर अंकित है कि यहाँ प्रति मरीज 25 पैसे की दवा उपलब्ध कराई जाती है । यह कितनी शर्म की बात हैं । 25 पैसे में कौन सी दवा आपकी सरकार उपलब्ध कराती थी ? पूरे बिहार में यही हालात थे कि 25 पैसे की दवा पी0एम0सी0एच0 में उपलब्ध करायी जाती थी ? आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, पी0एम0सी0एच0 के बेड बढ़ रहे हैं, आई0जी0आई0एम0एस0 का बेड बढ़ रहा है । आज राजबंशी नगर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है और आपके जमाने में क्या होता था ? आपके जमाने में डॉक्टरों का अपहरण करके मुख्यमंत्री आवास में पहुंचाया जाता था, वहां फिरौती की रकम तय होती थी और उस समय डॉक्टरों के फिरौती की रकम उस आवास से तय होती थी, बिहार से डॉक्टर पलयान कर रहे थे । हमारे मित्र ने ठीक कहा कि डॉक्टर रमेश चंद्र पलायन कर गये थे, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी हम सब लोगों से काफी जुड़ाव रखने वाले वर्षों–वर्ष के लोग हैं, उनके साथ जो कुछ बिहार के अंदर हुआ वह शर्मसार करने वाला था । उस शर्मसार बिहार से निकलकर आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जाइये । हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मंगल पाण्डे जी को जिन्होंने हमारे लालगंज विधानसभा क्षेत्र को एक 30 बेड का हॉस्पिटल दिया है, 50 बेड का अस्पताल निर्माण कराकर के पूर्णतः वातानुकूलित चालू कराया है और आज 19–19 पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं । यह काम हमारे मंत्री महोदय ने किया है, मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में किया है । अध्यक्ष महोदय, ये वे लोग हैं जो अपना स्वास्थ्य तो बिगाड़ते ही है, अभी मुकेश रौशन जी चले गये, मेरे जिले के हैं । असत्य का पुलिंदा लेकर आए थे।

अध्यक्ष : संक्षेप में अपनी बात कहिये । केवल एक मिनट है आपके पास ।

श्री संजय कुमार सिंह : अभी यहां वैशाली के माननीय सदस्य हमारे बैठे हैं । वह कह रहे थे कि वैशाली में मरीज को एक्सपाइरी दवा दी गयी । मैं चुनौती देता हूं वह जांच कराई गयी थी । वैशाली के अंदर डॉक्टर ने किसी चीज की दवा को लिखा ही नहीं, उस दवा को ये लोग केवल पुलिंदा बांधकर गये । ये सरकार को बदनाम करने के लिए गये थे, यह सरकार बदनाम होने वाली नहीं है। यह सरकार सत्य के आधार पर चलती है और आज जांच के बाद निकलकर आया कि आपने सरकार को बदनाम करने के लिए वह पुलिंदा दिखाया था ।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार चमकता बिहार, दमकता बिहार की सरकार है और स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्स बन रहा है । आज पी0एम0सी0एच0 का बेड बढ़ रहा है । राजवंशी नगर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है और हजारों–हजार रुपये की दवा एक–एक मरीज को मिल रही है । आपके जमाने में 25 पैसे की दवा दी जाती थी । मैं तो शर्मसार रह गया कि 25 पैसे की भी दवा किसी मरीज को दी जाती हो, यह पी0एम0सी0एच0 की दीवार पर अंकित था । जब माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार बनाकर आए थे तो मैंने सोचा कि

माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी माध्यम से सूचित करूं कि यह दीवार पुतवाइये क्योंकि आज हजारों–हजार रुपये की दवा मरीजों को मिल रही है और यह 25 पैसे वाली बात जो आर0जे0डी0 के शासन में लोग थे, तेज प्रताप जी जैसे लोग स्वास्थ्य मंत्री हो गये और आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल जी जैसे लोग हैं देखिए पूरे बिहार में स्वास्थ्य सेवा ठीक है । आपके तेज प्रताप जी क्या किये ? कुछ नहीं किये ? केवल, केवल, केवल, केवल, केवल यही काम अस्पतालों में जाकर उगाही करने का काम, यह काम हुआ था ।

(क्रमशः)

टर्न–24 / अभिनीत / 20.03.2025

..क्रमशः..

श्री संजय कुमार सिंह : आज मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में अस्पतालों में लोगों की चिकित्सा हो रही है, मरीज ठीक होकर जा रहे हैं । आपके समय में कितने लोग थे..

अध्यक्ष : संजय जी, अब समाप्त कीजिए । समय आपका समाप्त हो रहा है ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं–

''अंधेरों में दीया जलाने चला हूं

जो वादा किया, वह निभाने चला हूं

आप चाहे कितनी भी बेड़ियां हमारे पांव में बांधें

हम बिहार को चमकाने चले हैं

हम चांद को जमीन पर उतार देने वाले हैं ।''

बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान जी । दो मिनट समय है ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, मैं एक शेर से शुरू करता हूं–

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,

ये आंकड़ें आपके झूठे हैं ।

महोदय, चमचमाते भवन, बड़े–बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आप बना लीजिए लेकिन गांव के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, 2005 से पहले उसकी स्थिति

क्या थी, इतना बेहतर था कि वहां ड्रेसर हुआ करते थे, वहां कंपाउंडर हुआ करते थे, वहां गरीबों का इलाज होता था । महोदय, आज गांवों के अस्पतालों पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप जो ठेकेदारों को, सफाईकर्मी नियुक्त किये हैं, सच यही है कि आठ–आठ सफाईकर्मी का वह ठेकेदार अस्पताल के नाम पर पैसा उठाता है लेकिन वहां दो सफाईकर्मी रहते हैं, यह सच है । मैंने अस्पताल जाकर उसको देखा है । महोदय, पटना के पी0एम0सी0एच0 या आई0जी0एम0एस0 जाइये, अभी भी यहां पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो इमरजेंसी के बगल में शौचालय है उसमें रौशनी नहीं है, बल्व नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : दो ही मिनट में एक मिनट कैसे बढ़ा दें ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, संरक्षण चाहिए । आज कृषि के बारे में, बेगूसराय जिला का एक मात्र एकलौता मक्का अनुसंधान केंद्र था । महोदय, राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में रहने दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्येन्द्र यादव । दो मिनट आपका समय है । सत्येंद्र जी, बोलिए । अपनी बात कहिए ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हूं । 03 लाख 17 हजार करोड़ रुपये के बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो समाजिक रूप से हाशिए पर खड़े लोग हैं उनका यह अधिकार बनता है लेकिन यह XXX सरकार पिछले 400 रुपये से एक रुपया बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है जबकि केरल की सरकार 3000 हजार रुपये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन देती है लेकिन यह डबल इंजन की सरकार, जिसकी सरकार में गरीब और पिछड़े, दलित, अकलियत, जो विधवा और विकलांग हैं, जो बुर्जुग हैं उनको पेंशन देने से भी ये लोग इंकार करते हैं और ये लोग बात करते हैं समाज के विकास का, यह समाज का विकास नहीं बल्कि इनके डबल इंजन की सरकार में हाशिए पर खड़े विधवा, विकलांग और वृद्धजनों को कुचला जा रहा है । मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जरा भी नैतिकता बची है तो आप 03 लाख 17 हजार करोड़ के बजट में कम से कम केरल मॉडल के नाम पर 03 हजार पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लागू करना चाहिए लेकिन आपकी XXX इस कदर बढ़ गयी कि आपने उनके सवालों पर विचार करने से भी इंकार कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का डंका बज रहा है लेकिन हेल्थ एण्ड वेलनेस

सेंटर के नाम पर जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने खेल किया, बिहार के अंदर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर कहीं का काम नहीं कर रहा है ।..

अध्यक्ष : XXX शब्द को प्रोसीडिंग्स से हटा दिया जाय ।

श्री सत्येंद्र यादव : निर्माण ही नहीं हुआ । गांव के अंदर न डॉक्टर हैं, न नर्स हैं, ये झूठ का पुलिंदा लेकर आये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं के राज में जो लोग बीमार पड़ते हैं या इन्हीं के राज में जो एक्सीडेंट होकर प्राइवेट हास्पिटल में आते हैं, लाश छोड़ने के लिए भी पैसा मांगा जाता है, जो पैसा नहीं देते हैं उनकी लाश छोड़ी नहीं जाती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

....

XXX – इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

....

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान । एक मिनट आपका समय है ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, न्याय के साथ तरक्की की सरकार है । मेरे यहां 9 डॉक्टरों की जगह पर सिर्फ दो डॉक्टर हैं । बैसा के एक डॉक्टर को फल्का में डिप्युट कर दिया गया है । उनका डिप्युटेशन तोड़ा जाय । पी0एच0सी0 रसूलगंज में कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर दिया जाय । पांच लाख की आबादी में कोई ग्यानोकोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे यहां दिया जाय । अग्निपीड़ितों की अनुग्रह राशि कम से कम 50 हजार की जाय । किसान सलाहकारों को बहाल किया जाय । वृद्धा पेंशन 3000 प्रति माह किया जाय । महोदय, इसीलिए एक आंकड़ा सुनाउंगा । नालंदा में एक लाख पर 9 डॉक्टर हैं, जहानाबाद में 13 डॉक्टर हैं, मुंगेर में 9 हैं लेकिन सीमांचल के साथ नाइंसाफी है । किशनगंज में 03 डॉक्टर हैं । अररिया में 03 हैं, कटिहार में 03 हैं, पूर्णियां में 05 हैं और मेरे अमौर में एक लाख पर 02 डॉक्टर हैं । महोदय, इंसाफ किया जाय । हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, एक पंक्ति सुनाना चाह रहा हूं जरा सुन लीजिए । होली का रंग अभी बाकी है ।

अध्यक्ष : शेर पढ़िए ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय,

''बहकी–बहकी बातें करता है वो, बादशाह बीमार तो नहीं है,

अफसरशाही का बाजार गरम है, सरकार कहीं लाचार तो नहीं है ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी । तीन–चार मिनट में बात समाप्त कीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में तथा सरकार द्वारा लाये गये बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, बढ़ता भारत, चमकता बिहार जिसमें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है जिनके कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर भाड़ी सुधार हुआ है । स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पाण्डे जी एवं स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी के कुशल नेतृत्व में दिन दुगुणा रात चौगुना प्रगति कर रहा है । मंगल जी के स्वास्थ्य विभाग में आते ही मंगल ही मंगल हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने एवं दूर–दराज गांव तक सेवा उपलब्ध कराया गया है । विपक्ष के लोग बहुत बोल रहे थे, 2005 वाला जो देखें हास्पिटल में कभी डॉक्टर नहीं रहते थे, न सूई रहती थी और वहां पर कुत्ता बैठता था । हम भी देखे हुए हैं जो स्वास्थ्य मंत्री थे वे स्वस्थ नहीं थे इसलिए बिहार अस्वस्थ हो गया था । आज स्वास्थ्य मंत्री स्वस्थ हैं, स्वस्थ के हाथों में गया है, हमारे मुख्यमंत्री बिहार में चमकाने का काम किये हैं, इसलिए आपलोग बहुत ज्यादा अट–पट न बोलिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब संक्षिप्त कीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : राज्य में 18 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया जिसमें पांच बनकर तैयार हैं और 13 जगहों पर निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है । पूर्णियां, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा तथा सारण में बन गया है और सीतामढ़ी, मुंगेर, सुपौल, बेगूसराय, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई, भोजपुर, बक्सर में तेजी से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, 13 सदर अस्पतालों में मॉडल अस्पताल का निर्माण हो गया है । 25 में स्वीकृति दी गयी है । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डे जी तथा श्री प्रत्यय अमृत जी के प्रयास से आज पटना के आई0जी0आई0एम0एस0

अस्पताल को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अस्पताल का दर्जा प्राप्त हुआ है । अस्पताल में 500 बेड का अतिरिक्त भवन बनकर तैयार है, वहीं पर 1200 बेड का एक और भवन बनाया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मेडिकल के छात्रों को हिन्दी या अंग्रेजी में पढ़ाई की सुविधा प्रदान की गई है । इसके लिए मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं । प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय मंत्री श्री मंगल पाण्डे जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देती हूं । महोदय, 2005 से पहले प्रति महीने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र..

अध्यक्ष : गायत्री जी, अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, एक मिनट । हमको पांच मिनट समय दिए है, बस एक मिनट ।

टर्न–25/हेमन्त/20.03.2025

अध्यक्ष : अब आपका समय हो गया है ।

श्रीमती गायत्री देवी : बिहार में इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है, विकास के आधार पर जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में बागडोर सौंपी है और एक कहानी कही जाती है– चलनी हंसलन बढ़नी के, अपने बहत्तर गो छेद ।

तो वही हाल है और बिहार में कहा जाता है कि "बिहार में का बा", तो बिहार में नीतीश कुमार बा । फिर बिहार में 2025 में 225 लेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनायेंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती मनोरमा देवी ।

श्रीमती गायत्री देवी : मैं गारंटी के साथ बोलती हूं और गारंटी के साथ काम करती हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती मनोरमा देवी । बोलिये ।

श्रीमती गायत्री देवी : इसलिए आप लोग अस्वस्थ हैं ।

अध्यक्ष : बोलिये । चार–पांच मिनट में अपनी बात खत्म करिये ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, आप समय दिये इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : चार–पांच मिनट में खत्म करिये ।

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको कोटि–कोटि धन्यवाद देती हूं । साथ ही, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं हमारे दल के सचेतक श्रवण बाबू को भी मैं धन्यवाद देती हूं । मैं बेलागंज की महान जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे सदन तक पहुंचाने का आशीर्वाद दिया ।

महोदय, आज मैं स्वास्थ्य, कृषि एवं समाज कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में तथा सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को विकास अब पच नहीं रहा है । हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किये हैं । महोदय, हमारी एनडीए सरकार गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने हेतु दृढ़ संकल्पित है । स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं सुधार हुआ है । महोदय, एनडीए सरकार से पूर्व की सरकार के समय में बिहार से डॉक्टरों का पलायन होता था । जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी है, तब से डॉक्टर बिहार में बड़े–बड़े अस्पताल खोल रहे हैं । महोदय, राज्य को दिनांक 4, 5 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 24 में इनोवेशन अवार्ड भी राज्य को प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : मनोरमा जी, आपके अपने क्षेत्र की कुछ बात है, तो बोल लीजिए । समय नहीं है आपके पास ।

श्री मनोरमा देवी : महोदय, राज्य के सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है । प्रारंभ में 23 सदर अस्पतालों को विकसित किया जा रहा है, इनमें से 12 स्थलों यथा वैशाली, गया, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, सीतामढ़ी इत्यादि का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान 22 करोड़ की लागत से 100 बेड का मॉडल अस्पताल प्रभावती गया का उद्‌घाटन किया गया, जो गया के आम जनों के लिए वरदान साबित होगा इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि–कोटि धन्यवाद देती हूं । महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि गया जिला अंतर्गत बेलागंज प्रखंड के कोरियावा पंचायत के मेन गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मेनगांव स्थित उक्त स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाय ।

महोदय, कृषि विभाग पर भी मुझे बोलना था ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्रीमती मनोरमा देवी : महोदय, बस एक लाईन । महोदय, मुझे कृषि विभाग पर भी बोलना था, समाज कल्याण पर भी बोलना था । महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि हमारी एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार चमचमा रहा है । कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान इतने शिक्षित हुए हैं कि फसलें लहलहा रही हैं और समाज कल्याण में हम महिलाओं को भी बोलने का मौका मिला है । यह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे एनडीए के साथियों की देन है और मैं कहना चाहती हूं विरोधियों से कि आप लोग सच्चाई के चश्मे से देखें कि जब से हमारे मुख्यमंत्री जी का शासन आया है, हमारा बिहार जगमगा रहा है और भारत के नक्शे पर हमारा बिहार चमचमा रहा है ।

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्रीमती मनोरमा देवी : महोदय, देश–विदेश के भी लोग आ रहे हैं और हमारे बिहार की प्रशंसा पूरे देश–विदेश में है ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्रीमती मनोरमा देवी : इन्हीं चंद शब्दों के साथ आभार प्रकट करती हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं महोदय।

अध्यक्ष : श्रीमती दीपा कुमारी ।

श्रीमती दीपा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया...

अध्यक्ष : देखिये, लगातार महिलाएं ही बोल रही हैं । अब तो भरोसा करिये, जो कह रही हैं उस पर ।

श्रीमती दीपा कुमारी : इसके लिए आपको कोटि–कोटि धन्यवाद । सबसे पहले अपने विधान सभा की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करती हूं और दल के संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं । बिहार सरकार द्वारा दिनांक 3 मार्च को बिहार विधान सभा में पेश बजट का मैं समर्थन करती हूं । यह बजट बदलते बिहार का है जिसमें भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि विकास की चर्चा है । राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गरीब मरीजों का इलाज होता है । मौलिक एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्या शुरू की गयी है इसके तहत डॉक्टर मरीजों को ऑनलाईन देखकर उनको दवाइयां और जांच प्रेसक्राइब किया जा रहा है । इस तकनीक से मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाईन सुरक्षित रखी जा रही हैं । महाशय, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है । इसके लिए बिहार को इनोवेशन अवार्ड मिल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले सरकारी अस्पताल तो थे लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों के नहीं रहने के कारण यह लूट का अड्डा बना हुआ था। कागज पर ही मरीजों का इलाज हुआ करता था । पी0एच0सी0 में व्याप्त गंदगी के कारण मरीज भी नहीं आते थे । महीने में मात्र 9 मरीज यहां पर अपना इलाज करवाने आया करते थे। वह भी यहां की व्यवस्था देखकर प्राईवेट अस्पतालों में इलाज के लिए चले जाया करते थे, लेकिन अब बिहार बदल रहा है । बदलते बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आ गयी है । ऑनलाईन और ऑफलाईन डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं । पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5462 बिस्तरों वाला दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विस्तारित किया जा रहा है । साथ ही, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से दरभंगा एम्स का भी शिलान्यास किया गया है । आने वाले वर्षों में ये दोनों अस्पताल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होंगे । बिहार में हिन्दी और अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई करने का विकल्प हो, इसके लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई हिंदी में भी करने की शुरूआत की गयी है ।

अध्यक्ष : संक्षेप करिये अब ।

श्रीमती दीपा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, शिशु मृत्यु दर 2005 में 61 थी, जो घटकर 27 हो गयी है इसके लिए सरकार के स्तर पर अभी भी काम चल रहा है कि कैसे इसे और कम किया जाय । मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2004–06 में 312 था इसमें भी कमी आयी है । प्रदेश के 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनकर तैयार हो गये हैं । इसे जन उपयोग के लिए जनता को समर्पित कर दिया गया है । इसके साथ ही 10 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है । कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े इसके लिए भी सरकार की ओर से कई प्रकार के काम किए जा रहे हैं । इस तरह से स्वास्थ्य सेवा में सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और आगे के लिए बड़ी कार्य योजना के साथ हम बढ़ रहे हैं जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । अध्यक्ष महोदय, उसी तरह 2025–26 के बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है । प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्रीमती दीपा कुमारी : सरकार पूरे राज्य के...

अध्यक्ष : दीपा जी, अब समाप्त करिये ।

श्रीमती दीपा कुमारी : सर, मैं पहली बार बोल रही हूँ ।

अध्यक्ष : अपने क्षेत्र की बात भी तो बोल लीजिए न आप । सरकार को भी जवाब देना है न।

श्रीमती दीपा कुमारी : सर, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : इसीलिए मैंने आपको दो मिनट ज्यादा दिये ।

श्रीमती दीपा कुमारी : मेरे भाषण को प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(माननीय सदस्या श्रीमती दीपा कुमारी का लिखित वक्तव्य–परिशिष्ट द्रष्टव्य)

माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा ।

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री मंगल पांडे, मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं सदन में बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अगर आप महिलाओं के खिलाफ बोलियेगा, तो खाना नहीं मिलेगा घर में ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, द्वय उपमुख्यमंत्री का कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे इस कैबिनेट में काम करने का अवसर दिया है और आज स्वास्थ्य विभाग की चर्चा में मैं मंत्री के रूप में अपने विषयों को सदन में रख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को दो पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा–

''आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जायेगा, उस दिये से पूछना मेरा पता मिल जायेगा ।''

महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार लगातार पिछले 20 वर्षों से स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और इन बीस वर्षों में कई नवाचार एनडीए की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया है। इन्हीं बीस वर्षों में कोविड–19 की वैश्विक महामारी को भी हम सब लोगों ने झेला ....

(क्रमशः)

टर्न–26 / धिरेन्द्र / 20.03.2025

....क्रमशः....

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, और वैसी लोक आपदा के समय में भी हम सब लोगों ने अपने राज्य की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी और उसके बाद आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की एक नई लकीर हमलोगों ने खींचने का काम शुरू किया है । मानव संसाधन के क्षेत्र मे भी क्षमतावर्धन और नयी नियुक्तियों की दिशा में सरकार के द्वारा लगातार सकारात्मक कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है ।

महोदय, यह बिहार वही है जहाँ पहले स्वास्थ्य विभाग को यह देखा जाता था कि विभिन्न मानकों में कि नीचे से कितने पायदान पर खड़ा है लेकिन 20 वर्षों में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है आज स्वास्थ्य विभाग के कई मानक इस देश के अंदर उस स्थान पर पहुँच गए हैं कि अब ऊपर से गिनती होती है कि स्वास्थ्य सेवा के इस काम में एक नंबर पर है, दो नंबर पर है, तीन नंबर पर है, मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा और मैं माननीय सदस्यों को उन मानकों की भी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आज बिहार एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर पर है और कुछ काम तो ऐसा कर रहा है बिहार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो किसी राज्य ने नहीं किया है, बिहार ने उसकी शुरूआत की है, वह भी मैं बताउंगा ।

महोदय, आधारभूत संरचना के निर्माण में जो हम सब लोगों ने काम किया है विभिन्न अस्पतालों के जो उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का काम किया है, उस संदर्भ में चार पंक्तियां मैं कहना चाहूँगाः–

न पूछो की मेरी मंजिल कहाँ है,

अभी तो सफर का इरादा किया है ।

न हारूंगा हौसला उम्रभर,

यह मैंने खुद से वादा किया है ।

महोदय, और इसी के साथ अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने इस देश का ही नहीं, दुनिया के दूसरे बड़े अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं और उसके फर्स्ट फेज का काम अब पूर्ण हो चुका है, बहुत शीघ्र उसका हम सब लोग उद्घाटन करने वाले हैं और उस दिन संपूर्ण भारतवासी गौरवान्वित होगा जिस दिन पी॰एम॰सी॰एच॰ के फर्स्ट फेज का उद्घाटन होगा कि दुनिया के बन रहे सबसे बड़े अस्पताल का फर्स्ट फेज का हम उद्घाटन करेंगे ।

(व्यवधान)

महोदय, ललित बाबू को तो खुश होना चाहिए । दरभंगा को एम्स मिला और एम्स ही नहीं मिला....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वे आपकी प्रशंसा बहुत किये हैं ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : जी महोदय, इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भी 2500 बेड के हॉस्पिटल के रूप में बनाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी वह अब कार्यरूप ले रहा है । वहाँ का सर्जिकल ब्लॉक 400 बेड का बन चुका है, 1700 बेड का और वहाँ अस्पताल का जो शय्या बढ़ना है उसकी भी निविदा का काम पूर्ण हो गया है । महोदय, इस राज्य में लगातार नये चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना हो रही है, चिकित्सकों के कमी की चर्चा सदन में कर रहे हैं लेकिन यह भी बताना चाहिए था माननीय सदस्यों को कि 15 वर्षों की कार्यकाल में कितने चिकित्सा महाविद्यालय खुले थे 1990 से 2005 में और आज, मैं कहना चाहता हूँ कि 2005 से 2025 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमलोगों ने काम किया, 2005 में इस राज्य में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 09 मेडिकल कॉलेज थे, आज 21 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं और आगे जो बन रहे हैं, उसकी भी जानकारी देना चाहता हूँ । पाँच और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन कर तैयार हो गये हैं पूर्णियां, बेतिया, मधेपुरा, समस्तीपुर तथा सारण में और 10 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माणाधीन हैं, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, वैशाली अंतर्गत महुआ, मुंगेर, भोजपुर और सुपौल । महोदय, मोतिहारी, गोपालगंज, सहरसा, बांका, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा एवं जहानाबाद में भी नया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बनाने के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में सात नये जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उसकी भी कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि–

लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं,

सच कहता हूँ दोस्तों कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं।

आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग वही काम कर रहे हैं । महोदय, जो डॉक्टरों की बात हो रही थी वह बताना चाहता हूँ । आज राज्य में 2870 एम॰बी॰बी॰एस॰ की सीटें हैं और इसी राज्य में 2005 के पहले 1000 सीट भी नहीं होता था, आज तीन गुना बढ़ गया है यह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ । 1520 सरकारी....

(व्यवधान)

यह है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं । 1520 सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एम०बी०बी०एस० की सीटें हैं और 1350 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है आज हर साल 2870 डॉक्टर बिहार में बन रहा है पहले 1000 भी नहीं बनता था। आज यह परिवर्तन हुआ है, यह मानना पड़ेगा आपको । तर्क जो कर लीजिये लेकिन यह सत्य है, आपको मानना पड़ेगा । महोदय, केवल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों में मैं बेड की बात बता देता हूँ । महोदय, सरकारी अस्पतालों में 11,162 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 7,822 मतलब जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहार के अंदर हैं उनमें केवल 18,984 बेड है, यह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थिति है । महोदय, स्वास्थ्य संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का काम और विकास का काम लगातार हुआ, सदन में अभी चर्चा हो रही थी, एम्स दरभंगा बन रहा है । बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसको दो एम्स, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है । धन्यवाद देना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जिन्होंने बिहार को दूसरा एम्स दिया । आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर बिहार के दरभंगा में उन्होंने जमीन उपलब्ध करायी और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया और दरभंगा में एम्स के निर्माण का काम शुरू हुआ कोई दूसरे राज्य में नहीं हुआ है ऐसा, यह बिहार में हुआ है । आप सब लोगों को खुले हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए केन्द्रीय सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति । एम्स, पटना जो बना है वहाँ 248 शय्या का धर्मशाला बनवा रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ एम्स में गए थे और इन्होंने उसकी घोषणा की थी और आज उस घोषणा के बाद वहाँ धर्मशाला के निर्माण का काम चल रहा है । महोदय, चार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बने, एस०के०एम०सी०एच०, डी०एम०सी०एच०, जे०एल०एम०सी०एच०, ए०एन०एम०सी०एच० में । आज राजवंशी नगर में जो 400 बेड का हड्डी रोग के अस्पताल में जो नया एक्सटेंशन हो रहा है 400 बेड का, 400 बेड बन जाने के बाद महोदय, और वह काम इस साल पूर्ण हो जाएगा, मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूँ कि जो राजवंशी नगर में हड्डी रोग का अस्पताल है उसमें यह 400 बेड के निर्माण का काम पूरा हो जायेगा, 156 बेड अभी कार्यरत है और इसके बाद जब यह पूरा बन जायेगा तो यह देश का सबसे बड़ा हड्डी रोग का अस्पताल होगा, आप सब गौरवान्वित होंगे, यहाँ पक्ष–विपक्ष नहीं होगा, हर बिहारी गौरवान्वित होगा, सदन का हर सदस्य गौरवान्वित होगा कि देश का सबसे बड़ा हड्डी रोग का अस्पताल यदि कहीं है तो हमारे पटना में है, मैं यह कहना चाहता हूँ । आज यह संपूर्ण जो नॉर्थ इस्ट इंडिया है उसका सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में आँख का अस्पताल यदि कहीं खुला तो आदरणीय मुख्यमंत्री

जी और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रिजनल इंस्टीच्यूट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी का उद्घाटन आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰ में किया, आज नॉर्थ इस्ट इंडिया का वह सबसे बड़ा अस्पताल है । मैं माननीय सदस्यों को भी कहूँगा कि आप लोगों को भी उस अस्पताल को जाकर देखना चाहिए, ऐसे उम्र हो गया है, आँख भी दिखवा लीजियेगा तो अच्छा रहेगा । महोदय, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल का उन्नयन हो रहा है । राजकीय मानसिक अस्पताल कोइलवर में बनाया गया, वहाँ बेडों की संख्या बढ़ायी जा रही है । राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रहुई में 597 करोड़ की लागत से खुला, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और उद्घाटन किया और आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰ में महोदय, 500 बेड के अस्पताल का और उत्क्रमित हो रहा है 500 बेड, जिसमें से 250 बेड का उद्घाटन हो गया है 250 और बेड का उद्घाटन जून तक हो जायेगा । 1200 और बेड का अस्पताल बन रहा है और वह भी इस साल के अंत तक पूरा हो जायेगा और उसके बाद आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰ के अंदर 3100 से अधिक शय्या अस्पताल के अंदर हो जायेंगे, इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है और आपको दिख नहीं रहा है, बड़ा आश्चर्य लगता है मुझको महोदय, कोई भी जाकर देख सकता है जो सब काम हो रहे हैं । महोदय, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर वह भी निर्माणाधीन है । महोदय, पुराने अस्पतालों की बात इस सदन में हो रही थी, पुराने समय की बात हो रही थी, मैं कहना चाहता हूँ कि–

रात की घनी चादर ओढ़ी थी हमने,

लेकिन उजाले में अब हम फिर से खड़े हैं ।

मै इसलिए कहना चाहता हूँ कि सदर अस्पतालों की जो जर्जर स्थिति थी, देख कर अफसोस होता था....

अध्यक्ष : इतना बढ़िया शेर कह रहे हैं दाद तो दीजिये आपलोग ।

श्री मंगल पाण्डे : महोदय, यह हमारा सदर अस्पताल है, यह हमारा जिला अस्पताल है । कैसा जिला अस्पताल पहले होता था ? यहाँ सत्यदेव बाबू बैठे हुए हैं, पहले वाला भी सदर अस्पताल याद होगा, अभी चमचमाता हुआ जो सदर अस्पताल उद्घाटन हुआ है वह भी आप देख रहे होंगे । महोदय, यह बिहार बदला है और जो 25 सदर अस्पताल बनाने का निर्णय हमने किया, उसमें से 15 बन गए हैं और 10 बन रहे हैं । 19 अनुमंडलीय अस्पताल जिसमें से 13 बन गए, 06 निर्माणाधीन हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे राज्य के सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल होगा और उस लक्ष्य को हमलोग प्राप्त कर रहे हैं, 355 में बन चुका है और 111 प्रखंडों में निर्माणाधीन है । नया जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें 129 बन चुके हैं और 70 निर्माणाधीन हैं.....

....क्रमशः....

टर्न–27 / संगीता / 20.03.2025

(क्रमशः)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : स्वास्थ्य उपकेन्द्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की चर्चा अभी हो रही थी, 502 नए बने हैं और 272 निर्माणाधीन हैं । स्वास्थ्य उपकेन्द्र की भी चर्चा हो रही थी, 1602 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है । महोदय, प्रि–फिल्ड भी हॉस्पिटल के अंदर बनाकर बेडों की संख्या बढ़ायी जा रही है । 100 बेड के 13 फील्ड अस्पताल बने हैं, 50 बेड के 26, 42 बेड का 28 शिशु गहन चिकित्सा इकाई बना है । 32 बेड का 8 पीकू बना है और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो हैं वहां भी बेडों की संख्या बढ़ायी गयी है और 20–20 बेड के प्रि–फील्ड अस्पताल 242 स्थानों पर बनाये गए हैं ।

महोदय, ट्रॉमा सेंटर 3 जगहों पर स्वीकृति इस साल दी गई है । पटना के बिक्रम में, कैमूर के मोहनियां में और औरंगाबाद में उसकी स्वीकृति दी गई है । 22 मदर–चाइल्ड एम0सी0एच0 हॉस्पिटल बन रहा है, 22 में 18 के कार्य पूर्ण हो गए हैं। सीतामढ़ी की चर्चा यहां हो रही थी, सीतामढ़ी के एम0सी0एच0 को भी माननीय सदस्य जाकर जरूर देखें । मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा वहां बना हुआ है एम0सी0एच0। मानसिक आरोग्यशाला की चर्चा मैंने की थी महोदय, वहां...

(व्यवधान)

मानसिक आरोग्यशाला में बेड की संख्या बढ़ायी जा रही है, 321 किया जा रहा है । ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान 54 में 51 बन गए, जी0एन0एम0 23 में 17 बन गए, बी0एस0सी0 16 बन गए । मिशन उन्नयन का काम चल रहा है । नरसिंह संस्थानों का वर्गीकरण कराया जा रहा है उनका उन्नयन कराया जा रहा है । 33 जिलों में पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान बनने हैं जिसमें 26 का कार्य पूर्ण हो गया । फार्मेसी का 5 में 4 का कार्य पूर्ण हो गया, आयुष चिकित्सा को भी बेहतर किया जा रहा है । आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जा रहा है । नवाबमंजिल पटना सिटी में 50 शय्या इंटीग्रेटेड अस्पताल बना है महोदय, राजकीय टीबी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के नए भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । बेगूसराय और दरभंगा में आयुर्वेदिक कॉलेज हास्पिटल नया बन रहा है । मुजफ्फरपुर में होमियोपैथी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल बन रहा है । नियुक्तियों के संदर्भ में सदन को बताना चाहूंगा इस वर्ष 2 हजार 901 आयुष चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है । 52 औषधि निरिक्षकों की नियुक्ति हुई है । 642 सिनियर रेजीडेंट की नियुक्ति हुई है । 698 जूनियर

रेजीडेंट की नियुक्ति हुई है । स्नातकोत्तर और डिप्लोमाधारी 400 चिकित्सकों का पदस्थापना किया जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की भी बात सदन में आयी है । 1711 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में 1–2 दिन में विज्ञापन बी0पी0एस0सी0 से प्रकाशित हो जाएगा और नियुक्ति का भी काम होगा । विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 667, दंत चिकित्सक 808, फार्मासिस्ट 2473, प्राध्यापक 3326, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी 2659, एक्स–रे टेक्निशियन 1232, शल्य कक्ष सहायक 1683, ई0सी0जी0 टेक्निशियन 282, 18 हजार 868 की नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और इनकी नियुक्ति अब होने वाली है । ए0एन0एम0 के 10 हजार 709, जी0एन0एम0 के 7 हजार 903 और नरसिंह ट्यूटर 498 इनका भी बहुत शीघ्र विज्ञापन प्रकाशित होने वाला है । कुल 19 हजार 110 पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है । एन0एच0एम0 के तहत भी 13 हजार 66 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । राज्य में अस्पतालों के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं 3 लाख मरीजों को एक्स–रे की सुविधा हर माह उपलब्ध करायी जा रही है । हेल्थ एंड वेलनेस केन्द्र पर पैथोलॉजिकल जांच की सुविधाएं मिल रही हैं । डायलेसिस की सेवा 38 जिला में मुफ्त हो रहा है । सी0टी0स्कैन 34 हजार 789 मरीजों को उपलब्ध कराया गया है । महोदय, राज्य में प्रतिमाह 51 हजार लोगों को अल्ट्रासाउंड सुविधा दिया जा रहा है और दवाइयों की चर्चा हो रही थी । अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि इस वर्ष केवल राज्य के गरीब लोगों को अस्पतालों में दवाई देने के लिए 900 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है और निःशुल्क...

(व्यवधान)

सुन तो लीजिए । घोटाला से बाहर तो आप सोच ही नहीं सकते, उसी में रहे हैं आपलोग । महोदय, मैं बताना चाहता हूं यह डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल होता है ड्रग वैक्सिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखा जाता है, मॉनिटरिंग होती है उसके अनुसार यह भारत सरकार का पोर्टल है । 15 सितंबर, 2024...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इधर देखकर बोलिए मंत्री जी, उधर ध्यान मत दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, 15 सितंबर, 2024 से बिहार दवा वितरण में लगातार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है यह जानकारी तो प्राप्त कर लीजिए, गौरवान्वित होइए, आपका राज्य आज पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण करने में पिछले छः महीनों से लगातार पहला स्थान दर्ज कर रहा है । सबको गौरवान्वित होना चाहिए...

(व्यवधान)

फर्जी नहीं है यह डी0वी0डी0एम0एस0 का डाटा है, ऑथेंटिक डाटा है और सितंबर, 2024 से हम नंबर–1 पर हैं । एम्बुलेंस की सेवा भी बेहतर की गई, 1536 एम्बुलेंस आज संचालित हैं । महोदय, लगातार नवाचार के पहल हो रहे हैं । मैंने कहा कि कई काम हमने किए हैं जो देश में नहीं हुआ है । मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं । महोदय, बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री बाल थैलेसिमिया योजना शुरू किया । बोनमैरो ट्रांसप्लांट एक ट्रीटमेंट होता है महोदय और यह 15 लाख रुपया एक मरीज पर खर्च होता है । बिहार के जिन बच्चों को बोनमैरो ट्रांसप्लांट कराना है उसको सी0एम0सी0 भेलौर, क्रिस्चन मेडिकल कॉलेज भेलौर में मुफ्त में कराने की व्यवस्था बिहार की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया और 11 बच्चों को लेकर मैं सबसे पहले वहां गया था और वे बच्चे स्वस्थ होकर यहां आए हैं । महोदय, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, यह एच0पी0वी0 वैक्सिन महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर होता है देश में एक भी राज्य ने अपने बजट से एच0पी0वी0 वैक्सिनेशन फ्री में करने का निर्णय नहीं लिया लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें यह कहा कि यह मुफ्त में करिए और महिलाओं को कैंसर से बचाइए और 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त में टीका देने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोगों ने लिया है और वह टीकाकरण शुरू है । जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मुफ्त में वह टीका दिया जा रहा है और ऐसा करने वाला बिहार पूरे देश में पहला राज्य है । एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई अब हिन्दी में इस राज्य में शुरू हो गई है । शंकर आई फाउंडेशन, गुन्टूर के साथ समझौता किया, वह अस्पताल अब बिहार में बनेगा और टीकाकरण में भी मैं बताना चाहता हूं, टीकाकरण में भी बिहार अब पहले स्थान पर आ गया है यह सब लोग सुन लीजिए । 2 हजार हेल्थ एंड वेलनेंस केंद्र पर नया टीकाकरण कॉर्नर खोला गया और बहुत मॉनिटरिंग की गई इसकी, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया और मुख्यमंत्री जी का सपना था कि टीकाकरण में देश में पहले स्थान पर बिहार आए आज हम वहां पहुंच गए हैं। जो बच्चे जन्म लेते हैं अस्पतालों में उनके लिए जननी एवं बाल स्वास्थ्य हेतु जच्चा–बच्चा कीट मुफ्त में देने की व्यवस्था आदरणीय अध्यक्ष जी आप ही की उपस्थिति में पटना सिटी से हमने सदर अस्पताल से शुरू किया था और बिहार की वह योजना शुरू हुई थी । महोदय, आज पी0एम0 जय योजना और मुख्यमंत्री जय योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पूरे राज्य में 3 करोड़ 72 लाख गरीबों को 1 करोड़ 55 लाख परिवार के लोगों को वह कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है और वे गरीब के बच्चे आज 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज कराते हैं । जो बुजुर्ग हैं, 70 वर्ष से ऊपर के

हैं आयुष्मान वय–वंदना योजना उनके लिए शुरू है, 2 लाख से अधिक लोगों को यह कार्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है । कैंसर एक गंभीर बीमारी है, कैंसर के इलाज के लिए पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर में निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा है और मुझे सदन को बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मुझे उत्साहित प्रोत्साहित किया और आज एस0के0एम0सी0एच0 की चर्चा हो रही थी, कोई सदस्य कह रहे थे कि वह तो कबाड़ा हो गया है, इसका मतलब है कि वे 2005 के पहले वहां गए होंगे । आज एस0के0एम0सी0एच0 में सवा चार सौ करोड़ रुपये की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है और उसका भी उद्घाटन 1 महीने के अंदर हमलोग करने वाले हैं। वहां ऑलरेडी इलाज हो रहा है । 10 हजार से अधिक कैंसर का ऑपरेशन उस एस0के0एम0सी0एच0 परिसर में हो चुका है और दरभंगा में अभी हमने 100 बेड के कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया । जो कार्यक्रम चल रहे हैं यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम, फाइलेरिया के एस0एन0सी0यू0 का सुदृढ़ीकरण, एम0एन0सी0यू0 का । महोदय, एम0एम0आर0 जो मातृ–मृत्यु दर है वह राज्य में घटा है, पहले जहां 312 था अब 118 हो गया । महोदय, जो आई0एम0आर0 पहले 2005 में 61 होता था वह आज 27 हो गया है । पूरे देश का औसत 28 है और बिहार का 27 है मतलब देश के औसत से बढ़िया आई0एम0आर0 आज बिहार का हो गया है ।

(क्रमशः)

टर्न–28 / सुरज / 20.03.2025

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : (क्रमशः) उसी प्रकार से एन0एम0आर0 जो था वह 2008 में 32 था वह घटकर 21 हो गया है । टी0एफ0आर0 3.4 से घटकर 3 हो गया है और महोदय, आज आपको बताना चाहता हूं कि संस्थागत प्रसव आज बढ़ा है, घरेलू प्रसव घटा है और बाल टीकाकरण का काम भी बढ़ा है । बाल कुपोषण के भी सुधार में हम सबलोगों ने काम किया है ।

महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री डिजिटल मिशन के तहत बिहार ने अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में क्रांति की शुरूआत की है । अब सभी जिला अस्पतालों की निगरानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होती है । 90 प्रतिशत ओ0पी0डी0 पंजीकरण आज डिजिटल हो गया है । इस बिहार को लोग कहते थे कि यह डिजिटलाइज्ड हो सकता है क्या, बिहार आधुनिक व्यवस्था की ओर जा सकता है क्या और आज यह डिजिटलाइज्ड हुआ है । आज किस प्रकार से हम आगे

बढ़ रहे हैं । 90 परसेंट ओ0पी0डी0 आज पंजीकरण डिजिटल हो रहा है । महोदय, 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड निर्गत होते हैं हर महीने । मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना नव्या के माध्यम से चिकित्सकों द्वारा मरीजों को ऑनलाइन दवाईयां दी जा रही हैं और 28 अगस्त, 2024 को बिहार ने एक दिन में सबसे अधिक स्कैन एंड शेयर अकाउंट का राष्ट्रीय रिकार्ड भी बनाने का काम बिहार ने किया है । टेली कंस्लटेंसी आज बहुत ख्याति पा रहा है । गांवों में रहने वाले लोगों को भी बड़े अस्पताल के चिकित्सकों से सुझाव और ईलाज के उपाय सुझाये जाते हैं । आज टेली कंस्लटेशन में बिहार पूरे देश में पांचवें स्थान पर है और प्रति महीने 30 हजार से अधिक मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चिकित्सा राहत कोष की शुरूआत की गयी थी मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 215 करोड़ रुपया इस साल राज्य के वैसे गरीबों को जो असहाय थे, जिनको गंभीर बीमारी के लिये ईलाज में मदद किया जाता है, 215 करोड़ रुपया उन गरीब लोगों के ईलाज के लिये दिया गया है, मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से । मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं फिर से मुख्यमंत्री जी का बाल हृदय योजना इस राज्य में शुरू हुई और जिन बच्चों के हृदय में छेद होते हैं उन बच्चों के जान को बचाने का निर्णय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2021 में हमलोगों ने लिया और अभी तक 1871 बच्चों की जान बचाने का काम हम सबलोगों ने किया । उस कार्यक्रम में विजय बाबू भी थे जब शुरूआत हमलोगों ने इसकी की थी । महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा...

(व्यवधान)

महोदय, कुछ नई घोषणाएं मैं करने जा रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग करने वाले हैं । मैं कहना चाहूंगा :

खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा

कि अभी और उड़ान बाकी है

जमीन नहीं है मंजिल मेरी

अभी पूरा आसमान बाकी है ।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं जो आसमान बाकी है उसमें हम क्या–क्या करने वाले हैं । महोदय, ग्रामीण स्तरों पर अस्पतालों को ठीक करने की बात हो रही थी । अगले वित्तीय वर्ष में 2025–26 में राज्य में 1500 से अधिक नये अस्पतालों का निर्माण गांवों में किया जायेगा जो एच0डब्लू0सी0 होगा, एच0एस0सी0 होगा, ए0पी0एच0सी0 होगा । ऐसे 1500 से अधिक अस्पतालों का निर्माण किया जायेगा और अभी तक इसके निविदा की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली

गयी है । यह मैं बता रहा हूं, यह केवल घोषणा नहीं है इस पर काम हो रहा है यह मैं बताना चाहता हूं ।

दूसरा, राज्य के 7 जिले जो अभी प्रगति यात्रा में घोषणा हुई अररिया, औरंगाबाद, बांका, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, नवादा में नया चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया जायेगा । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आशा की चर्चा कर रहे थे सत्यदेव बाबू । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पूर्व से कार्यरत आशा, आशा फैसलिटेटर एवं शहरी आशा के अलावे 21,009 ग्रामीण आशा, 1050 आशा फैसलिटेटर एवं 5300 शहरी आशा का चयन भी इस साल किया जायेगा, यह आप सुन लीजिये । कुल 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, पटना में 100 बेड के नये शिशु रोग अस्पताल की स्थापना की जायेगी । राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 20 हजार सी0सी0टी0वी0 कैमरे का अधिष्ठापन किया जायेगा । बहुत बड़ा काम करने जा रहा है स्वास्थ्य विभाग, बिहार कैंसर केयर एवं शोध सोसायटी की स्थापना भी इस साल की जायेगी जिसकी घोषणा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया था । बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जायेगी । लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में स्पोर्ट इंजूरी यूनिट की स्थापना होगी । एम्बुलेंस की सेवा के अतिरिक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विशेष रेफरल परिवहन की व्यवस्था होगी । सरकारी मेडिकल कॉलेज को निजी जनभागीदारी के आधार पर स्थापित एवं संचालित करने हेतु नीति–निर्धारित की जायेगी । निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा । राज्य के घोषित एवं स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर का निजी जनभागीदारी के आधार पर संचालन की नीति बनेगी । लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग की भी चर्चा हुई थी । लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग को क्रियाशील किया जायेगा और अंत में हरिवंश राय बच्चन जी की चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा :

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

महोदय,

गहन सघन मनमोहक वन तरू मुझको आज बुलाते हैं

किंतु किये जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं

अभी कहां आराम बड़ा यह मूक निमंत्रण छलना है

अरे अभी तो मीलों मुझको, मीलों मुझको चलना है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये अनुदान मांग संख्या–20 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग का 20035,80,000/– (बीस हजार पैंतीस करोड़ अस्सी लाख) रुपये के अनुदान मांग की स्वीकृति हेतु सदन से स्वीकृति चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष–2211, उप मुख्य शीर्ष–00 के लिए 2872,43,82,000/– रुपये की मांग 5,00,00,000/– रूपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 20035,80,00,000/– (बीस हजार पैंतीस करोड़ अस्सी लाख) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–43 है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

मानननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको कोटि – कोटि धन्यवाद। सबसे पहले अपने विधान सभा की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। और दल के संरक्षक मा० जीतन राम मांझी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। ~~मा० अध्यक्ष महोदय~~ बिहार सरकार द्वारा दिनांक 03 मार्च को बिहार विधान सभा में पेश बजट का मैं समर्थन करती हूं.यह बजट बदलते बिहार का है.जिसमें भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि विकास की चर्चा है, राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गरीब मरीजों का इलाज होता है.मौलिक एंव मूलभूत स्वास्थय सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्या शुरू की गई है. इसके तहत डॉक्टर मरीजों को ऑनलाइन देखकर उनको दवाईयां और जांच प्रेसक्राईब किया जा रहा है.इस तकनीकी से मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रखे जा रहे हैं. महाशय, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह की तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है. इसके लिए बिहार को इनोवेशन अवार्ड मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय 2005 से पहले सरकारी अस्पताल तो थे, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों के नहीं रहने के कारण यह लूट का अड्डा बना हुआ था. कागज पर ही मरीजों का इलाज हुआ करता था.पीएचसी में व्याप्त गंदगी के कारण मरीज भी नहीं आते थे. महीने में मात्र 9 मरीज यहां पर अपना इलाज करवाने आया करते थे. वह भी यहां की व्यवस्था देखकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए चले जाया करते थे. लेकिन, अब बिहार बदल रहा है. बदलते बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आ गयी है. ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं. पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का 5462 बिस्तरों वाला दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विस्तारित किया जा रहा है. साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से दरभंगा एम्स का भी शिलान्यास किया गया है. आने वाले वर्षों में ये दोनों अस्पताल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा. बिहार में हिन्दी और अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई करने का विकल्प हो इसके लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढाई हिन्दी में भी करने की शुरुआत की गई है।

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष महोदय,

शिशु मृत्यु दर वर्ष 2005 में 61 था, जो घटकर 27 हो गया है. इसके लिए सरकार के स्तर पर अभी भी काम चल रहा है कि कैसे इसे और कम किया जाए. मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2004-06 में 312 था. इसमें भी कमी आयी है. प्रदेश के 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनकर तैयार हो गया है. इसे जन उपयोग के लिए जनता को समर्पित कर दिया गया है. इसके साथ ही 10 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है. कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े इसके लिए भी सरकार की ओर से कई प्रकार के काम किए जा रहे हैं. इस तरह से स्वास्थ्य सेवा में सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और आगे के लिए बड़ी कार्ययोजना के साथ हम बढ़ रहे हैं जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है..

अध्यक्ष महोदय, उसी तरह 2025-26 के बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है. प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरे राज्य के प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज बनाने का संकल्प लिया है. सरकार ने यह फैसला किसानों को अपनी फसलों को स्टोर करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े इसको ध्यान में रखकर किया है. इसी प्रकार से सरकार प्रदेश बाजार समितियों की स्थापना के लिए 1289 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. किसानों से एमएसपी पर जैसे धान खरीदती है. वैसे ही अब अरहर दाल और मूंग खरीदेगी. इसके साथ ही सरकार नई खाद्य प्रसंस्करण कानून लाएगी. जिससे किसानों को राहत मिलेगी.किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सतत् औद्योगिक विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा राज्य में रोजगार के नये अवसर विकसित करने के उद्देश्य से "बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2025" लाई जाएगी. बिहार में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों के लिए वृहत संभावना है, जिसको बढ़ावा देने में यह नीति मील का पत्थर साबित होग. इससे राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों आधारित इनपुट के लिए किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, इन उत्पादों के आधार पर होने वाले मूल्य संवर्द्धन की प्रक्रिया में रोजगार के कई अवसर भी सृजित होंगे।गुड़ के लिये एक "सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स' की स्थापना पूसा (समस्तीपुर) में की जायेगी।

2 [signature]

प्रदेश की एनडीए सरकार विकास के साथ साथ समाज कल्याण पर भी कार्य कर रही है. इससे पहले की सरकार जहां खास वर्ग को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को बनाया करती थी वहीं हमारी सरकार सभी को ध्यान में रखकर काम कर रही है. इसके तहत सरकार सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि से उन छात्रों को मदद कर रही है जो पैसा के अभाव में योग्यता रहते हुए भी अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते थे. हर वर्ग और धर्म के लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है. पहले की सरकार इस दिशा में काम करने के बदले आपस में लोगों को धर्म के नाम पर वर्ग के नाम पर लड़वाने का काम करती थी. जबकि हमारी सरकार सभी का विकास के लिए काम कर रही है.

इसी कड़ी में हमारी सरकार वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत उन महिलाओं को मदद कर रही है जो कि किसी प्रकार की हिंसा से प्रभावित हुई हों. इनको धर्म, जाति को ध्यान में रखे बिना एक ही छत के नीचे 05 दिनों तक रखा जा रहा है. लालू राज में जहां महिलाओं के ~~साथ रेप हुआ करता था~~ वहीं हमारी सरकार इस दिशा में 181 महिला हेल्प लाइन सेवा शुरु कर घटना को रेकने का प्रयास कर रही है और किसी प्रकार से पीड़ित महिलाओं को मदद कर रही है. प्रदेश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है.

इस योजना के तहत लिंग आधारित चयन पर रोकथाम. बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना. बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना.बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना है. जबकि लालू-राबड़ी राज में लालू परिवार में ही बहू के साथ क्या कुछ किया किसी से नहीं छिपा है. आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास की कहानी भी हर किसी को याद है. गौतम शिल्पी हत्याकांड और ऐसी अनेकों घटना जिसने बिहार को शर्मसार किया.. बेटियों का घरों से निकलना मुश्किल था.. लेकिन हमारी सरकार महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने का प्रयास कर रही है.

सरकार पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 06 माह से 06 वर्ष तक के सामान्य, कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है. कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय क्रेच स्कीम पर काम कर रही है. इसके तहत कामकाजी महिलाओं के 05 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को डे केयर की सुविधा प्रदान कर रही है. प्रदेश में छह पेंशन योजनाओं का संचालन हो रहा है. इसके तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग एवं अन्य असहाय व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत राशि दी जाती है. सरकार राष्ट्रीय परिवार योजना लाभ के तहत 18-59 वर्ष के बीच के कमाऊ सदस्य की अकस्मात मौत होने पर उसके परिजनों को एकमुश्त एत बड़ी राशि दी जाती है, इसी प्रकार से प्रदेश में मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना भी काम कर रहा है।

बिहार में बाढ़ के कारण एक बड़ा हिस्सा डूब जाया करता है. बाढ़ से बिहार के 27 जिलों के 152 प्रखंड के 1014 पंचायत आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं. यहां पर रहने वाली करीब 55.78 लाख आबादी के बीच सरकार की ओर से राहत शिविर चलाकर काम किया गया. इसी प्रकार से स्थानीय प्रकृति आपदा को लेकर सरकार ने अपनी संवेदना दिखाते हुए विभिन्न जिलों को 144.57 करोड़ आवंटित किया गया है. इसी प्रकार कोविड, अग्नि कांड, शीतलहर से प्रभावित लोगों के बीच सरकार की ओर से काम किया जा रहा है. इसके साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जा रहा है. सरकार बिहटा में एसडीआरएफ का मुख्यालय बना रही है. इससे एसडीआरएफ का काम पेशेवर तरीके से हो सकेगा. इसी प्रकार सरकार आपदा के समय किसी बड़ी घटना होने पर समन्वय बनाकर काम करने के लिए रिस्पौंस टीम का गठन कर रही है. इसे 38 स्थानों पर स्थापित करना है.इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में राज्य आपात कालीन संचालन केंद्र बनाया जा रहा है. जो कि अपने अन्तिम चरण में है।

4